₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

जनवरी 2020

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

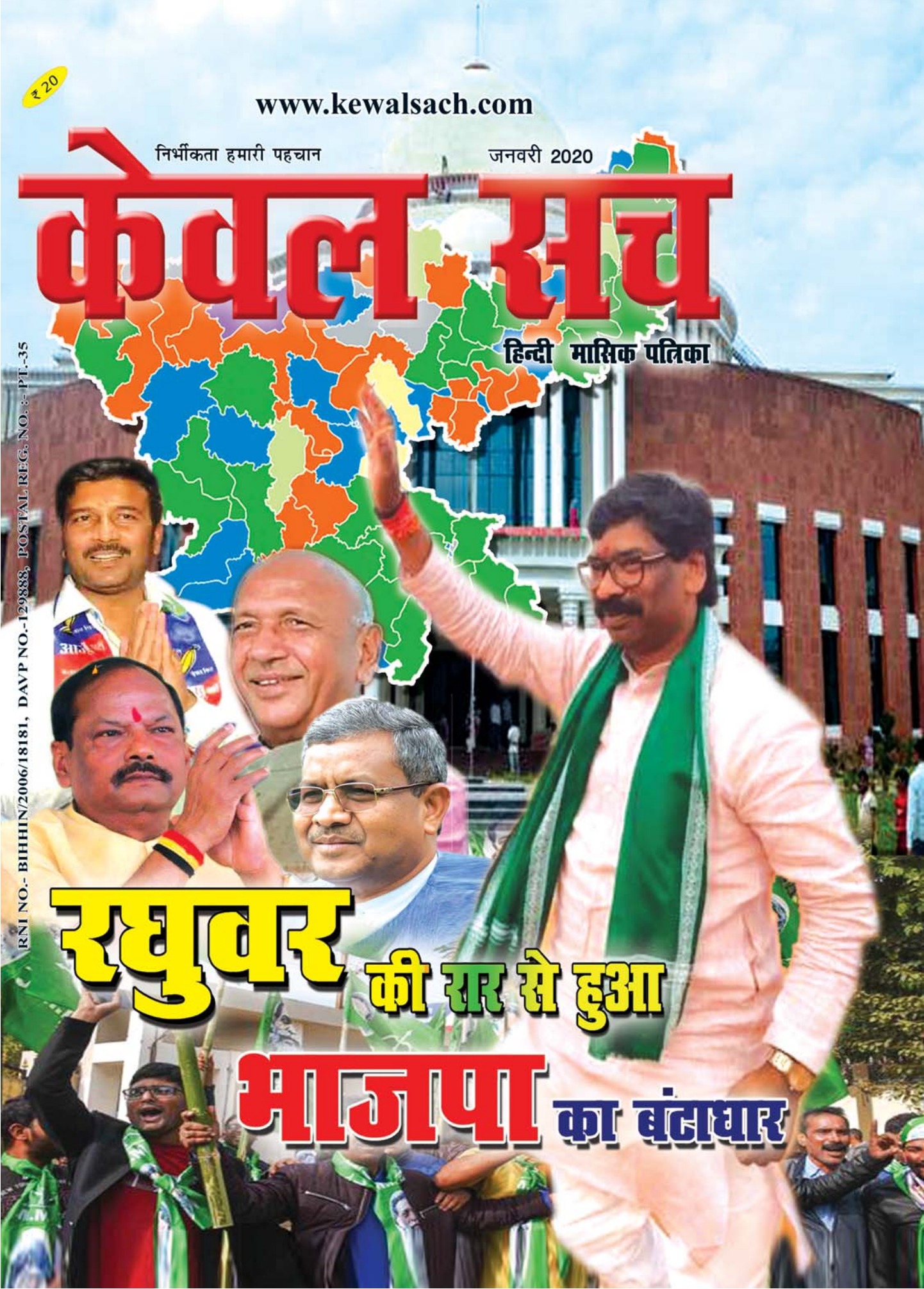

रघुवर की रार से हुआ भाजपा का बंटाधार

(A unit of Sant Shiromani Dandi Swami Sansthan)
ज्ञानदीप इंटरनेशनल विद्यालय
C.B.S.E. पैटर्न पर आधरित वर्ग प्री-नर्सरी से अष्टम् तक
लड़के एवं लड़कियों के लिए उत्तम छात्रावास की व्यवस्था
एक आदर्श संस्थान जहाँ सभी प्रतियोगी परिक्षाओं (नवोदय, सिमुरतल्ला, सैनिक स्कूल, बी.एच.यू., आर.के.मिशन, एवं अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं) की तैयारी कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है।
Hurry up!
नामांकन प्रारंभ है....
शिक्षा
समाज सेवा
वृक्षारोपन
व्यक्तिगत विकास
नैतिक विकास
कैरियर परामर्श
सड़क सुरक्षा
सांस्कृतिक कार्यक्रम
चित्रकारी एवं रंगसाजी
विद्यालय की विशेषता
शुद्ध वातावरण
CCTV के निगरानी में पढ़ाई
अग्नि सुरक्षा
शुद्ध शकाहारी रसोई
कम्प्यूटर लैब
शैक्षणिक परिभ्रमण और अन्य कार्यक्रम
पुस्तकालय
नृत्य एवं कला की प्रशिक्षण
सांस्कृतिक क्रियाकलाप
साप्ताहिक जाँच परीक्षा
अन्य विशेषता
स्पोकन इंग्लिश की व्यवस्था
प्ले वर्ग के छात्रों के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था
रेल एवं सड़क मार्गो से जुड़ा हुआ
माह के अंतिम शनिवार को अभिभावक बैठक
Director
Madhu Raj
M.D.
B. Kumar
M.Ed
Principal
Dr. R. Sinha
P.hd
चाँदनी चौक बाईपास रोड, वारिसलीगंज (नवादा) बिहार
Contact No.: 7004533516, 8102305855

हाजीपुर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर
नववर्ष 2020, मकर सक्रांति एवं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों, पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं सहित हाजीपुर की समस्त जनता एवं बिहारवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।
राघव दयाल
उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO),
सदर, हाजीपुर (बिहार)
मो.:-9431800083
अपराध और हिंसा छोड़कर मानवता के सूत्र में बंधे!

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई।
METHODIST HOSPITAL
PRATAPSAGAR BUXAR
मेथोडिस्ट हॉस्पीटल
प्रताप सागर,
बक्सर-802101 (बिहार)
-: सुविधाएँ :-
सभी सुविधाओं से लैश। मुफ्त रेलवे पास। गरीब रोगियों को विशेष छूट।
डॉ0 आर.के. सिंह

MARTIN MISSION
ELEMENTARY SCHOOL
A Step of Smart Study
FULLY CBSE CURRICULUM
Bypass Road, Warisaliganj (Nawada)-805130
Call :- 9801764747, 8521695458
Smart Class Available For Nursery to VII[th]
GAURI SHANKAR
Director

चलें गाँधी मैदान! पायें प्रतिष्ठा और सम्मान!!

12 अप्रैल 2020

ब्राहमण परिवार मिलन महाकुम्भ

भविष्य की रक्षा करनें पहुचे

समय 11 बजे AM

1001 ब्राह्मणों के द्वारा सुन्दर कांड का पाठ

पारिवारिक प्रीतिभोज

परिवार के साथ पहुचें गाँधी मैदान, पटना

आयोजक

चाणक्य विकास मोर्चा

पता - पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान सं. 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

Mob. 9431073769, 9955077308

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

कुर्सी बनाम कुर्सी

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

बूथ मैनेजमेंट और पन्ना कमिटि बनाकर भी भाजपा कई राज्यों का चुनाव हार चुकी है लेकिन सभी अपनी पार्टी के राजनीतिक औकात को साबित करने एवं विपक्षी के साथ अपने गठबंधन में शामिल दल को भी नीचा दिखाने की होड़ की वजह से बूथ स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2020 की बधाई के साथ - साथ राजनीतिक दांव-पेंच भी चलना प्रारंभ हो गया है और 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है जिसमें नीतीश कुमार का 05 साल बहुत ही विवादस्पद रहा है तथा जुबान के पक्के नीतीश कुमार की राजनीतिक दांव उजागर हो चुका है। कभी लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार भाजपा के साथ शामिल होकर लालू यादव को राजनीति के हासिये पर पहुंचा चुके हैं तो 17 साल की पुरानी भाजपा की दोस्ती को भी लात मार चुके हैं और बाद में अपना स्वाभिमान बचाने के लिए पुन: लालू यादव को पेट में दांत है की शक्ति का एहसास करा चुके हैं। 05 साल में दलित - महादलित कार्ड को भी खेल चुके नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने पानी पिला दिया था और उनको हटाने के लिए क्या राजनीति कर चुके हैं पूरा बिहार जानता है। मिट्टी में मिल जाने के बाद भी भाजपा में नहीं जायेंगे की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार को थक-हारकर मोदी के शरण में जाना ही पड़ा है और मोदी को कमजोर होता देख प्रशांत किशोर से 125 सीट पर चुनाव लड़ने की कूटनीति को हवा दे चुके हैं। अगर 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं तो महागठबंधन ने अगर यह दावा करके एकजुट हुए की चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा तो निश्चित तौर पर तीर और कमल को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। 09 प्रतिशत की आबादी वाला कोयरी समाज 2 प्रतिशत वाले कुर्मी को यह कह रहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा की राजनीति में ब्राह्म्ण और मुस्लिम साथ हो गया तो सुशील कुमार मोदी एवं नीतीश कुमार को ''ठीके तो है नीतीश कुमार'' एवं ''फिर बार-बार भाजपा सरकार'' की स्लोगन पर ग्रहण लग जायेगा। एससी/एसटी एक्ट, आरक्षण जैसे कोढ़ को लेकर सवर्ण वोटर में नाराजगी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और भाजपा को इसका जवाब मिल भी चुका है और जदयू ने होशियारी दिखायी तो वोटर से बड़ा पावर किसी के पास नहीं होता और जदयू को हराने के लिए नोटा का खेल शुरू हो गया तो शायद प्रशांत किशोर के शब्दों का जादू नहीं चलेगा परन्तु वशिष्ठ नारायण सिंह का प्रदेश अध्यक्ष होने का लाभ भी मिलेगा। सवर्ण 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेगा किसी को जिताने के लिए भी और हराने के लिए नोटा बटन दबाने के लिए भी वह राज्य स्तर पर काम कर रहा है। जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर काम कर रही है उसी स्तर पर नोटा का भी काम हो रहा है जिसका खामियाजा पिछले वर्षों के सम्पन्न हुए चुनाव एवं उसके परिणाम से देखा जा सकता है। 15 साल बनाम 15 साल की खेल को कुर्सी बनाम कुर्सी की कूटनीति का जवाब देने का मन जिस प्रकार जगदानंद सिंह ने उठा रखा है और सुशील कुमार मोदी को साईड करके भाजपा अन्य लोगों के साथ गठबंधन बनाकर 100 पर स्वयं 143 में अन्य 7-8 पार्टियां को टिकट देगी तो नीतीश कुमार एवं प्रशांत किशोर की जुगलबंदी को करारा जवाब मिलेगा क्योंकि जदयू में प्रशांत किशोर के राजनीतिक दुश्मनों की संख्या व्यापक स्तर पर है और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्री सिंह का नाम सबसे उपर है। बड़े बड़े बोल से प्रवक्ता पद प्राप्त करने वाले नेता का राजनीतिक कद कितना बड़ा है यह एमएलसी के रूप में जगह प्राप्त किया गया है का अनुमान हर कोई लगा सकता है। जिनको लड़ने का मौका मिला उसको जनता ने नकार दिया है। 15 साल में लालू का जंगलराज का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव को बुद्धिजीवियों को फ्रंट पर लाना होगा तथा मनोज झा को राज्यसभा भेजना और जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का लाभ निश्चित तौर पर 2015 के विधानसभा से बेहतर रिजल्ट देगा। इस पूरे चुनाव में सबसे कमजोर दल के रूप में भाजपा दिख रही है क्योंकि वह राजद के साथ जा नहीं सकती और जदयू के सामने वह सुशील कुमार मोदी के कारण बौना साबित हो चुकी है। यहां महाराष्ट्र वाली भी स्थिति नहीं है की अधिक सीट लाने वाला मुख्यमंत्री होगा बल्कि यहां तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा ही नहीं की राजनीति पर राजनीति होगी और 15 साल बनाम 15 साल की कुर्सी के खेल में मोदी एवं शाह का श्रम का लाभ जदयू को मिलेगा और भाजपा नीतीश कुमार की पीछलग्गू की भूमिका निभाने के अलावा कुछ खास करती नहीं दिख रही है। भले गिरीराज सिंह शेर की तरह दहाड़ते रहें पर श्री कुमार को सुशील कुमार मोदी का बर्दहस्त प्राप्त है। लालू यादव को केन्द्र में रखकर खुद विकास के मुद्दे के दरकिनार करके श्री कुमार ने लालटेन को रौशनी दी है। राजद को 22 से 81 पर पहुंचाने की कूटनीति में फंस चुके नीतीश कुमार को विपक्ष के लोगों ने कुर्सी कुमार बना दिया है, अब जनता क्या गुल..... ।

वर्ष 2020 के प्रारंभ होने से पहले ही झारखण्ड चुनाव का परिणाम आने के बाद जदयू का राष्ट्रीय औकात पता चल चुका है तो भाजपा अपने झूठे अहंकार एवं भरोसेमंद साथियों को दरकिनार का दंड भुगत चुकी है। स्वाभाविक है झारखण्ड 2000 के पहले इसी बिहार का हिस्सा था तो आबादी का 60 प्रतिशत भाग आज भी बिहार ही है और भाई के घर हुए फैसले का असर बड़े भाई पर अवश्य पड़ेगा। बिहार हो या झारखण्ड लालू यादव के इर्द - गिर्द ही राजनीति मंडराती है और बिहार में किसी भी नेता के बयान में लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं आये और राजद का लालटेन की रौशनी नहीं दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव में ब्रांडिंग के नयी तकनीक के जनक प्रशांत किशोर को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (महागठबंधन) के लिए 2015 में प्रचार का दायित्व लिया और महागठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार कभी आर. सी. पी. सिंह की सलाह को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे वहीं या उससे भी उपर का स्थान श्री कुमार ने प्रशांत किशोर को देकर कुर्सी बनाम कुर्सी (15 -15) का राजनीति प्रारंभ कर दिया है। लगातार कई राज्यों से सत्ता से बेदखल के बाद बिहार में सुशील कुमार मोदी को नेता बनाकर भाजपा नीतीश कुमार के सानिध्य में ही चुनावी वैतरणी पार करने की राजनीति कर रही है तो विपक्ष में बैठा महागठबंधन सत्ता पर काबिज होने के लिए सवर्ण कार्ड को महत्व दे रही है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.....।

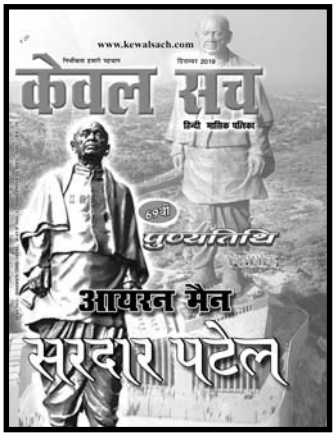

दिसम्बर 2019

हमारा ई-मेल

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769, 9955077308
kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

शिक्षा

संपादक जी,

दिसम्बर 2019 अंक में दरभंगा की खबर को शशि रंजन सिंह ने बेबाकी के साथ लिखा है। मामूली विवाद में राजेश के उपर गर्म तेल फेंक कर मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरभंगा की इस घटना के बाद की राजनीति एवं पुलिस की लापरवाही को बेबाकी के साथ लिखकर केवल सच ने पत्रकारिता को जिन्दा रखा है। इस खबर को हू-ब-हू लिखने के लिए शशि रंजन सिंह बधाई के पात्र हैं। दरभंगा की खबरों को प्राथमिकता मिलना ही चाहिए।

✦ **संतोष साह, लहेरियासराय चौक, दरभंगा**

खतरे में है कुर्सी

ब्रजेश जी,

दिसम्बर 2019 अंक में प्रकाशित संपादकीय '' खतरे में है कुर्सी'' पढ़कर मन को बहुत संतोष मिला तथा वर्त्तमान समय की सभी कूटनीति को सटीक व बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया है। बड़ी से बड़ी बात सरलता के साथ लिखकर देश की आवाम को जागृत करने का आपका प्रयास काफी सराहनीय है। इस अंक की सभी खबरें काफी मजबूत एवं पठनीय है। पत्रिका रंगीन हो जाये तो यह पत्रिका देश का नाक बनेगा कहने में कोई गुरेज नहीं है।

✦ **कन्हैया मिश्र, नाला रोड़, पटना**

आयरन मैन

मिश्रा जी,

पत्रिका प्रबंधन को दिसम्बर 2019 अंक के लिए बधाई। पत्रकार अमित कुमार की विशेष खबर ''आयरन मैन सरदार पटेल'' में पटेल की जीवन एवं राजनीति सहित उनके योगदान की छोटी-छोटी महत्वपूर्ण जानकारी को पाठकों के समक्षा रखा गया है जो पठनीय, संग्रहनीय एवं जानकारी योग्य है और प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह अंक काफी जानकारीप्रद है। कुछ अनछुए पहलुओं अमित कुमार ने अपने खबर में रखा है तथा सरकार ने सभी थानों में सरदार पटेल की तस्वीर को भी लगायी जायेगी की जानकारी काफी संतोषद है। उत्कृष्ट खबर के लिए लेखक को बधाई।

✦ **प्रदीप पटेल, सेक्टर 6, बोकारो, झारखण्ड**

उद्धव का राज

संपादक जी,

केवल सच, पत्रिका का दिसम्बर 2019 अंक में महाराष्ट्र की राजनीति एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीति एवं ''महाराष्ट्र की ताज पर उद्धव का राज'' कूटनीति पर अमित कुमार एवं कामोद कुमार कंचन ने काफी संदेशात्मक खबर पाठकों के समक्ष समीक्षात्मक खबर को रखा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद हुई राजनीतिक खेल से भी पर्दा हटाता यह खबर बहुत दमदार एवं मसालेदार लगा क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की सत्तालोलुप्तता को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ लिखा है। इस अंक का अधिकांशत: खबर पठनीय है।

✦ **योगेन्द्र शाण्डिलय, माटूंगा, मुम्बई**

लोक अदालत

ब्रजेश जी,

न्यायपालिका की साख बढ़ती जा रही है तथा अपराधी को भी न्यायालय पर भरोसा जगा है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका धीरे-धीरे आवाम के बीच काफी महत्वपूर्ण हो गयी है और लोगों का विश्वास के साथ समस्याओं का निष्पादन भी बहुत तेजी से होता जा रहा है। दिसम्बर अंक में लोक अदालत के सचिव सुनील कुमार सिंह का साक्षात्कार में महत्वपूर्ण जानकारी शिवानन्द गिरी के प्रश्नों के जवाब में श्री सिंह ने दिया है। पाठकों के लिए यह साक्षात्कार बहुत ही जानकारी के साथ कानून के विषय में समझने में सहूलियत मिलेगी।

✦ **शैलेश पाण्डेय, अस्सी घाट, बनारस**

शुभकामना

मिश्रा जी,

दिसम्बर 2019 अंक में विभिन्न क्षेत्र के प्रबुद्धगणों का शुभकामना पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि देश क विभिन्न हिस्से के लोगों के साथ बिहार के महामहिम ने भी अपना उद्‌गार व्यक्ति किया है जो पत्रिका प्रबंधन को संघर्ष करने में सहायक सिद्ध होगा। सभी मंत्री के शुभकामना के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की विस्तृत जानकारी भी पठनीय व संग्रहनीय है। केवल सच पत्रिका समाज का आइना का काम कर रहा है तथा देश के महापुरूषों के योगदान को युवा पीढ़ी तक ले जाने का सार्थक प्रयास कर रहा है। सच्ची पत्रकारिता पर खरा उतर रहा है केवल सच।

✦ **दिलीप सिंह, टावर चौक, दरभंगा**

अन्दर के पन्नों में

सरदार पटेल की मनायी गयी पुण्यतिथि....13

दरभंगा का खेवनहार कौन?.....70

निर्भया को मिला इंसाफ.....94

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 14 अंक:- 165 माह:- जनवरी 2020, मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

गोपाल मिश्र **0612/2362784**

संपादक

ब्रजेश मिश्र

09431073769

09955077308 08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

सच्चिदानन्द मिश्र 09431878843

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 09430888060, 08873004350

अमोद कुमार 09431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 09308815605, 09122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

रीता सिंह 7004100454, 9308729879

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उपसंपादक

शिवचन्द्र झा 7488742471, 8521329144

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 9576438501

अजित कुमार त्रिपाठी 9430826676, 9294942868

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

amit.kewalsach@gmail.com

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

प्रदीप कुमार सिन्हा 9472589853, 6204674225

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

रामपाल प्रसाद वर्मा 9939086809, 7079501106

संजीव रंजन तिवारी 9430915909

कृष्ण कुमार चंचल 9430520291, 7870421678

संदीप स्नेह 9971679857, 9667977987

रविन्द्र कुमार सिंह 7004238997, 9576084702

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 09608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

ललन कुमार 9430243587, 9334813587

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 09308454485

रणविजय सिंह यादव 09334612716, 09801111138

रवि कुमार पाण्डेय 09507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

प्रिया सिंह मौर्य 7764062233

गगन कुमार मिश्र 8210810032, 9835585560

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 09905244479

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 08002647553, 09060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 09905203164

झारखण्ड सहायक संपादक

ब्रजेश मिश्रा 07654122344, 07979769647

अभिजीत दीप 09835916650, 09430192929

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो चीफ

ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	09431732481	
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	09546624444	
खूँटी	:-		
जमशेदपुर	:-		
हजारीबाग	:- शैलेश मेहता	09973027485	
जामताड़ा	:-		
दुमका	:-		
देवघर	:-		
धनबाद	:-		
बोकारो	:- विनय कुमार सिंह	07903166519	
रामगढ़	:- दिव्य प्रकाश सिंह	08227979999	
चाईबासा	:-		
कोडरमा	:-		
गिरीडीह	:-		
चतरा	:- धीरज ठाकुर	09430353639	
लातेहार	:- रविकांत पासवान	09801637947	
गोड्डा	:-		
गुमला	:-		
पलामू	:-		
गढ़वा	:-		
पाकुड़	:-		
सरायकेला	:-		
सिमडेगा	:-		
लोहरदगा	:-		

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:- श्रीधर पाण्डेय	09470709185	
(म०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
भोजपुर	:-		
बक्सर	:- बिन्ध्याचल सिंह	8935909034	
कैमूर	:-		
रोहतास	:- अशोक कुमार सिंह	7739706506	
	:-		
गया (श०)	:-		
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:- मयंक कुमार	9852569398	
जहानाबाद	:- नवीन कुमार रौशन	9934039939	
अरवल	:- संतोष कुमार मिश्रा	9934248543	
नालन्दा	:- ललन प्रसाद	6299793069	
	:-		
नवादा	:- अमित कुमार	9934706928	
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:- रवि शंकर कुमार	6204758273	
बेगूसराय	:- निलेश कुमार	9113384406	
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:- अजय कुमार	09430030594	
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:- सनोज कुमार	9955672241	
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:- अविनाश कुमार	9470659050	
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-		
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-		
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:- सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141	
	:-		
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:- अब्दुल कय्यूम	9934276870	
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-		
नवगछिया	:-		
बांका	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०-09868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०-09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
रिया प्लाजा, फ्लैट नं0-303,
कोकर चौक, राँची-834001
मो०- 9955077308, 9431073769

मध्य प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- नूर आलम
हाउस नं.-74, अटल आवास,
बेलभाँटा, अभनपुर, रायपुर
(छत्तीसगढ़)
मो०-09835845781,
08602674503

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश कुमार मिश्रा 07992327070
09631400205

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

उत्तर प्रदेश हेड
गदाधर नाथ मिश्रा 09452127278

महाराष्ट्र हेड
कमोद कुमार कंचन 07783822144

महाराष्ट्र कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- कमोद कुमार कंचन
Swapnapoorti Society,
Phase- 1, Sector - 26,
Nigdi, Pune- 411044
Mob:- 7492868363

उत्तर प्रदेश कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उत्तराखण्ड कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

गुजरात कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

राजस्थान कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

हरियाणा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

कर्नाटक कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

उड़ीसा कार्यालय

बहुत जल्द कार्यालय का शुभारंभ

आसाम कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- शम्भू नाथ मिश्र
रेलवे गेट नं.- 02 राजेन्द्र नगर
वार्ड नं.- 08, लंका, पोस्ट- लंका
जिला-नगावँ, दिसपुर (आसाम)
मो०- 08135023285, 07631376135

एक नजर इधर भी

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308
- e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए-17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।
- A/C No. :- 0600050004768
  BANK :- United Bank Of India
  IFSC Code :- UTBI0KKB463
  PAN No. :- AAJFK0065A

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

देवब्रत कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी
53 ठाकुरगंज विधानसभा
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
8986196502/9304877184
devbartkumar15@gmail.com

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009
09437029875

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.)
N.B.C.C
08877663300

पत्रिका संरक्षक

श्री जय कुमार सिंह	:- मंत्री, आई. टी. विभाग, बिहार सरकार	9431821104
डॉ० उमाकान्त पाठक	:- जेनरल फिजिशियन, MBBS	9835291966
भगवान सिंह कुशवाहा	:- पूर्व मंत्री, बिहार सरकार	9431821525
श्री ललन पासवान	:- विधायक, चेनारी, रालोसपा	9431483540
डॉ० ए० के० सिंह	:- शिशु रोग विशेषज्ञ MBBS	9431258927
श्रीमती अरूणा सिंह	:- सदस्य, जिला पार्षद, बिक्रमगंज	9931610437

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	धर्मेन्द्र सिंह	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

www.kewalsach.com

विशेष प्रतिनिधि

राजेश कुमार मिश्र	8757834700, 7004296529
लक्ष्मी नारायण सिंह	9204090774
मणिभूषण तिवारी	9693498852
कामोद कुमार कंचन	8971844318, 9110187832
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
राजीव रंजन	9431657626
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
अनु कुमारी	9471715038, 7542026482
विवेक कुमार मिश्र	7461803110,
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
प्रणव कुमार कश्यप	8809903185
सलाम साबरी	9835094832
रंजीत कुमार सिन्हा	9931783240, 7033394824
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
अजय कुमार	8409103023, 6203723995
राजेश कुमार	7632936806, 7563816708
अवधेश कुमार शर्मा	9304827131, 8789324045
शिव कुमार ओझा	9162841133, 9162746866
राजमंति पाण्डेय	6201672831, 9155794800
वंदना सिंह	7903669215,

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000,	9431096964
मुकेश कुमार	9835054762,	9304377779
जय प्रसाद	9386899670,	
कृष्णा प्रसाद	9608084774,	9835829947

ठाकुरगंज में

गरजेगा युवा शेर

आज देश हो या प्रदेश, अच्छा करे या बुरा उसको धर्म में बांटकर हिसाब किया जाता है और जब बात राजनीति की हो या फिर विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारों का चेहरा वोटरों के सामने आने लगता है। बिहार का सिमांचल की राजनीति बहुत ही चिंतनीय एवं धर्म पर आकर फिट बैठता है। झारखण्ड चुनाव के नतीजे के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का शंखनाद हो चुका है और बूढ़ा-जवान सभी अपने-अपने क्षेत्र से भाग्य आजमाना चाहते हैं। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से युवाओं के बीच खास महत्व रखने वाले देवव्रत गणेश भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनका नाम आते ही कई राजनेताओं की नींद हराम है की जिला परिषद् से सीधा विधानसभा का यात्रा देवव्रत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इनके समाज के साथ-साथ मुस्लिम वर्ग में देवव्रत का अपना खास पकड़ है और वह युवाओं को रोजगार के साथ पलायन जैसा समस्या पर विराम लगायेंगे की पड़ताल करती सुमित राज यादव की रिपोर्ट:-

बिहार राज्य के सीमांचल में किशनगंज लोकसभा सीट से कई दलों के बड़े नेता चुनाव लड़े और जीत चुके हैं। यहां बाहरी बनाम स्थानीय नेताओं का मुद्दा हमेशा गर्माया रहता है। सैय्यद शहाबुद्दीन, एम जे अकबर, तस्लीमुद्दीन, सैय्यद शाहनवाज हुसैन जैसे कद्दावर नेता यहां से जीतकर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में अबतक कोई युवा वर्ग ने न तो कमान संभाली हैं और न ही कोई चेहरे सामने उभरते दिख रहे हैं। किशनगंज बिहार में राजधानी पटना से करीब 380 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। जिसके बॉर्डर में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, पड़ोसी देश नेपाल और बंग्लादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। 1990 में ये जिला बना। यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल का बागडोगरा है। जो किशनगंज से 90 कि०मी० और ठाकुरगंज से महज 35 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां से पानीघाटा, गंगटोक, कलिंगपोंग, दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है। महाभारत कालीन युग से जाने जाने वाली ठाकुरगंज में कोलकाता के रविंद्र नाथ टैगोर की वंशज के नाम से बसा हुवा बाबा भोले की नगरी हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी यहां से बसें उपलब्ध हैं। यह लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल है। लेकिन, हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ गंगा यमुना तहजीब की दुहाई देते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करते दिखाई देते है। बीते वर्ष किशनगंज से कांग्रेस सांसद मौलाना असरार-उल-हक कासमी का निधन 7 दिसंबर 2018 को हो गया था। 2019 में आम चुनाव नजदीक होने

हर घर में देंगे रोजगार – देवव्रत

देश की राजनीति में बिहार की राजनीति का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार लोकतंत्र की राजनीति में निश्चित तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका के कारण सरकार बदलने और बंनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती आ रही है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र से महज 28 वर्षीय युवाओ के युवा देवव्रत गणेश ने आगामी विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे है। जिस उम्र में आज युवा अपनी कैरियर बनाने और भविष्य की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। इस उम्र में ही दो बार जिला परिषद के चुनाव का अनुभव प्राप्त करने के बाद अब विधानसभा चुनाव में कदम बढ़ाने के संकेत दे रहे है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह 'जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है', लेकिन अलग-अलग देशकाल और परिस्थितियों में अलग-अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा भी कुछ जटिल हो गयी है। केवल सच पत्रिका ब्यूरो चीफ **सुमित राज यादव** से पत्रिका संरक्षक **देवव्रत गणेश** के साक्षात्कार' करने के दौरान खास बातचीत के प्रमुख अंश:-

आप राजनीति के क्षेत्र में बीते 15 वर्षो से सक्रिय भूमिका में है। इसके बाद विधानसभा का चुनाव में अपना भविष्य देख रहें हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं इसकी कोई खास वजह?

सबसे पहले पत्रिका परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए साक्षात्कार के लिए चयन किया। मेरा मन राजनीति से इसलिए जुड़ता चला गया कि जब आज 50 वर्ष तक आयु वाले नेताओं को युवा प्रकोष्ठ से विभिन्न पद आसानी से प्राप्त हो जाता हैं। तो युवाओं को युवा का पद क्यों नहीं मिल सकता है? ऐसा तब होता हैं जब युवाओं के चेहरे सामने नजर नहीं आते हैं। आज बिहार सहित पूरे देश मे युवाओं के चेहरे कम हैं। इसका यही मूल कारण है कि युवाओं का हक पुराने नेताओं को निभाना पड़ता है। अगर युवाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित होंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें भी उनका हक अवश्य मिलेगा। जब 50 वर्ष तक के नेताओ को पार्टी में युवा प्रकोष्ठ के पद प्राप्त हो सकते हैं। तो हम 28 वर्ष के ही है तो हम तो युवाओं के भी युवा हुए न! इसलिए युवाओं के भविष्य को लेकर मैं राजनीति में नई ऊर्जा के साथ ठाकुरगंज विधानसभा को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की योजनाएं लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं के साथ, युवाओं के लिए राजनीति मर अपने कदम बढ़ाने जा रहा हूँ।

क्या आप युवाओं के लिए कोई खास योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं?

देखिए, नेताओ के लिए क्षेत्र की जनता भले वह किसी भी उम्र के पायदान पर खड़ी हो। उनके लिए सभी बराबर होता हैं। बुजुर्गों के लिए भी वही जिम्मेदारी से आगे बढ़ना पड़ता है तो युवाओं के लिए भी तो महिलाओं के लिए भी तो बच्चों के लिए भी। लेकिन, खासकर आज जो एक बड़ी मतदाताओं की आबादी युवाओं की टोली हैं। वो कहीं न कहीं अपने कैरियर बनाने के लिए देशों और विदेशों में

कैरियर तलाश रहे हैं। अपनी घरो की जरूरत को पूरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, नेपाल, बंगाल आदि जगहों के चक्कर घर छोड़कर लगाने को मजबूर हो रहें हैं। उनके जिम्मेदार कौन हैं? आज अगर उन्हें अपने ही विधानसभा में रोजगार के अवसर प्राप्त हो गए होते तो उन्हें भी अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। शिक्षा के बेहतरीन मंच हमारे लोकसभा क्षेत्र और बिहार में ही मिल जाते तो शायद उन्हें किसी अन्य राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जो कल के भविष्य हैं उन्हें ही जब अपने घरों के आसपास और राज्यों में रहकर जानने का अवसर नही प्राप्त होगा तो कैसे युवाओं को अपने गाँव, समाज, राज्य, देश के लिए कुछ बेहतर अनुभव के साथ नई योजनाओं पर कार्य करने के अवसर मिलेंगे। इसलिए, खासकर युवा वर्ग को लेकर बढ़ने और क्षेत्रों में युवाओं के योगदान को मजबूत करने की सोच लेकर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कदम उठाया है।

आप अपने प्रखंड और जिला के राजनीति से आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में बढ़ने का मन बनाया हैं। आपको क्या लगता हैं? किस प्रकार आप राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं?

बिहार में जनतंत्र की जड़ें काफी गहरी तथा यहां जनतांत्रिक सिद्धांतों, परम्पराओं और मर्यादाओं का भरपूर सम्मान है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं को अपनी आत्मविश्वास से राजनीति में कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि दृढ़ संकल्प के साथ एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती हैं और जनता का भरोसा और यकीन पर खड़ा भी उतरना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि युवाओ के साथ सभी समुदायों के लोगों का वोट जाति, समुदाय और दल भावना से ऊपर उठकर साथ खड़े होकर साथ निभाएंगे। हर घर को रोजगार मुहैया कराकर पलायन जैसी समस्या को भी रोकेंगे।

के कारण किशनगंज में उपचुनाव नहीं कराए गए।

वही दिसंबर 2018 में किशनगंज के सांसद मौलाना असरार-उल-हक कासमी के निधन से यहां का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया. वर्ष 2014 के चुनावों में भाजपा की लहर के बीच भी मौलाना असरारुल हक ने किशनगंज लोकसभा सीट को रिकॉर्ड मतों से जीता था। सभी धर्म और समुदाय के लोगों में उनकी पकड़ थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासमी पहली बार 2009 में मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने यहां अपनी जीत बरकरार रखी थी। 1957 और 1962 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर जीते। 1967 के चुनाव में इस सीट से विजयी रहे पीएसपी के एलएल कपूर. उन्होंने मोहम्मद ताहिर को शिकस्त दी. 1971 में इस सीट से कांग्रेस के जमीलुर रहमान जीते. 1977 में बीएलडी के हलीमुद्दीन अहमद को किशनगंज की

जनता ने चुनकर दिल्ली भेजा. इसके बाद 1980 और 1984 के चुनावों में यहां की जनता का जनादेश कांग्रेस के उम्मीदवार जमीलुर रहमान के पक्ष में आया. 1985 में यहां उपचुनाव हुए जिसमें जेएनपी के सैय्यद शहाबुद्दीन जीते. 1989 में किशनगंज से कांग्रेस ने पत्रकार एम. जे. अकबर को उतारा और वे जीतकर लोकसभा पहुंचे. 1991 में इस सीट से फिर सैय्यद शहाबुद्दीन जीत गए. 1996 में किशनगंज से जनता दल के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जीते. 1998 में तस्लीमुद्दीन यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर सदन पहुंचे। 1999 का चुनाव किशनगंज सीट पर काफी रोचक रहा। बीजेपी के युवा नेता के रूप में सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने यहां के दिग्गज तस्लीमुद्दीन को हराकर लोकसभा की सदस्यता हासिल करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन, 2004 में तस्लीमुद्दीन ने शाहनवाज हुसैन को हराकर फिर अपना परचम लहराया। इसके बाद के दो चुनाव 2009 और 2014 में इस सीट से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना असरार-उल-हक कासमी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर दिल्ली पहुंचे।

किशनगंज लोकसभा सीट पर वोटरों की संख्या 1186369 हैं। इसमें से महिला वोटर 561,940 हैं। जबकि इस सीट पर पुरुष वोटरों की संख्या 624,429 है। किशनगंज लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी। 2015 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 कांग्रेस, 2 जेडीयू और एक सीट आरजेडी ने जीती. किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के तीन विधायक हैं। किशनगंज विधानसभा से डॉ. जावेद आजाद, बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम और अमौर विधानसभा से अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के विधायक हैं। 16वीं लोकसभा के लिए 2014 में हुए चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार असरार-उल-हक कासमी को 493461 वोट मिले।. उन्होंने बीजेपी के डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को हराया। दिलीप जायसवाल को 298849 वोट मिले। वहीं, जेडीयू के अख्तारुल इमान को 55,822 वोट मिले. इस सीट से आम आदमी पार्टी ने अलीमुद्दीन अंसारी को उतारा था. उन्हें 15,010 वोट मिले थे। इसके बाद एआईएमआईएम के नेता हैदराबाद से किशनगंज पहुँचकर असरूद्दीन ओवैसी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को लोकसभा चुनाव में उतारा। लेकिन, डॉ. मो. जावेद ने कोंग्रेस को एकलौती सीट से जीत हासिल कर ओवैसी को हैदराबाद वापस भेजा। लेकिन, किशनगंज के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की देश मे सरकार रहने के बाद भी स्वीटी सिंह को एआईएमआईएम के उम्मीदवार कमरुल होदा ने करारी शिकस्त दी और ओवैसी के किशनगंज आकर राजनीति करने के द्वारा खोल दिए। कोंग्रेस से ही पिता और पुत्र आजाद परिवार से सांसद बने हैं। सांसद रहते हुए भी पुत्र डॉ. मो. जावेद अपनी माँ को उपचुनाव में जीत नहीं दिला पाए। वर्तमान में किशनगंज लोकसभा में दो जदयू विधायक के रूप में ठाकुरगंज से नौशाद आलम और कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद आलम तो कोंग्रेस से बेसी से जलील मस्तान और बहादुरगंज से तौसीफ आलम हैं। तो एआईएमआईएम से कमरुल होदा हैं। बहादुरगंज विधायक के बड़ी भाभी को जिला परिषद में अध्यक्षा के पद पर जीत भी हासिल हुई। लेकिन, करीब तीन वर्षों के अंतराल में अविश्वास प्रस्ताव लगाकर जिला परिषद के सदस्यों ने फरहत फातमा को दुबारा अपना अध्यक्षा के रूप में उनके पक्ष में मतदान किया। जहां किशनगंज में एमएलसी के पद पर डॉ. दिलीप कुमार जयसवाल एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक हैं। तो जदयू के विधायक नौशाद आलम बिहार सरकार में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। जिला परिषद् धनोमाता के काम का मुआवजा भी देवव्रत गणेश को मिलेगा तथा पहली बार इनकी जाति गंगई समाज का विधायक होगा की चर्चा को लेकर सिमांचल में राजनीतिक गलियारे में गणेश का बाजार गर्म है

मेरा काम बोलेगा- गणेश

जिला परिषद का चुनाव दो बार लड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में कदम रखने जा रहे देवव्रत गणेश से बातचीत करने पर बताया कि सीमांचल की बदहाली को लेकर राज्य सरकर अब तक राजनीति ही करती रही। पिछले 10 वर्षो में सीमांचल का विकास लगभग अवरुद्ध हो चुका है। इसके लिए विधान सभा में कई बार आवाज भी हमारे नेताओं ने उठाया हैं। लेकिन, सुबे के मुख्यमंत्री सिर्फ यहां केवल वोट बैंक राजनीति करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सीमांचल का क्षेत्र बिहार के अन्य जिले की तुलना में काफी पिछड़ा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनो ही समान रुप से जिम्मेवार है। सीमांचल क्षेत्र अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला होने के बावजूद सरकारी उपेक्षाओं का शिकार बना हुआ है। इस बावत सीमांचल में रहने वाले एक करोड़ आठ लाख लोग विकास की मुख्य धारा से नही जुड़ सके। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार सरकार के विकास का बजट 46 हजार करोड़ रुपये था। सीमांचल के चार जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में आबादी के हिसाब से यहां चार हजार आठ सौ करोड़ रुपये खर्च होने थे। कारण यह कि इन चार जिले में बिहार की आबादी का कुल 10 फीसद लोग रहते हैं। लेकिन, केवल 200 करोड़ रुपये ही खर्च हो पायें। वहीं, वर्ष 2015-16 में बिहार का बजट 57 हजार करोड़ का है। इस बार यहां पांच हजार आठ सौ करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए। लेकिन, अब तक पंद्रह सौ करोड़ रुपये भी खर्च नही हो पायी है। सीमांचल के किशनगंज जिला में राज्य सरकार मेडिकल और पोलीटेक्नीक कालेज खोलने में असमर्थ रही है। यहां अस्पताल की संख्या केवल 154 है। जबकि 29 लाख की आबदी वाले नालंदा जिला में अस्पताल की संख्या 443 है। सीमांचल के विकास के लिए अब युवाओं को आगे आने का समय आ गया है। जब युवाओं के लिए भी नए विकल्प तलाशने की जरुरत दिख रही है। कभी मानव श्रृंखला तो कभी सुशासन बाबू का बिहार दौरा के नाम पर सरकारी खजाने से राशि के बहाव से बिहार के युवाओं को हक मिले नहीं मिल पा रहीं हैं। दर्जनों परीक्षा होते ही पेपर लीक हो जाने के मामले को लेकर रदद् कर दी जाती हैं। जिसका भुक्तभोगी सीमांचल के युवा भी है। युवाओं को भी बड़ी संख्या में सरकार की नाकामी का दंश झेलना पड़ता है।

अबतक किशनगंज के रह चुके है सांसद:-

वर्तमान में किशनगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में छह विधानसभा (विधान सभा) क्षेत्र शामिल हैं।जिसमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी शामिल हैं। जिसमें अबतक कई सांसदों ने बाजी मारते हुए किशनगंज लोकसभा सीट से सदन तक का सफर तय चुके हैं।

1957: एम.डी. ताहिर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1962: एम.डी. ताहिर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1967: लखन लाल कपूर, पी एस पी
1971: जमीलुर्रहमान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
1977: हलीमुद्दीन अहमद, भारतीय लोक दल
1980: जमीलुर्रहमान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1985: सैयद शहाबुद्दीन, जनता पार्टी
1989: एम जे अकबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1991: सैयद शहाबुद्दीन, जनता दल
1996: मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जनता दल
1998: मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, राष्ट्रीय जनता दल
1999: सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी
2004: मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, राष्ट्रीय जनता दल
2009: मोहम्मद असरारुल हक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2014: मोहम्मद असरारुल हक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2019: मोहम्मद जावेद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनायी गयी

69वीं पुण्यतिथि

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट प्रतिवर्ष महापुरूषों के उपर विशेषांक का प्रकाशन कर युवाओं के लिए उपयोगी सामग्री देने का काम केवल सच, पत्रिका पिछले 14 वर्षों से लगातार करती आ रही है। देश के लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 69वीं पुण्यतिथि के पुनित अवसर पर दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के मावलंकर भवन में ''लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल सच सम्मान- 2019'' से विभिन्न सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया तथा ''देश की एकता में राजनेताओं की भूमिका'' पर विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान ने अपनी बातों से देश की जनता को अवगत कराया की किस प्रकार सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली और 565 रियासत को एकसूत्र में बांधकर राष्ट्र की अखडता को बरकरार रखा। आज सरदार पटेल सिर्फ कांग्रेस के नेता के रूप में ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के आदर्श हैं और उनकी राजनीतिक सोच को हर दल अपना करके राष्ट्र को नई दिशा देना चाहता है। सरदार पटेल के पुण्यतिथि पर आयोजित आयोजन पर सभी वक्ताओं ने संगठन को साधुवाद दिया। प्रस्तुत है प्रदीप सिन्हा/त्रिलोकी नाथ प्रसाद की रिपोर्ट :-

नई दिल्ली। भारत माता की गोद में जन्में महापुरूषों के इतिहास एवं बलिदान को 'श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट' देश के युवाओं के बीच जन्मोत्सव एवं पुण्यतिथि के रूप में कार्यक्रम करके राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत करती है। इसी कड़ी में 15 दिसम्बर 2019 (रविवार) को द्वापरयुग के पांडवों की पावन नगरी एवं समस्त देशवासियों की पवित्र भूमि देश की राजधानी नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया मावलंकर सभागार में श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले राष्ट्र को एकता के सूत्र में 565 रियासतों को एकत्रित करने वाले सर्व समाज के प्रणेता हदृय सम्राट लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 69वीं पुण्यतिथि

महिला क्रिकेटर मंजू गोदरा एवं भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा को सम्मानित करते चन्द्र प्रकाश सिंह

शिक्षाविद् सुधीर कुमार को सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार

शिक्षाविद् सुधीर कुमार को सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार

कार्यक्रम में सम्म

को बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया तथा एक चिंतन राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 69वीं पुण्यतिथि पर एक विशेषांक का भी प्रकाशन किया गया जिसको विमोचन प्रबुद्धगणों ने किया। विभिन्न सेवा क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल सच सम्मान- 2019 से सम्मानित भी किया गया। सांस्कृति कार्यक्रम एवं प्रतिभोज का भी आयोजन सम्पन्न हुआ जिसमें दिल्ली प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्य से भी आये लोगों ने लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन दर्शन एवं राष्ट्रीय सेमिनार देश के विकास में राजनीति की भूमिका को समझने एवं आत्मसात करने का संकल्प लिया।

बताते चले कि उक्त कार्यक्रम में ब्रजेश मिश्र उरवार (संपादक सह संस्थापक, केवल सच), चन्द्रप्रकाश सिंह (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,

समाजसेवी रविन्द्र कुमार सिंह एवं पत्रकार कुणाल अमृत राज को सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार, चन्द्रप्रकाश सिंह

ानित पत्रकारगण

सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार

इंटक), ई० संजय विनायक जोशी (पूर्व संगठन महासचिव, भाजपा), सज्जन सुरेका (समाजसेवी), विजय कुमार (डीआईजी, सीआरपीएफ), अभय सिन्हा (समाजसेवी), डॉ० रमा (प्राचार्य, हंसराज कॉलेज, दिल्ली), शंभू शिखर (सुप्रसिद्ध हास्यकवि)सहित विभिन्न क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति रही।

राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विचारक के रूप में ख्याति रखने वाले भारतीय जनता पार्टी पूर्व महासचिव (संगठन) ई० संजय विनायक जोशी ने कहा कि ब्रजेश मिश्र लगातार देश के विभिन्न राज्यों में श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए समर्पित उन महापुरूषों को जीवंत रखने के साथ युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज सबकुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है लेकिन श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

व्यवसायी विपुल गौतम को सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार

सामाजिक दृष्टिकोण से संसाधनों के अभाव के बाद भी अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है। पूरी दुनिया लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र को एकसूत्र में बांधने की अद्म्य क्षमता को सलाम करता है। एक मजबूत एवं दिर्घायु सोच का ही यह नतीजा है 565 रियासत आज भारत का मजबूत हिस्सा सरदार पटेल जी के मेहनत का नतीजा है। घर कैसे मजूबत बनेगा, घर कैसे सुरक्षित रहेगा, हर घर में चूल्हा जले, हर घर को रोटी नसीब हो, हर हाथ को काम मिले तब जाकर एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना संभव है और वही कर दिखाया था सरदार पटेल ने। राजनीतिक बाधाओं को दूर करके राष्ट्र की प्राथमिकता के गंभीरता को समझकर उन्होंने सफल प्रयास किये जिसकी वजह से सरदार पटेल को सभी राजनीतिक पार्टियां अपना आर्दश मानती है। इनके विचारों को आगे बढ़ाने का श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट का यह प्रयास भी याद किया जायेगा। ऐसे आयोजनों के लिए मैं संस्था की पूरी टीम को बधाई देता हूं।

राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त हास्य कवि शंभु शिखर ने भी सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद कविता पाठ करके श्रोताओं का मन मोह लिया तथा अपने कविता के माध्यम से राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को लेकर लोगों को जागरूक किया तथा ''धरती पुत्र बिहारी हैं....'' कविता से बिहार की गौरवगाथा को भी लोगों को बताया। हंसराज कॉलेज नई दिल्ली की प्राचार्य डॉ० रमा ने भी देश की एकता में राजनेताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया की गुलामी के जंजीर से मुक्त होने के बाद राजनेताओं ने भी देश का विकास किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की

लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर प्रकाशित विशेषांक

भूमिका को पूरी दुनियां सदैव याद करेगी। 565 रियासत को एकसूत्र में एकत्रित करने वाले पटेल आज इन्हीं कारणों की वजह से सभी राजनीतिक दलों में पूजे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एवं विभिन्न प्रकार के आरोप से घिरे रहने के बाद भी लोकतंत्र में राजनीति का अपना महत्व एवं प्रभाव है और ट्रस्ट ने ऐसे महापुरूष के पुन्यतिथि पर ऐसा साहसिक कार्यक्रम करके समाज को दिशा देने का काम किया है।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट पिछले 14 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में महापुरूषों पर कार्यक्रम करके युवा पीढ़ी को सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही है। आज पटेल जी पर राजनीति हो रही है और कांग्रेस के उन नेताओं को भाजपा आज आर्दश मान रही है और उनके कार्यकर्त्ता इन्हीं महापुरूषों के विषय में गलत बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस की नीतियां गलत हैं लेकिन वहां के राजनेता आज अन्य दलों के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पहली दफा कोई गैर राजनीतिक संस्था पुण्यतिथि का कार्यक्रम कर रहा है ऐसा मुझे लगता है और यह एक अच्छी पहल है क्योंकि किसी भी बिरादरी के महापुरूषों को जाति में बांधना उचित नहीं है और यह पहल ट्रस्ट ने प्रारंभ करके पटेल जी के विचारों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। देश के विकास में सरदार पटेल का योगदान हर कालखंड में सराहनीय रहा है क्योंकि सनातन धर्म एवं मानवता को एकसूत्र में पिरोने वाले पटेल जी की दूरदर्शी सोच का लोहा पूरा विश्व मानता है। आज सभी विकसित राज्यों में पटेल जी का योगदान सरकार से कम नहीं है

''आयरन मैन सरदार पटेल'' का लोकार्पण करते प्रबुद्धगण

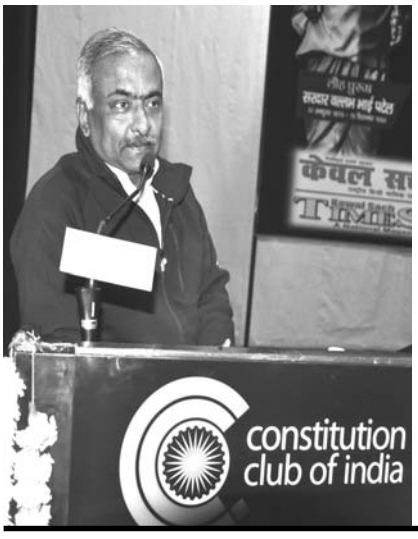

ई० संजय विनायक जोशी

चन्द्र प्रकाश सिंह

ब्रजेश मिश्र

और यही कारण है झारखण्ड, दिल्ली, मुम्बई, राजस्थान, गुजरात सहित सभी विकसित प्रदेश एकत्रित काबिलियत की वजह से दिन दुगनी रात चौगनी विकास किया है। अपनी कमाई के हिस्से में से धर्म एवं समाज पर खर्च करना वास्तव में एक मजबूत सामाजिक शक्ति का एहसास कराता है। सरदार पटेल युगों-युगों तक याद किये जायेंगे। आचार्य चाणक्य के बाद राष्ट्र सबसे पहले बाद में कुछ और सोचने वाले सरदार पटेल ही हुए और स्वस्थ्य भारत एवं एकत्रित भारत बनाने में पटेल जी को सभी राजनीतिक दल याद करते रहेंगे। सामाजिक सारोकार से जुड़े अभय सिन्हा एवं उज्जैन से आये आचार्य लक्ष्मण पाण्डे ने भी राजनीति के गिरते आयाम पर प्रकाश डाला तथा राजनेताओं की भूमिका पर अपना योजस्वी विचार रखा, वहीं जदयू के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के लिए श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट को जहां बधाई दिया वहीं वह देश की आवाम को यह बताने की कोशिश की, कि अगर पटेल जैसे व्यक्तित्व राजनीति में सक्रिय होकर काम करेगा तो देश विकासशील से विकसित राष्ट्र में शुमार होगा। देश अपनी गति में चल रहा है और बहुत से राजनेता पटेल जी के बताये मार्ग पर चलकर देश की एकता पर बल देता है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम भी शामिल है। लौहपुरूष पटेल जी की तरह ही विकास एवं प्रदेश की सुरक्षा एवं सामाजिक सारोकार को प्राथमिकता देकर राज्य का विकास करके राष्ट्र में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। पटेल से हमारे आदर्श रहे हैं और सदैव रहेंगे।

ट्रस्ट की अध्यक्ष बहन सुषमा मिश्रा ने कहा कि आज समाज में क्रोध, ईर्ष्या और एक दूसरे को नीचा दिखाने, ह्रास करने का दौर है जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रोटी खुद को दूसरे रोटी दूसरे के लिए निश्चित हो उसको सुनिश्चित किया था। गांव से विश्व स्तर तक पटेल समाज की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता बल्कि राष्ट्रीय एकता को संचालित कर राष्ट्र के उत्थान एवं विकास में कैसे सार्थक भूमिका सिद्ध हो उसपर पुरजोर बल दिया था। सरदार पटेल नहीं होते तो आज

संजय कुमार

अभय सिन्हा

आचार्य लक्ष्मण पाण्डेय

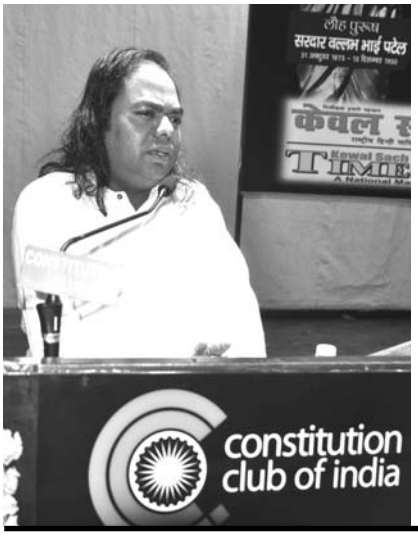

शंभु शिखर

विजय कुमार

डॉ० रमा

राष्ट्र को बचाना बहुत कठिन होता। धार्मिक स्थलों एवं राष्ट्रीय एकता को जीवंत रखने में सरदार पटेल के उद्देश्य को हम कभी नहीं भूल सकते बल्कि सभी भारतीय को शपथ लेना होगा की सरदार पटेल की नीति को देश-दुनिया के पटल पर मजबूती से स्थापित करना होगा। हमारा कोई भाई भूखा नहीं हो और रोटी का निवाला हर पेट को मिले, यही संकल्प श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट का है।

संस्थापक भाई ब्रजेश ने कहा की आज यह देश- प्रदेश किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं चल रहा है बल्कि प्रत्येक भारतीय इस पुनित कार्य में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। प्रधान सेवक के रूप में देश को नरेन्द्र मोदी जैसा व्यक्तित्व एवं अमित शाह जैसा चाणक्य मिला है जिसके रहते दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकते। छोटा-बड़ा का भेदभाव मिटाकर राष्ट्र को सनातन की दिशा में ले जाने की पहल की वजह से ही मोदी आज दुनिया के कोने-कोने में लोकप्रिय हो गये हैं। सरदार पटेल की रणनीति एवं विचारों को आगे बढ़ाने वाले अमित शाह की नीति से भारतीय को सीखना होगा की संकल्प अगर ईमानदारी से लिया जाये तो किसी भी पद पर पहुंचना नामुमकिन नही है और यही परिभाषा लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संदेश दिया है। सुख से जीने के लिए दूसरे के दुख को दूर करना ही होगा अन्यथा आप सम्पन्न हो सकते हैं, सुखी नहीं। सरदार पटेल शांति के भी दूत थे और हत्या एवं किसी प्रकार का षड्यंत्र जैसे शब्दों से भी नफरत करते थे। हर हाथ को काम एवं हर पेट को रोटी का जुगाड़ की तकनीक के भी वह जन्मदाता हैं। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी महत्ती भूमिका निभाई और देश के कई राज्यों के अतिथियों ने संगठन का आमंत्रण स्वीकार किया और खासकर दिल्ली की आवाम का भरपूर साथ एवं समर्थन मिला उसके लिए हृदय से सभी का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली या अन्य राज्यों में भीख मांगकर कार्यक्रम करने की आदत की वजह से संगठन को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अपने महापुरूषों की जीवनी से यह सीख मिलती है की जो ठाना है आपने उसको पूर्ण करने के लिए आहुति भी देनी पड़ सकती है। गरीबी एवं लाचारी के बाद भी सरकार से कोई मदद ऐसे कार्यों के लिए नहीं मिलता जबकि कमीशन देने के बाद बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सरदार पटेल त्याग की प्रतिमूर्ति थे तथा राष्ट्र के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर चुके थे। उन महापुरूषों के आर्दश के कारण ट्रस्ट अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लायेगी।

टीआरपी ब्यॉय इंडिया जयस कुमार को सम्मानित करते डीआईजी विजय कुमार

लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केवल सच, पत्रिका के विभिन्न पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया और संगठन 2020 में होने वाले कार्यक्रम के लिए अभियान में जुट गयी है।

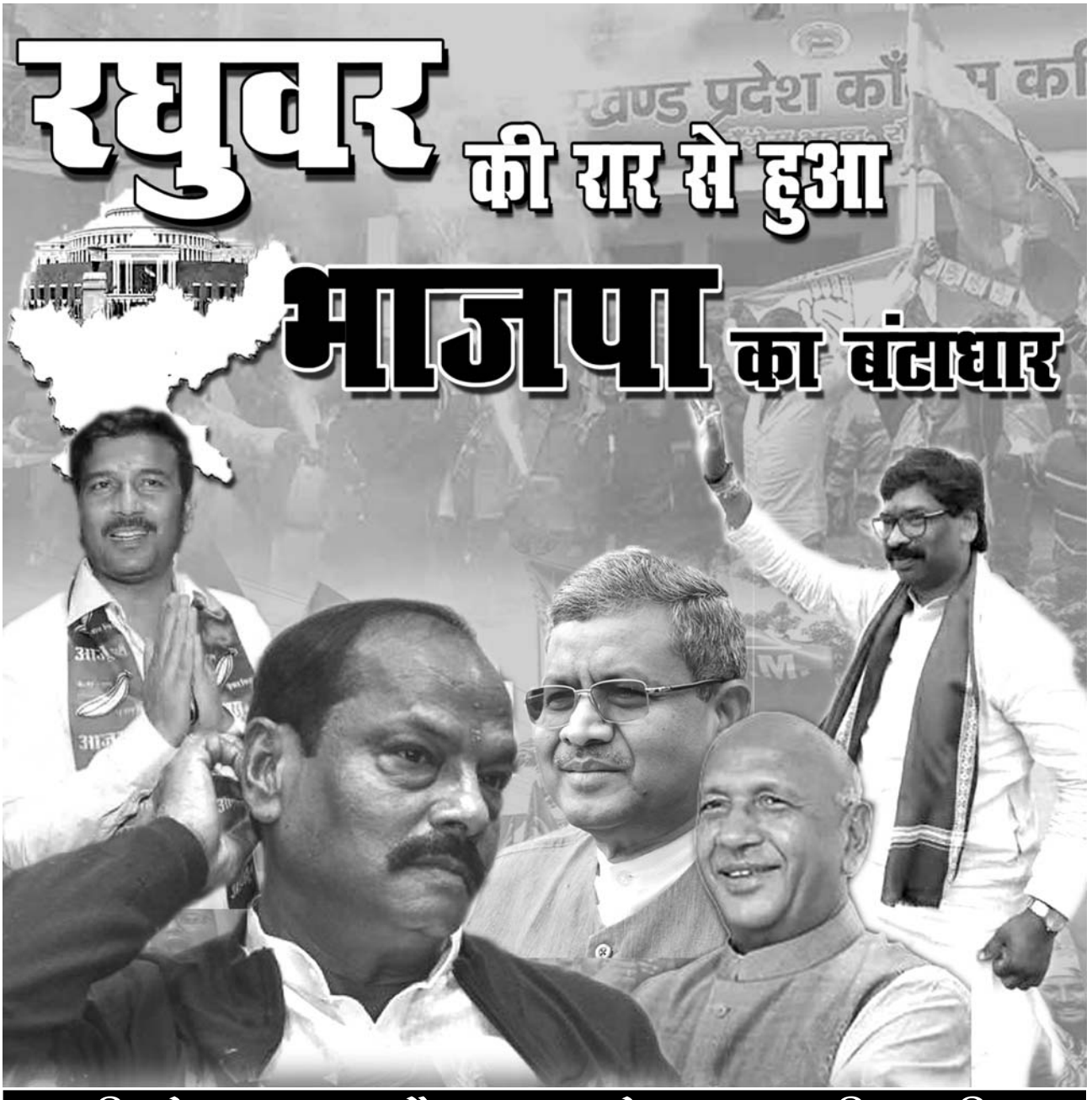

रघुवर की रार से हुआ भाजपा का बंटाधार

उत्तरी छोटानागपुर और पलामू ने भाजपा की २२वी मान दक्षिणी छोटानागपुर में मुश्किल से बची साख

● अमित कुमार/कामोद कुमार कंचन

जब राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बताकर संगठन व सत्ता का अधिकार किन्ही खास हाथों तक सिमट कर रह जाता है, तब वे हाथ खुद को उस संगठन व उससे प्राप्त होने वाले खुद को सत्ता का गॉड फादर समझने लगते हैं और तब उनका यही हश्र होता है जो झारखंड में इस चुनाव भाजपा की हुई। केवल सच ने अपने अक्टूबर माह के संस्करण में ही 'पारा और पेंशन....' नामक शिर्षक में ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अहंकार की गाथा को कवर स्टोरी में प्रकाशित कर चुकी है, परंतु भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसे छोटी बैनर की एक छोटी पत्रिका समझ कर नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम झारखंड में भाजपा को भुगतना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सह ने रघुवर दास के अहंकार को कुछ इस कदर पाला की खुद को झारखंड की जनता से लेकर यहाँ के नौकरशाहों और भाजपा के अदना

से लेकर सरयू राय, रविंद्र पांडेय, रविंद्र राय, निशिकांत दुबे, प्रो० दिनेशानंद गोस्वामी, बैधनाथ राम, लक्ष्मण टुडू और अर्जुन मुंडा की पत्नि मीरा मुंडा सरीके कद्दावर नेताओं के भी भाग्यविधाता समझने लगे। भले ही लोकसभा के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक और मोदी लहर के कारण 14 में से 11 सीटे भाजपा जीती हो, लेकिन यह इनके अहंकार की पराकाष्ठा ही थी कि रविंद्र राय जैसे कद्दावर नेता का टिकट इन्होंने केवल इसलिए कटवा दिया क्योंकि राज्य के पारा शिक्षकों के नियमितीकरण और सरकारी शिक्षकों के समान वेतन संबंधी मांगों को रविंद्र ने समर्थन किया था। यही नहीं गिरिडीह से रविंद्र पांडेय का टिकट तो कटवाया ही, गोड्डा से निशिकांत दुबे का भी पत्ता साफ कराने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि इस में ये सफल नहीं हो पाये, ये अलग बात है। केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पकड़ के कारण निशिकांत दुबे इन पर भारी पड़े। इनकी और निशिकांत दुबे की राजनितिक प्रतिद्विन्दता की चर्चाएं झारखंड में, खासकर संथाल में आम है।

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री के सार्वजनिक सभाओ में मुख्यमंत्री के बजाय निशिकांत दुबे जिंदाबाद के नारे लगना और उन नारों पर रघुवर दास का खीझ जाना बहुत कुछ बयां करता है। हालांकि 6 जिलों से समाहित राजमहल, मधुपुर, देवघर, महगामा, गोड्डा, पोड़ैयाहाट, सारठ, जामताड़ा, जरमुंडी, नाला, जामा, दुमका, शिकारीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, बरहेट, बोरियो सहित 18 विधान सभाओं वाले संथाल परगना पर अपने 5 साल के कार्यकाल में रघुवर दास ने विशेष ध्यान रखा। वावजूद इस क्षेत्र से 2014 की अपेक्षा इन्हें निराशा ही हाथ लगी। सरकार के इतने कार्यों के वावजूद इस क्षेत्र से फायदे के बजाये भाजपा को 4 सीटों की नुकसान ही हुआ। और तो और संथाल के दुमका विधान सभा सीट से सरकार में मंत्री रही लुईस मरांडी तथा मधुपूर सीट से मंत्री रहे राज पलिवार भी हार गए। इनके अलावे महगावां से विधायक अशोक भगत और बोरियो सीट से सूर्य नारायण हासदा हार गये। संथाल में झामुमो का जनाधार दरकाने और अपनी किला फतह करने का भाजपा ने भरपूर प्रयास किया। बावजूद इनका खुद का ही जनाधार खिसक गया। झामुमो के इस गढ़ को जितने के लिए भाजपा सरकार ने विकास की गंगा बहा दी, बावजूद कोई जतन काम न आया।

संथाल में विकास की बात करें तो साहेबगंज मेदी पर बंदरगाह, देवघर में एम्स, दुमका में मेडिकल कॉलेज, पहाड़िया जनजाति बाहुल्य इस क्षेत्र के जनजातियों को साधने के लिए पहाड़िया बटालियन की स्थापना, गोड्डा में रेलवे के तमाम तरह की सुविधाएं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ के वोटरों को अपने पाले में करने का प्रयास सरकार ने की, लेकिन पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व से नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में भाजपा असफल रही, जिसके कारण सरकार की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंच नहीं पायी। जबकि यूपीए ने सुदूरवर्ती वोटरों तक पहुंच कर सरकार की स्थानीय नीति के विरुद्ध यह माहौल बनाने में सफल रहीं की, अगर अगली बार भाजपा की सरकार आयी तो आदिवासियों की जमीन छिन जायेगी। यही संथाल परगना का चुनाव सम्पन्न होने तक एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा बन चूका था, जिसका प्रभाव झारखंड के अंतिम दौर के दो चुनवों पर व्यापक पड़ा। एनआरसी के मुद्दे को भी विरोधियो ने ऐसा भुनाया की मुस्लिम वोटर गोलबंद हो गए, जिसका परिणाम संथाल में देखने को मिला। पाकुड़ में कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलाम का रिकॉड मतों से जीत, एनआरसी के विरुद्ध मुस्लिम मतों का गोलबंदी का ही परिणाम है। हालांकि पाकुड़ में झामुमो प्रत्याशी तथा आजसू प्रत्याशी में से जिताऊ प्रत्याशी कौन है, यह स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण अल्पसंख्यक कहे जाने वाले ये वोटर

अपने कर्मभूमि कोल्हान में शून्य पर आउट हुए साहेब

राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते भले ही रघुवर दास की कर्मभूमि पूरा झारखंड माना जाये, लेकिन झारखंड के जिस क्षेत्र 'कोल्हान' में मुख्यमंत्री का खुद का विधान सभा क्षेत्र अवस्थित हो और इस क्षेत्र से शून्य पर आउट हो जाना, मुख्यमंत्री की हास्यास्पद स्थिति ही मानी जाएगी। यही नहीं, बहरागोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, चक्रधरपुर, ईचागढ़, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, मंझगांव, चाईबासा, खरसांवा, सरायकेला, जुगसलाई, पोटका और घाटशिला सहित 14 सीटों वाली कोल्हान जहाँ पार्टी का दबदबा हुआ करता था, वहाँ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ चक्रधरपुर, आईएएस अधिकारी जेबी तुबिद भी अपनी सीट नहीं बचा सके। रघुवर के प्रति मतदाताओं कार्यकर्ताओं और खास कर कर्मचारियों का आक्रोश इसी से समझा जा सकता है की वर्ष 2005 के विधान सभा चुनाव में भाजपा को 05 सीटें मिली थी, जबकि 2009 में 04 और 2014 में पुनः 05 सीटों पर भाजपा का कब्जा था। परन्तु 2019 के आम चुनाव में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी शून्य पर आउट हो गई। उसमे भी तब, जबकि झारखंड का चुनावी शंखनाद कोल्हान के चाईबासा से ही प्रारम्भ हुआ। वो भी तब जबकि इस क्षेत्र का विधायक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ। वह भी तब, जब वर्तमान राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, राजनाथ सिंह और हिंदुत्व के फायर विग्रेड माने जाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरीके नेता, पार्टी और सरकार की नियत और नीतियों का प्रचार-प्रसार करने और झारखंड जितने आये। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन सबों पर रघुवर और सरयू की रार भारी पड़ गई। यही नहीं रघुवर की निजी पसंद और ना पसंद भी कोल्हान में भाजपा की बंटाधार का कारण बना। अर्जुन मुंडा की पत्नि मीरा मुंडा, भाजपा के किसी भी चुनाव में संघ परिवार की रणनीतियों और उनके संघटनों की अहम भूमिका होती है ऐसे में संघ का सशक्त इकाई माने जाने वाले विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके दिनेशानंद गोस्वामी का टिकट कट जाने से संघ की नाराजगी और लक्ष्मण टुडू जैसे जिताऊ प्रत्याशियों का टिकट कट जाना कोल्हान के लिए दुर्भाग्य पूर्ण साबित हुआ। इस क्षेत्र के लगभग आधे दर्जन शहरी सीटों पर बिहारी मूल के मतदाताओं का खासा प्रभाव है। ऐसे में बिहार से आने वाले सरयू राय का अपमान ने बिहारी वोटरों को तथा अर्जुन मुंडा कि पत्नी तक का टिकट कट जाना, प्रतिष्ठा बन गया और यह भी हार का एक कारण बना। बातों में कितनी सच्चाई है यह तो जाँच का विषय है, लेकिन कहा जाता है कि पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को हराने में रघुवर दास की अहम भूमिका रही थी, ताकि झारखंड की राजनीति में अपना कद बढ़ा सके और यही कारण है कि केंद्र में मंत्री बनवा राज्य की राजनीति में अर्जुन मुंडा की हस्तक्षेप की सारी संभावनायें बंद कर डाली। अर्जुन मुंडा जैसे मात खा चुके नेताओं की अंदरूनी शह तो मिलनी ही थी।

झामुमो के कुतुबुद्दीन शेख और आजसू के एम.टी. राजा में बंट जाने के कारण भाजपा के अनंत ओझा दोबारा बाजी मार गए।

गौरतलब हो कि सात जिलों के 25 विधान सभा क्षेत्रों वाली उत्तरी छोटानागपुर तथा 9 विधान सभाओं में पलामू की जनता ने भाजपा की मान रख ली। रामगढ़, मांडू, बरकागांव, हजारीबाग, बरही, बरकट्ठा, चतरा, सिमरिया, कोडरमा, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धन्यबाद, झरिया, टुडी, बाघमारा में से 11 सीटें उत्तरी छोटानागपुर तथा भवनाथपुर, गढ़वा, हुसैनाबाद, डाल्टेनगंज, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, लातेहार, मनिका में से 5 विधान सभा सीटें भाजपा को पलामू से मिला। हालांकि 2014 के अपेक्षा उत्तरी छोटानागपुर में दो सीटों का जहाँ भाजपा को नुकसान हुआ है, वहीं पलामू में एक सीट फायदे में रहा। उत्तरी छोटा नागपुर के गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से रविंद्र पांडेय जैसे कद्दावर नेता का संसदीय चुनाव में टिकट कट जाने का असर गिरिडीह जिले में देखने को मिला। यहां के 6 में से मात्र एक सीट ही भाजपा को मिली। गिरिडीह जिले से तीन सीटों का नुकसान हुआ है। यहां भी स्थानीय राज्य सरकार से स्थानीय नेताओ और कार्यकताओं

रघुवर दास नहीं, 'रघुवर दाग' हैं

मोदी डिटर्जेंट और शाह लॉन्ड्री भी इस दाग को साफ नहीं कर सकता : सरयू राय

जीत गये झारखण्ड के आडवाणी

आज भले ही भाजपा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही हो, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रचंड बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने में अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के योगदानों को भाजपा के राजनीति में भुलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार झरखंड की राजनीति ही क्या, संयुक्त बिहार के भाजपा राजनीति में भाजपा को जन-जन तक पहुंचाने व सत्ता में स्थापित करने में झारखंड भाजपा के कद्दावर नेता सरयू राय के योगदानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व केंद्र की तरह ही इस कद्दावर नेता को भी झारखंड की राजनीति में आडवाणी की श्रेणी में ला कर खड़ा कर देना चाहती थी, लेकिन झारखंड की जनता को यह ना गंवार गुजरा और लोकतंत्र में भगवान कहे जाने वाले वोटरों ने वोट की ऐसी चोट मारी की अपने आप को झारखंड भाजपा का गॉड फादर समझने वाले साजिसकर्ता ही नेस्तनाबूद हो गये। 1962 से आरएसएस के बाल स्वयं सेवक रहे, तीन-तीन मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने वाले सरयू राय की सख्सियत को इसी से आंका जा सकता है कि राजनीति में लोग इनकी ईमानदारी की कसमें खाते हैं। बिहार की राजनीत में पशुपालन घोटाले को भुनाकर भले ही सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने बैठे हो, लेकिन 1994 में सर्व प्रथम पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ करने का श्रेय सरयू राय को ही है। पशुपालन घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने हेतू सरयू राय ने उच्च न्यायालय से लेकर, सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया। इसी के फलस्वरूप बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित कई नेताओं तथा नौकरशाहों को जेल जाना पड़ा। यही नहीं 1980 में किसानों को आपूर्ति होने वाले घटिया खाद-बीज तथा नकली कीटनाशकों का वितरण करने वाली शीर्ष सहकारी संस्थाओ के विरुद्ध भी आवाज उठा उन्हें मुआवजा दिला एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में सरयू राय ने अपनी छवि संयुक्त बिहार से ही स्थापित कर रखी थी। बाद में अलकतरा घोटाला, खनन घोटाले आदि को उजागर कर सरयू भ्रष्टाचारियों में खौफ का पर्याय बन गये। इनकी यही ईमानदार छवि भाजपा को बिहार व झारखंड में स्थापित होने में मददगार साबित हुई। झारखंड बटवारें के बाद भी सरयू अपने ईमानदार छवि से समझौता नहीं कर पाए और करोड़ों घोटाले को उजागर कर झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी जेल भेजवा दिया। यही कारण था कि इस कद्दावर नेता का नाम 2014 में ही जब भाजपा ने झारखंड में गैर आदिवासी मुख्य मंत्री की परिकल्पना की थी, तब सरयू राय का नाम एक नम्बर पर था, लेकिन राज्य की सामाजिक ताने-बाने इनसे मेल नहीं खाने के कारण ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए और रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वर्तमान विधान सभा के चुनाव में सरयू का टिकट कटवाने वाले रघुवर की सरयू से राजनितिक प्रतिद्वंदिता की गहराई इसी से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद के इस उम्मीदवार को रघुवर दास के मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए लगभग डेढ़ महीने तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। जमशेदपुर पश्चिमी और पूर्वी से दोनों कद्दावर नेताओं की अहम की लड़ाई झारखंड की राजनीत में कोई नई नहीं है। दोनों में शह और मात का खेल 2005-2006 से चलता आ रहा है। यही कारण है कि तत्कालीन झारखंड विधान सभा चुनाव में रघुवर, सरयू की परम्परागत सीट कौन पूछे, राज्य के किसी भी विधान सभा सीट से टिकट से वंचित कराकर ऐसा शह दिया की इस बाल स्वयं सेवक को पार्टी का बागी बनना पड़ा। लेकिन सरयू भी चुकने वालो में से कहाँ थे, इन्होने भी रघुवर के धूर विरोधियों को साथ लिया और कार्यकर्ताओं के नाराजगियों के विसात पर ऐसे मोहरे बिछाये की, मात ही दे दी। ऐसी मात की मुख्यमंत्री कौन पूछे, विधायकी के भी लायक नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री होते हुए अपनी भी सीट नहीं बचा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरयू राय ने अपनी जीत के कारणों की चर्चा करते हुए कहा की कोई व्यक्ति केवल बेईमान रहे चलेगा, बदजुवान रहे चलेगा, लेकिन कोई बदजुवान भी हो और बेईमान भी इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। रघुवर दास संगठन और सरकार के लिए दाग हैं। ऐसा दाग जिसे 'मोदी डिटर्जेंट और शाह लॉन्ड्री भी साफ नहीं कर सकता'।

की नाराजगी के सामने नरेंद्र मोदी जैसे स्टार प्रचारक भी काम नहीं आये। इस क्षेत्र से धनबाद जिला ही भाजपा का मान रखा। हालांकि यहां भी पार्टी की पारम्परिक सीट झरिया से भाजपा को हाथ धोना पड़ा। इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। जिले के 6 में से 4 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। डाल्टेनगंज, छतरपुर और विश्रामपुर की सीटें लाख विरोध के बाद भी भाजपा ने बचा ली। वहीं पांकी और भवनाथपुर जैसे दो नए सीटों पर भी कब्जा कर लिया। पलामू की इस जीत को भी राज्य सरकार की उपलब्धियों से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। यहाँ की जीत का श्रेय भी स्थानीय प्रत्याशियों की रणनीति और चूक को ही जाता है। सरकार के विरुद्ध सबसे ज्यादा गुस्सा स्थानीयता को लेकर अगर कहीं था तो, वह पलामू में ही था। रघुवर सरकार के नौकरशाही ने कुछ ऐसा स्थानीय नीति बनाई थी कि अपने ही राज्य में पलामू वासियों को बेगाना बना दिया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। साथ ही पारा शिक्षकों का मुद्दा, जो सरकार की बुनियाद हिला कर रख दिया। उन आंदोलनों को धार देने में यह प्रमंडल अहम भूमिका का निर्वहन करता है। क्योकि इस प्रमंडल के केवल छतरपुर विधान सभा में ही लगभग 500 पारा शिक्षक है जो अपनी स्थायीकरण को लेकर आंदोलित है। ऐसे में छतरपुर विधान सभा से भाजपा का जितना आश्चर्यजनक है। पलामू के राजनीतिक पंडितों की माने तो दोपहर पूर्व डाल्टेनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी का चुनाव के दिन रिवॉल्वर चमकाना, पांकी से लाल सूरज को साध कर चुनाव लड़ने से रोक लेना तथा कई विधान सभा सीटों पर लगातार पिछले दो-दो टर्मो से नेतृत्व करने के वावजूद अपेक्षित विकास नहीं हो पाना, विश्रामपुर में एक ही परिवार से चुनावी मैदान में भाग्य आजमाना भाजपा के लिए राह आसान कर गया। विश्रामर में नरेश सिंह और अंजू सिंह का चुनाव लड़ा जाना भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी का जीत का कारण बना। झारखंड सरकार में स्वास्थ मंत्री रहे रामचंद्र चंद्रवंशी को उतना भी वोट नहीं मिला, जितना इन दोनों ने काट लिया। वावजूद रामचंद्र चंद्रवंशी को 2014 के अपेक्षा अधिक मत मिले। पुत्र के आकस्मिक निधन के बाद सहानुभूति वोट के आसार पर विश्रामपुर के राजनीत में दबंग माने जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे की जीत पक्की मानी जा रही थी. परन्तु क्षत्रिय वोटों का झुकाव नरेश सिंह और अंजू सिंह की ओर देख मुस्लिम वोटरों ने अपना रुख कांग्रेस के बजाय बसपा के ब्रह्मदेव प्रसाद की ओर कर लिया।

सनद् रहे कि लोहरदगा, कोलेबिरा, सिमडेगा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिल्ली, खिजरी, राँची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, बिशुनपुर और गुमला को मिला कर 15 सीटों वाली दक्षिणी छोटानागपुर में भी भाजपा की शाख बामुश्किल ही बची इस क्षेत्र से 15 में से मात्र 5 सीटों से ही भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा। वह भी तब जब इसी क्षेत्र में राज्य की राजधानी भी अवस्थित है। जहां से विकास की सारी योजनाओं का संचालन और सम्पादन होता हो, उस प्रमंडल के विधान सभाओं में भी एक दो को छोड़ सभी में भाजपा को कड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा। रांची विधान सभा, जिसका नेतृत्व भाजपा के कद्दावर नेता और सरकार के मंत्री चंदेश्वर सिंह पिछले पांच बार से लगातार नेतृत्व करते आ रहें हो उस सीट पर भी इस बार झामुमो प्रत्याशी महुआ माजी से कड़े संघर्षो का सामना करना पड़ा। इसके अलावे खूंटी से नीलकंठ मुंडा, कांके से समरी लाल, हटिआ से नवीन जयसवाल तथा तोरपे से कोचे मुंडा ने जीत हासिल कर भाजपा की शाख बचा ली। यहां भी भाजपा के इस दुर्गति का कारण मुख्यमंत्री का

सकल कर्म कर थकहूं गोसाई

अपने आप को 'पार्टी विथ डिफरेंट' कहने वाली भाजपा, सत्ता तक आने के लिए सारा कर्म-कुकर्म कर थक-हार गई फिर भी सत्ता में बने रहना फिर भी नसीब नहीं हुआ। जब यह पार्टी सत्ता से दूर हुआ करती है तब भ्रष्टाचार और अपराध इसके प्रमुख मुद्दे हुए करते हैं। बिहार में पशुपालन घोटाला, झारखंड में मधु कोड़ा सरकार में हुए घोटाला और कांग्रेस के केंद्रीय सरकारों में टू जी स्पेक्ट्रम, कोयला आदि घोटाला, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, योगेंदर साव जैसे अपराधिक पृष्ठ भूमि वाले नेता इसके मुद्दे हुआ करते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त होते ही भाजपा गंगोत्री बन गई है। गंगोत्री बनी इस पार्टी का दामन थामते ही बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी और अपराधी भी दूध से धूल जाते हैं। झारखंड में इसने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा बाहरियों पर भरोसा किया। यही कारण था कि हत्यारोपी शशी भूषण मेहता से लेकर भ्रष्टाचारी भानू प्रताप शाही तक को पार्टी में शामिल कर लिया गया। हालांकि ये दोनों ने जीत भी हासिल किया, लेकिन पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल करने से कार्यकर्त्ता आक्रोशित थे। भले ही पलामू में तो इसका इन्हें फायदा मिला लेकिन पुरे झारखंड में नुकसान ही हुआ। शशी भूषण और भानू के अलावे झामुमो से जय प्रकाश पटेल, अर्पणा सेन गुप्ता भाजपा का में शामिल हुये, जिन्हें जीत मिली लेकिन इनके अलावे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, मनोज यादव, कुणाल षाड़गी झामुमो से, जर्नादन प्रसाद राजद से भाजपा में शामिल होने वालो में प्रमुख थे, जिन्हें दल बदलने के बाद भी जनता ने नकार दिया।

पारा और पेंशन कर्मियों ने तोड़ा रघुवर का अहंकार

अहंकार से मदमांध रघुवर का अहंकार आखिर पारा और पेंशन कर्मियों ने तोड़ ही दिया। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि, पड़े हुए पोस्टल बैलेटो के ट्रेंड बता रहें हैं। पोस्टल बैलेटो के शेयर आकड़े इसकी पुस्टि करती हैं और यही कारण था कि अहले सुबह लगभग 40 सीटों पर टीवी स्क्रीनों में झामुमो गठबंधन की बढ़त दिख रही थी। ज्ञात हो कि चुनावी प्रक्रिया में लगे सरकारी कर्मी अपना मत पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही देते हैं। गिनती प्रक्रिया में इन वोटों की गिनतियाँ पहले की गिनी जाती है। ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मियों खास कर शिक्षक इस सरकार से नाराज चल रहे थे, तभी तो राज्य के 81 सीटों वाली विधान सभा क्षेत्रों में से 65 विधान सभा क्षेत्रों में झामुमो गठबंधन को बढ़त मिली है। वही चुनाव में सरकारी कर्मियों की भूमिका अहम होती है। एनपीएस कर्मियों ने झमाझम बारिस के बीच रांची के मोरहाबादी मैदान में पुरानी पेंशन आंदोलन को समर्थन करने आये हेमंत सोरेन को उसी दिन झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर दी थी। इसकी घोषणा करते हुए एनपीएस के उड़ीसा राज्य के प्रभारी प्रेम सागर ने कहा था कि जो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, इस बार उसी की झारखंड में सरकार बनेगी। अहंकारी राज्य सरकार को उस मंच से चेताते हुए प्रेम सागर ने यह भी कहा था कि शिक्षकों की चुनाव में अहम भूमिका होती है। कहीं दिमाग लगा दिये तो तारे दिखने लगेंगे। चुनावी वर्ष होने के बावजूद आत्मविश्वास से लवरेज रघुवर सरकार ने इनको साधने की कोशिश नहीं की। राज्य स्तरीय इस आंदोलन में हजारों की संख्या में उपस्थित सरकारी कर्मियों ने अपनी भूमिका की चर्चा करते हुए कहा था कि हम वो हैं जो वोट देते है, वोट दिलाते है, वोट गिनते हैं यानि सरकारें हम ही बनाते है। इन कर्मियों के समर्थन से आह्लादित हेमंत सोरेन ने भी राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था और इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया। यानि इस बार सरकार से नाराज हर एक पक्ष को हेमंत ने कुशल साधकों की तरह साधने का भरपूर प्रयास किया और इनका यह प्रयास सफल भी हुआ। यही नहीं राज्य के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए खाज हो चुके पारा शिक्षकों के आंदोलनों को भी हेमंत सोरेन ने भरपूर समर्थन दिया और अपनी सरकार आने पर इनकी माँगो को पूरा करने का वादा किया। ऐसे में राज्य के लगभग 62 हजार पारा शिक्षकों तथा हजारों सरकारी कर्मियों और उनके परिवार ने हेमंत तथा इनके गठबंधन को अपना समर्थन देकर तकदीर लिख दी। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन अपने वादे पर कब खरे उतरते हैं।

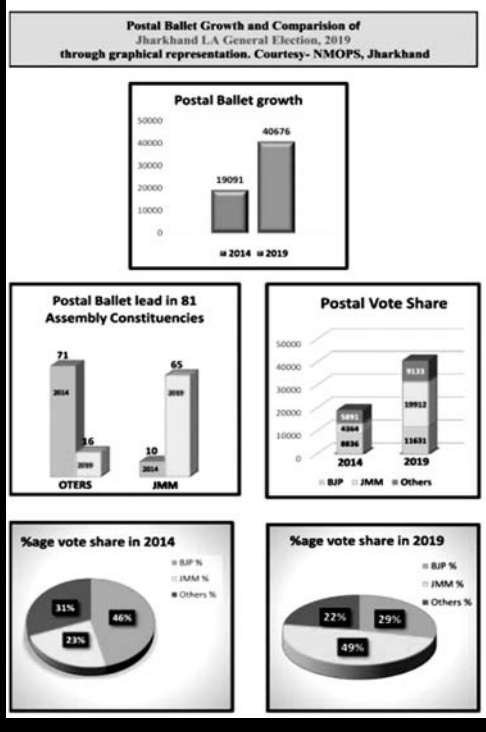

'हमको है जो पसंद, वही बात करेंगे' ही रहा। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और रांची जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भाजपा सरकार द्वारा सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़-छाड़ की कोशिशों से अधिसंख्यक आदिवासी मतदाता तो नाराज थे ही नेतृत्व द्वारा नजअंदाज करने के कारण इस क्षेत्र के कद्दावर नेता कड़िया मुंडा के पुत्र द्वारा झामुमो का दामन थामने का भी खासा असर पड़ा। हेमंत सोरेन की पार्टी और विरोधियों ने इसे आदिवासियों का अपमान और रघुवर के अहंकार से जोड़ कर भरपूर भुनाने का प्रयास किया। जिसमें सफलता भी मिला। इसके अलावे गंगोत्री कुजूर, शिवशंकर उरांव और विमला प्रधान का टिकट कट जाने से भितरघात भी इस क्षेत्र में हार का कारण बना। इस प्रकार विरोधी भले ही इसे अपनी उपलब्धी मान जश्न मना रहें हो, लेकिन वास्तव में यह उनकी उपलब्धि नहीं बल्कि भाजपा की हार है, क्योंकि झारखंड भाजपा में लग गई आग, घर हीं के चिराग से और जल गया आशियाना, साहब के अहंकार से। ●

लंबित काण्डों का निष्पादन करना होगा चुनौति : जयंतकान्त

बिहार के पुलिस प्रशासनिक सेवा में कार्यरत्त कई ऐसे आईपीएस हैं, जिन्होंने अपने काम के बदौलत अपने नाम की डंका देश के हर कोने में बजवाने का काम किया है। क्योंकि बिहार, देश के उन राज्यों में आता हैं जहां की अपराधिक गतिविधियां पूरे देश पर प्रभाव डालती है। इसलिए यहां काम करना काफी चुनौतिपूर्ण भी माना जा सकता है। अक्सर कई दफा यह देखने को पाया गया कि काम के दौरान वरीय पुलिस पदाधिकारियों पर कई तरह से पॉलटीकल प्रेशर से राजनीति में अपना दमखम रखने वालों पर पुलिस का शिकंजा कस पाना आसान नहीं होता। इस बाबत अंगेस्ट टू पॉलीटकल्स इशू को एक किनारे रखकर यहां के पुलिस पदाधिकारियों ने अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आम जनता के बीच विश्वास बना पाने में सफल रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी की आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, वे हैं जयन्तकांत। जहां फिल्मी पर्दे पर अपने धमाकेदार एक्शन से लोकप्रिय अभिनेता रजनीकान्त हैं तो दूसरी तरफ बिहार में अपने कार्यों से हो रहे लोकप्रिय एसएसपी मुजफ्फरपुर, जयंतकान्त हैं। बताते चले की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले जयंतकान्त ने वर्ष 2009 में बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान देना प्रारंभ किया तथा बिहार के रोहतास जिले से ट्रेनिंग के बाद एएसपी फतुहा में रहकर क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान देत हुए अपने काम से लोकप्रियता हासिल की। उसके बाद अपना योगदान नवगछिया तथा एस.पी. जमुई में रहकर नक्सली समस्याओं पर भी काम किया। जयंतकान्त जैसे बहादूर ऑफिसर के सामने इनकी एक नहीं चली। नक्सलियों में इनका खौफ था। इसका अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि जमुई के लोग इन्हें नक्सल डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। फिर उन्हें एस.पी. बेतिया में पोस्टिंग मिली। जब पूरी तरह बेतिया में अपराधियों का खौफ जनता में बना हुआ था, उस समय सरकार ने इस तेज-तर्रार ऑफिसर को वहां क्राइम कंट्रोल के लिए डिबूट किया। गौरतलब हो कि जयंतकान्त को इसके बाद राजधानी पटना का नगर पुलिस अधीक्षक एवं यातायात पुलिस अधीक्षक बनाया गया। सनद् रहे कि नगर पुलिस अधीक्षक, पटना में रहकर अपराधियों में खौफ बनाते हुए क्राइम कंट्रोल का पूरा-पूरा ध्यान इन्होने दिया। इस बाबत वर्ष 2016 में जयंतकान्त को बिहार पुलिस महानिदेशक द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर गेलैंट्री अवार्ड भी मिला। बाद में इन्हें एस.पी. बक्सर का कार्यभार मिला और अब वह बिहार की मिनी राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक का कमान संभाले हुए हैं। वही जमुई में कार्य के दौरान स्थिति सामान्य बनाये रखने एवं बेहतरीय कार्य के लिए दो बार सी.आर.पी.एफ. के डी.जी. द्वारा प्रशस्ती पत्र दिया गया। सिर्फ यही नहीं, जयंतकान्त ने 30 लाख रूपये के इनामी नक्सली कमांडर को पकड़कर सम्मान भी पाया। और तो और इन्हें फेम इंडिया मैग्जीन में एशिया पोस्ट के 25 सर्वश्रेष्ठ सुपर कॉप्स 2017 से सम्मानित किया गया। अगर इनकी निजी जिंदगी पर प्रकाश डाले तो, जयंतकान्त लखनऊ से अपनी शिक्षा अर्जित की तथा कुरूक्षेत्र से आईटीआई किये। उसके बाद एन.टी.पी.सी. में नौकरी भी किये, उसके बाद भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा में आ गये। वही राजधानी पटना में नगर पुलिस अधीक्षक पद पर कार्य के दौरान उनकी मुलाकात स्मृति पासवान से हुई तथा बाद में परिवार की सहमति से एसएसपी जयंतकान्त और स्मृति पासवान ने शादी कर ली। स्मृति की रूचि भी समाजिक कार्यों में देखी जा सकती है। सनद् रहे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वूमेन से स्मृति अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेसंस की डिग्री हासिल की है। बहरहाल, कई जिलों में कार्य का योगदान दे चुके जयंतकान्त को मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करना कोई चुनौति से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां शहरी व्यवसायियों का इसे क्षेत्र माना जाता है तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी नक्सली घटनाएं सामान्य है, फिर भी पूर्व के लंबित करीबन 16 हजार कांडों का निष्पादन कर पाना कोई चुनौति से कम नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर पत्रिका के संवाददाता **अविनाश कुमार** ने एसएसपी मुजफ्फरपुर **जयंतकान्त** का साक्षात्कार किया है, प्रस्तुत है इसके प्रमुख अंश :-

★ विभिन्न जिलों में कार्य करने के बाद आज मुजफ्फरपुर जिले का कमान आपके हांथों में है, यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा?

यह चैलेंजिंग डिस्टीक है और जहां भी मेरी पोस्टींग हुई है, वह भी काफी बड़ा जिला रहा है। ये उत्तर बिहार का हब है। यहां जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ी है तो उसके अनुसार अपराधिक गतिविधियों का बढ़ना लाजिमी है। इसके अलावा ट्रैफिक की भी यहां समस्या है तथा जनता को पुलिस से अपेक्षा भी ज्यादा है, तो इन सभी चुनौतियों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है।

★ देखा गया है कि रात्रि में हाइवे पर ट्रकों से पुलिस के द्वारा अवैध वसूली की जाती है, क्या कहेंगे?

ऐसा कोई सबूत मिले तो हम कार्रवाई करेंगे, जरूर करेंगे। अगर आपके पास इसका सबूत है तो हमें दें, हम इस पर त्वरीत कारवाई करेंगे।

★ मुजफ्फरपुर जिले में अपराध में तेजी आयी है तथा ट्रैफिक की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके लिए क्या करेंगे?

कुछ पुराने केश है जिनपर हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि पिछले एक से दो महीने में सौ से भी ज्यादा अपराधी हथियार के साथ

पकड़े गये हैं तथा जेल भेजे जा चुके हैं। दूसरा आपका सवाल ट्रैफिक का है, तो इसमें हम कहेंगे कि अवैध पार्किंग की वजह से यह समस्या होती है। शॉपिंग मॉल हो या अर्पाटमेंट, इनके पास अपना पार्किंग नहीं होने से जाम की समस्या बढ़ गई है। वही पुलों पर भी गाड़ियों को पार्क करते लोग देखे जा सकते हैं। ये तो नगर-निगम का काम है। पुलिस अपना काम यातायात नियमों के अनुसार ही करता है।

★ इन दिनों थानों में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है। अगर किसी व्यक्ति का सिम कार्ड खो जाता है तो दो सौ और बाइक खो जाता है तो पांच सौ सहित अन्य मामलों के लिए सूचना या प्राथमिकी के लिए थानों में पैसे लिये जाते हैं, क्या कहेंगे?

साफ शब्दों में आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बक्सा नहीं जायेगा। अभी तक हमारे संज्ञान में यह मामला नहीं आया है, फिर भी आप बता रहे हैं तो इसपर हम कुछ स्कॉट टीम लगायेंगे।

★ आधी रात के बाद थाने के गेट बंद देखे गये हैं और पुलिसकर्मी सोये रहते हैं?

देखिए, थाने में ओ.डी. ऑफिसर रहते हैं और फरियादी की कंप्लेन सुनी जाती है तथा एक ओ.डी. ऑफिसर की ड्यूटी होता है कि वह रात में जगा रहता है। हम इसकी गस्ती करते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, लेकिन पूरे थाने की नहीं। ये जांच का विषय है। हम इसपर कार्यवाई करेंगे। लेकिन फरियादी का कोई कंप्लेन नहीं लेता है तो थानेदार का नंबर है, मेरा है। अगर फिर भी कोई फोन नहीं उठाता है तो 100 नंबर पर डॉयल करे तथा इसकी जानकारी दे, कार्यवाई जरूर होगी।

★ थानो में बिना जांच के एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, क्या यह सही है?

ये सही नहीं है। दरअसल, पुलिस का काम है कि उसे जांच करना। होता ये है कि कोई फरियादी अगर कम्लेन लेकर आये और बोले की मैंने किसी का खून किया है इस चाकू से और चाकू पर खून लगा हुआ हो तब भी पुलिस का काम है कि उसे जांचा जाये। रही बात धारा लगाने की तो जांच के दौरान धारा बढ़ाया और घटाया भी जाता है।

★ जिले में मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक होने के बाद भी 24 लाख रूपये की लूट हो गई, पुलिस क्या कर रही थी?

इस लूट की वारदात मेरे संज्ञान में है और आपको बता दूं कि वैन लूट में सुरक्षा गार्ड अपने हथियार को छोड़कर भाग गया था, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है किन्तु पुलिस निर्दोष को तो गिरफ्तार नहीं करेगी। बहुत जल्द इससे जुड़े अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तथा पैसे की रिकवरी भी होगी। हमारी टीम इस पर काम कर रही है।

★ आपने बेतिया में भी अपना योगदान दिया है। बेतिया और मुजफ्फरपुर में क्या अंतर देखते हैं?

बेतिया और मुजफ्फरपुर में काफी अंतर है। मेरे कार्य के दौरान बेतिया में पहली बार छः घटनाएँ हुई, जिसमें एक भी बैंक डकैती नहीं हुई थी तथा दूसरे साल ज्यादा कोई गंभीर घटनाएं नहीं हुई थी। हमारी कोशिश रहेगी की मुजफ्फरपुर में अपराध पर लगाम लगाया जा सके। मुजफ्फरपुर चुनौतियों से भरा शहर है, उसे बेतिया के लेवल पर लाना हमारी कोशिश रहेगी।

★ जमुई में जब आप कार्यरत्त थे तो आपको 'नक्सली डॉक्टर' कहा जाता था। मुजफ्फरपुर में भी नक्सल की समस्या है, क्या कहेंगे?

जी बिल्कुल जमुई की जनता का प्यार हमें बहुत मिला था और उन्होंने ही 'नक्सल डॉक्टर' का नाम मुझे दिया था, जिसे आपकी पत्रिका ने भी प्रकाशित किया था। यहां हमारे जिले में तीन प्रखण्ड है पारू, साहेबगंज और मिनापुर। हमलोग समय-समय पर नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम कराकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां के ए.एस.पी. अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि दस से अधिक नक्सली

गिरफ्तार भी हुए हैं। तीन नक्सलियों कमांडर भी मोतीपुर से गिरफ्तार हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी नक्सली हैं, उसकी गिरफ्तारी हो और जेल से छुटे हुए को रिमांड पर लें। साथ ही जमुई की अगर बात करें तो वहां पर जनता और मीडिया का सहयोग काफी मिला था। यहां पर भी एसटीएफ का तथा सीआरपीएफ का सहयोग मिलता है।

★ आपको कार्य के दौरान कभी कोई पॉलिटीकल प्रेशर मिला है?

देखिए, यह पद ही एक प्रेशर है। जो अपने आप में कर्तव्य का पालन करना ही हमारा लक्ष्य होता है। दरअसल, दो ऐसे मामले हैं जो चुनौतियों से भरा था। एक जमुई को नक्सलियों से मुक्त कराना और दूसरा छठ पूजा के दौरान भगदड़ को कंट्रोल करना। यह काफी चुनौतिपूर्ण था, फिर भी हमने किया और इसके लिए हमें सम्मान भी मिला।

★ आपको नहीं लगता की 498 एक्ट का महिलाएं दुरूपयोग कर रही हैं?

हाँ कुछ केश है जो पूरी तरह से सच नहीं होता। पुलिस का काम है कि जांच करके उस व्यक्ति को अरेस्ट करे। सीधे तौरपर बता दें कि कोई कहे की 'My wife has blood on this knife' तो भी यह काम है पुलिस के लिए जांच का है।

★ केश के सुपरविजन में कई बार रिपोर्ट सही नहीं आता, क्या कहेंगे?

अविनाश जी हम ये नहीं कह सकते की पूरी तरह से केश में रिपोर्ट सही आते हैं। कुछ गलतियां होती ही है किन्तु कमियां सभी में होती है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। फिर भी पुलिस के नाते सही रिपोर्ट आये, यही हमारी अपेक्षा रहती है।

★ नये साल में अपराध नियंत्रण के लिए आपकी क्या योजना होगी?

कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारी कोशिश होगी की आमजनों में पुलिस पर विश्वास बना रहे। आमजनों का विश्वास ही अपराध पर अंकुश लगाने में सहायक होता है। शहर चुनौतियों से भरा परा है और यहां कुछ नया अनुभव मिला है। टीम वर्क से अपराध पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश रहेगी वही कम उम्र के बाईकस गैंग पर कंट्रोल करना तथा 16 हजार लंबित कांड का निष्पादन करना हमारे लिए चुनौति होगी। इसके साथ आधे से ज्यादा दारोगा, जमादार, सिपाही सहित अन्य खाली पदों को मैनेज करना हमारी प्राथमिकता होगी। शराब कारोबारियों के सिंडीकेट को तोड़ना भी हमारी प्राथमिकता में होगी। वाहनों की सघन चेकिंग की जायेगी, ट्रैफिक पर कंट्रोल करना है। साथ ही मुजफ्फरपुर शहर में रह रहे अपराधियों को साफ तौरपर कहना चाहता हूं कि जो अपराधी जेल से छुटे हुए हैं, अगर वह अपराधी गतिविधि में हैं तो मेरी पहली प्राथकिमता होगी कि उन्हें जेल भेजना। इसके अलावा बैंकों की सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए बैंक के जी. एम. से मीटिंग करनी है।

भारी संवैधानिक भूल का सुधार है नागरिकता संशोधन बिल

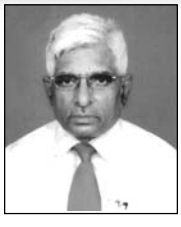

● **ललन कुमार प्रसाद**

करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद 9 दिसम्बर 2019 को करीब पौने बारह बजे रात में लोकसभा से यह बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में कुल 391 में से 311 वोट पड़े और बिल के विरोध में महज 80 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस सहित देश की 11 पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही थी। अर्थात् बिल के पक्ष में 79% वोट पड़े और विरोध में 21% वोट पड़े। राज्यसभा में 11 दिसम्बर 2019 को घंटो गरमा गर्म बहस के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में कुल 203 में से 125 वोट पड़े और विरोध में 105 वोट पड़े। अर्थात् बिल के पक्ष में 55% और विरोध में 45% वोट पड़े। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना जरूरी है कि राज्यसभा में वोटिंग के पहले शिवसेना के सांसद संसद से बाहर चले गये, जबकि लोकसभा में बिल के पक्ष में वोट दिया था। इससे स्पष्ट है कि शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है, इसलिए शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए दो दिन के भीतर ही पलटी मारकर दिखा दिया कि वह कुर्सी के लिए कुछ भी उलटा-पुलटा कर सकती है।

राज्यसभा में बिल पारित होने के पहले विपक्ष द्वारा पेश किये गये करीब सभी 40 संसोधन प्रस्ताव वोटिंग के दौरान गिर गये। इतना ही नहीं बिल को सलेक्ट कमिटी को भेजने का प्रस्ताव भी वोटिंग के दौरान 124 के मुकाबले 99 मतों से धाराशायी हो गया। इससे स्पष्ट है कि बिल को पारित करने के दौरान संसद में सभी मानको का पूरी तरह से पालन किया गया। बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नागरिकता संसोधन बिल कानून बन गया। ऐसे में बिल के विरोध में विपक्ष द्वारा पूरे देश में आगजनी और तोड़फोड़ कराये जाने को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। यह तो भारतीय संविधान और संसद दोनो का घोर अपमान है। यह पूरे देश की जनता का अपमान है, क्योंकि इन सांसदों को भारत की जनता ने ही चुनाव में जिताकर संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। ऐसे में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के सांसदों का चरित्र संसद में बैठने लायक नहीं रह गया है। विपक्ष के सांसदों ने अपने ही हांथों अपने मुख में कालिख पोत लिया है। ऐसे सांसदों के लिए अब संसद नहीं, जेल ही उपयुक्त स्थान हो गया है, क्योंकि अब ये सांसद देश की जनता के लिए गद्दार साबित हो गये हैं। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे दगाबाज राजनेताओं

को आगामी चुनाव में जनता को अवश्य ही मजा चखाना चाहिए। जनता को ऐसे राजनेताओं का अवश्य ही बहिष्कार करना चाहिए।

★ क्या है नागरिकता संसोधन बिल (CAA या CAB)? :- इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर उत्पीड़ित उपरोक्त तीन देशों से पलायन कर भारत में आये अल्पसंख्यकों यानि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। अर्थात् जो गैर मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 या उससे पहले भारत आये हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता देने का वादा भारत ने किया था, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जायेगी। गैर मुस्लिम यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइ।

यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया जाना जरूरी है कि यह प्रक्रिया आजादी के वर्षो पहले से चली आ रही थी। 26 सितम्बर 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा था कि पाकिस्तान में रह रहे हिन्दु और सिख वहां नहीं रहना चाहते हैं तो वे नि:संदेह भारत आ सकते हैं। इस मामले में उन्हें रोजगार देना, नागरिकता देना और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। दरअसल, ब्रिटेन चाहता था कि भारत को आजादी मिले, लेकिन आजादी मिलते समय खंड-खंड में बंटा हो। अर्थात् भारत एक न रहकर भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बंट जाये। भारत को बांटने की प्रक्रिया भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटवेटेन की देख-रेख में आजादी मिलने के वर्षो पहले से ही चल रही थी। मो० अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नहेरू यथाशीघ्र देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए व्यग्र थे। यदि ये दोनो नेता सत्ता के लिए इतने व्यग्र न होते तो भी देश आजाद होता ही। ऐसा इसलिए क्योंकि

अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अब भारत को पराधिन रखना संभव नहीं है। उन्हें भारत को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन वे भारत को एक मजबूत देश के रूप में नहीं, बल्कि एक कमजोर देश के रूप में, एक लाचार देश के रूप में देखना चाहते थे और वे अपने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में सफल भी हो गये। हर भारतीय को समझना ही चाहिए की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर सताये गये गैर मुस्लिमों को उक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यक यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हमारे अपने ही है। उन्हें वहां आजादी के समय से ही बुरी तरह से सताया जा रहा है। इसलिए वे भारत में आना चाहेंगे तो हम उन्हें जरूर स्वीकार करेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने शपथ ग्रहण के समय कहा था कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते जो भी वहां से विस्थापित होने का कष्ट झेल रहे हैं, वे कभी भी भारत आ जाये, उनका यहां स्वागत है।

★ क्या है नेहरू-लियाकत समझौता? :- 'नेहरू-लियाकत समझौता' के तहत 1950 में नैतिकता संसोधन कानून लागू किया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के लोग भारत के विभाजन का दंश झेल रहे थे। वह दौर था जब दंगा पीड़ित लाखों लोग भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार आ जा रहे थे। देश के विभाजन के समय आठ से दस लाख लोग मारे गये थे। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच दिल्ली के गवर्नमेंट हाउस में बातचीत की शुरूआत हुई, जो छः दिनों तक चलती रही। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 8 अप्रैल 1950 को समझौता पर दस्तखत किये। इसे नेहरू-लियाकत समझौता का नाम दिया गया। इस समझौते को 'दिल्ली पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के तहत शर्त है कि प्रवासियों को ट्रांजिट यानि भारत-पाकिस्तान की सीमा के आर-पार आने-जाने के दौरान आने-जाने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। वे बची हुई संपत्तियों को बेचने के लिए सुरक्षित भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत सीमा से होकर आ-जा सकते हैं। जिन औरतों का अपहरण किया गया है, उन्हें वापस परिवार में भेज दिया जायेगा। अवैध तरीके से कबजाई गई दोनो देशों के अल्पसंख्यकों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी जायेगी। जबड़न धर्म परिवर्तन अवैध होगा। अल्पसंख्यको को देश के सभी नागरिकों की तरह बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिये जायेंगे। दोनो देशों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी तरह का कुप्रचार नहीं चलने

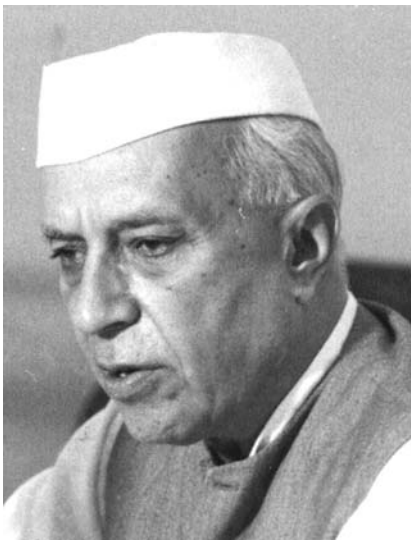

दिया जायेगा। दोनो देश अपने-अपने देश के अंदर आपस में युद्ध को भड़काने वाले और देश की अखंडता के खिलाफ खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे। इसी समझौते के तहत दोनो देशों में अल्पसंख्यक आयोग बनाये गये। जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न से उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन, पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत समझौते का पालन नहीं किया, जिससे पाकिस्तान वहां के अल्पसंख्यकों के लिए दोजख बन गया। जिसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक भुगतते आ रहे हैं और जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, कभी भी नहीं की जा सकती है। भारत ने नेहरू-लियाकत समझौते का पूरी तरह से पालन किया, जिससे भारत अपने यहां रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत बन गया है। अगर धर्म के आधार पर 1947 में देश का विभाजन नहीं हुआ होता तो 2019 में नागरिकता संशोधन बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती।

दरअसल नेहरू-लियाकत समझौता खुल्लम-खुल्ला कानून के स्तर पर साम्प्रदायिक विभाजन का मामला है, जिसकी इजाजत आजादी की सैकड़ों वर्ष लंबी लड़ाई की पृष्ठ भूमि में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान नहीं देता है। लेकिन नेहरू तो नेहरू थे, वे अपने को सुपरमैन समझते थे। इसलिए किसी को भी अपने सामने नहीं लगाते थे। उन्होंने भारतीय संविधान को भी कोई खास महत्व नहीं दिया। भारत की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज नेहरू जी ने अनुच्छेद 370 को अपने वर्चस्व के बलबूते जम्मू-कश्मीर में इस आश्वासन के साथ अस्थायी रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया कि निकट भविष्य में शीघ्र ही अनुच्छेद 370 को हटा लिया जायेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, देश की जनता के साथ धोखा दिया। देश को तोड़ने वाले यानि देश से जम्मू-कश्मीर को अलग करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के बजाये इस अनुच्छेद को भरपूर मजबूती प्रदान करने के लिए 14 मई 1954 को

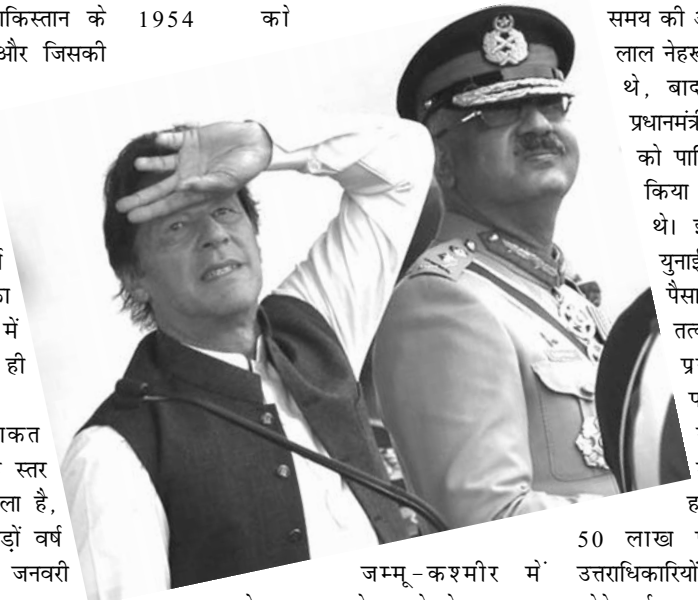

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35 ए को चुपके से लागू कर दिया। अनुच्छेद 25 ए को लागू करने के लिए संसद में इसको रखा नहीं था, उन्होंने संसद में चर्चा करने के लिए कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसा करके नेहरू ने भारत और भारत की जनता के साथ भारी गद्दारी की। भारत में एक ही शेर दिल गृहमंत्री हुए सरदार पटेल। जिन्होंने नेहरू जी के नहीं चाहने के बावजूद भी देश के 565 छोटे-बड़े रियासतों को देश में विलय करा दिया। वरना भारत देश के न जाने कितने टुकड़े हो गये होते, भारत देश का वजूद ही मिट गया होता।

☆ **कौन थे लियाकत अली खान? :-** लियाकत अली खान की शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ में हुई थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा था। भारत के विभाजन और आजादी के पहले एक अस्थायी और कम समय की अंतरिम सरकार में वे पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रीमंडल में सहयोगी भी रहे थे, बाद में वे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ने ही हैदराबाद निजाम को पाकिस्तान में विलय करने को राजी किया था। नेहरू जी भी इसके लिए राजी थे। इसके लिए हैदराबाद निजाम ने युनाईटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बैंक में पैसा भी जमा करवा दिया था। लेकिन, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के प्रयास से हैदराबाद का विलय पाकिस्तान के बजाय भारत में हो गया। यही कारण है कि वर्ष 2019 में लंदन हाईकोर्ट में पाकिस्तान के हार जाने के बाद वह पैसा 3 करोड़ 50 लाख पौण्ड हैदराबाद निजाम के उत्तराधिकारियों (वारिसों) मुकरंम जाह और उनके छोटे भाई मुफक्कम जाह को दे दिया गया, इतना ही नहीं मुकदमे की कानूनी खर्च की भरपाई के एवज में 60 लाख पौण्ड की राशि भी पाकिस्तान को हैदराबाद निजाम के वारिसों को देना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में 1949 में नेशनल बैंक की स्थापना की तो उन्हें बहुत सराहना मिली। 16

अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली खान को गोली मारकर हत्या कर दी गई।

★ दोजख है पाकिस्तान, जन्नत है भारत :- पाकिस्तान का निर्माण ही मुस्लिम देश के रूप में हुआ है, इसलिए वहां पर मुसलमानों को क्यों प्रताड़ित किया जायेगा? वहां पर पहले कभी भी मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं किया गया है, आज भी नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और भविष्य में भी प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। फिर भी यदि आज बॉर्डर से सेना हटा ली जाये तो पाकिस्तान के सभी मुसलमान भारत आ जायेंगे, पाकिस्तान जड़-मूल से मिट जायेगा। ऐसा इसलिए की आज पाकिस्तान की मालीय हालत इतनीइ खराब है, इतनी जर्जर हो गई है कि वहां के मुसलमान मुफलिसी में जिने को मजबूर हैं। वहां की आधी से अधिक आबादी को दो जून का भोजन भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। पूरा देश कर्ज के भारी बोझ तले बुरी तरह डूबा हुआ है। इमरान सरकार कटोरा लेकर पूरी दुनियां में भीख मांग रही है। अर्थात् पाकिस्तान पूरा का पूरा दोजख बन गया है। लेकिन यदि बॉर्डर से सेना हटा ली जाये तो एक भी भारतीय मुसलमान पाकिस्तान नहीं जायेगा, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के लिए भारत जन्नत है। यहां पर हर भारतीय मुसलमान को हिन्दुओं से बहुत अधिक सुविधाएं दी गई है। पूरी दुनियां में भारत के मुसलमानों को जितनी सुविधाएं प्राप्त है, उतनी सुविधा किसी भी मुस्लिम देश में मुसलमानों को प्राप्त नहीं है। इसलिए आज भारत का हर मुसलमान गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहा है कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में, खासकर पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं जायेंगे। मरना कबूल है, लेकिन भारत को छोड़कर किसी भी दूसरे देश में जाना कबूल नहीं है।

★ हिन्दुओं को दी जा रही जबरदस्त अमानवीय यातनाओं से निजात पाने का बिल है 'नागरिकता संशोधन बिल' :- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिस क्रूरतापूर्वक हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को 1947 से ही लगातार धार्मिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता रहा है, वह मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। ध्यान रहे, उपरोक्त तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई ने भारत के बंटवारे की मांग नहीं की थी। वर्ष 1947 में मो० अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जल्दी से जल्दी गद्दी हासिल करने के चक्कर में देश की जनता की राय लिये बगैर ही धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान का निर्माण तो मुस्लिम देश के रूप में हो गया, लेकिन भारत ने अपनी हिन्दु मान्यताओं के चलते धर्म आधारित देश बनना पसंद नहीं किया। हिन्दु मान्यताएँ धर्म निरपेक्षता के अनुकूल है। इसलिए हिन्दुओं का किसी भी धर्म या पंथ से कोई टकराव नहीं है। भारतीय इतिहास इस तरह के दृष्टांतों से भरा-पटा है। इसलिए भारत में किसी का भी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न नहीं किया जाता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या पंथ को मानने वाला क्यों न हो। महात्मा गांधी देश का बंटवारा कभी नहीं चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति में जिन्ना-नेहरू ने धार्मिक आधार पर अफरा-तफरी में देश का बंटवारा कर लिया। महात्मा गांधी के अडिग रहने के चलते भी भारत धर्म निरपेक्ष बना रहा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की सरकारें भारत की नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चिंता जाहीर कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि भारत का धर्म निरपेक्षता

संशोधन बिल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, लेकिन क्या पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफगानिस्तान धर्म निरपेक्ष देश है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और धर्म निरपेक्ष देश ही बना रहेगा। भारत के उपरोक्त पड़ोसी देशों को भी धर्म निरपेक्ष होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये तीनों पड़ोसी देश ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों देशों में इंसानिसत नाम की कोई चीज नहीं है। ये तीनों देश इस्लाम के नाम पर हिन्दुओं पर जुल्म और सिर्फ जुल्म करते आ रहे हैं। इन तीन देशों को इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। इस्लाम के नाम पर कलंक हैं ये तीनों देश।

1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। उसने तब ऐसा किया, जब वहां अच्छी-खासी संख्या में अल्पसंख्यक यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई रहते थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी, जो 2011 में घटकर 3.7% हो गई और अब महज 1.6% रह गई है। दरअसल, 1947 से ही पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार शुरू हो गया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है।

1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, तभी से वहां धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार शुरू हो गया। हिन्दु महिलाओं का अपहरण कर उनका जबड़ीया धर्मांतरण किया जाने लगा, अल्पसंख्यकों को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जाने लगा, हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाने लगा, हिन्दुओं की हत्याएं की जाने लगी, उनके घरों को आग की भेंट चढ़ाई जाने लगी। इन्ही कारणों से वर्ष 1947 में वहां की आबादी 23% थी, जो अब मुश्किल से 1.6% रह गई है। कहां गये ये अल्पसंख्यक? या तो वे मुसलमान बना दिये गये या मार दिये गये या वहां से पलायन कर गये? यूरोपीयन युनियन संसद की मई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष एक हजार वहां के अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। मानवाधिकार संगठनों और पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान में हर साल करीब एक हजार हिन्दु लड़कियों का अपहरण कर जबड़न उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनकी शादी मुसलमानों से करा दी जाती है। इनमें बड़ी तादाद में नाबालिक लड़कियां होती है। पाकिस्तानी महिला पत्रकार आयशा असहर की माने तो पाकिस्तान में हर महीने कम से कम 20-25 हिन्दु और ईसाई लड़कियां, मुस्लिम बलात्कारियों की शिकार बनती हैं। स्थितियां इतनी विकट है कि पेशावर जैसे कई इलाकों में हिन्दु और सिख, शवों का दाहकर्म न कर पाने के कारण दफनाने के लिए मजबूर हैं। हिन्दु मंदिरों और सिख गुरूद्वारों पर हमले होते ही रहना तो आम बात है। पाकिस्तान में हिन्दुओं पर किये जा रहे दिल दहला देने वाले जुल्मों की कोई सीमा नहीं है। पाकिस्तान हिन्दु काउंसिल की माने तो धार्मिक उत्पीड़न के चलते हर साल पांच हजार हिन्दु पाकिस्तान से भारत पलायन कर रहे हैं।

1947 में पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में हिन्दुओं की आबादी 31% थी, जो घटकर 1951 में 22%, 1961 में 18.5%, 1974 में 13.5%, 1981 में 13.13%, 1991 में 11.6%, 2001 में 9.8% और 2011 में 7.8% हो गई। जबकि इस अवधि में बांग्लादेश की आबादी तीन गुनी बढ़ी है। न्यूर्याक स्टेट युनिवर्सिटी के शोधकर्ता शची दास्तीदार ने 2008 में किये गये अपने शोध में पाया था कि 4 करोड़ 90 लाख हिन्दु बांग्लादेश से गायब हो चुके हैं। धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की ऐसी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। जाहिर है कि इन हिन्दुओं को या ता मार डाला गया या धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बना दिया गया या फिर बांग्लादेश से पलायन को मजबूर कर दिया गया। सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर मुसलमानों द्वारा हर तरह का जुल्म किया जाता है। बांग्लादेश के लेखक सलाम आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1947 से 1991 के बीच प्रतिदिन औसतन 475 लोग यानि हर साल 1 लाख 73 हजार 375 हिन्दू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य होते थे। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो

आज बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी 3 करोड़ 25 लाख होती।

बांग्लादेश में 'शत्रु संपत्ति अधिनियम' वहां के अल्पसंख्यकों के लिए काल साबित हो रहा है, क्योंकि यह कानून अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन-जायदाद से बेदखल करने का हथियार बना हुआ है। इस कानून की वजह से बांग्लादेश में रह रहे लाखों अल्पसंख्यकों को अपनी जमीन गंवानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मो० गुलाम रब्बानी और ढ़ाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अबुल बरकत ने लिखा है कि 'शत्रु संपत्ति कानून' की वजह से देश में 1965 से 2006 के दौरान हिन्दुओं की 26 लाख एकड़ जमीन दूसरों के कब्जे में चली गई। इस कानून के कारण चटगांव में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की 22% जमीन उनके हांथों से निकल गई। वास्तव में बांग्लादेश से हिन्दुओं और बौद्धों को पलायन की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह यह कानून भी है। साल 1971 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान और उसके बाद 2009 में फिर अवामी लीग पुन: सत्ता में आयी तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 'वेस्टेड प्रोपर्टी एक्ट' और 'वेस्टेड प्रोपर्टी रिर्टन एक्ट' बनाकर हिन्दुओं से छिनी गई जमीन को उन्हें वापस लौटाने का असफल प्रयास किया। ऐसा इसलिए कि आज तक एक भी हिन्दु की छिनी गई जमीन को लौटायी नहीं जा सकी है। इस समय वेस्टेड प्रोपर्टी रिर्टन एक्ट से जुड़े करीब दस लाख अल्पसंख्यकों, खासकर हिन्दुओं के मुकदमे बांग्लादेश के विभिन्न अदालतों में लंबित है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं को हत्या तथा अन्य संगीन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वहां पर पिता के सामने बेटी और माँ-बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है। बांग्लादेश में हिन्दु महिलाओं का उत्पीड़न और जबड़ीया धर्मांतरण जैसे उत्पीड़न को सहना पड़ता है। वर्ष 2016 के अक्टूबर-नवम्बर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दु समुदाय पर हुआ हमला उस समय काफी चर्चा पर रहा था, जिसमें नसीरनगर इलाके में भीड़ ने 15 हिन्दु मंदिरों पर हमला कर उनको ध

Tribal Hindu housewives, gang raped by Islamic fanatics. The insult made them speechless. (Mukto-Mona.com)

रासायी कर दिया था तथा देवी-देवताओं के मुर्तियों को तोड़ दिया था और हिन्दुओं के एक सौ घरों को आग के हवाले करके लूटपाट की थी। वर्ष 2012 में बौद्ध मंदिरों पर हमला किया था, जिस दौरान कुछ बौद्धों की मौतें हो गई थी। कुछ बौद्धों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। उस दौर में जिन हिन्दु मंदिरों पर हमला किये किये गये उनमें जगन्नाथ और गौरा मंदिर उल्लेखनीय है, क्योंकि ये दोनो मंदिर आस्था के बड़े केन्द्र माने जाते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के पास तीन ही रास्ते हैं-पहला की आत्महत्या कर लें, दूसरा की धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन जाये और तीसरा की देश से पलायन कर जाये। इन तीनों में तीसरा रास्ता ही सहुलियत वाला है।

अफगानिस्तान भी इस्लामिक देश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह वहां भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अनेकों तरह से सताया जाता है। वहां भी अल्पसंख्यकों को या तो मुसलमान बना दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई या वहां से पलायन कर गये। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में हिन्दुओं और सिखों की आबादी सात लाख हुआ करती थी, जो वर्तमान में घटकर महज पंद्रह सौ रह गई है। सिर्फ पिछले तीन दशकों में 90% हिन्दु और सिख अफगानिस्तान को छोड़कर पलायन कर चुके हैं और शेष इस्लामिक कट्टरपंथियों के शिकार बन चुके हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हिन्दुओं और सिखों के डेलीगेट की बस पर किया गया फिदाइन हमला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। अफगानिस्तान में चले युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के चलते वहां सिखों और हिन्दुओं का सफाया हुआ, जिसे सारी दुनियां ने देखा। सारी दुनियां ने देखा कि अफगानिस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतीमा को तोप के गोले दागकर तोड़ा गया।

म्यांमार के अकरान में रह रहे हिन्दु, रोहिंग्या मुसलमान के हांथों बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ित हो रहे हैं। हिन्दुओं के कोई-कोई गांव का पूरी तरह से सफाया हो गया है। बहुत दिन

पाकिस्तानी रिफ्यूजी हसीना बेन

नहीं हुए, जब वहां के कब्र में दफनाये गये करीब एक सौ हिन्दुओं के शव मिले थे।

ये तो विदेशों की घटनाएं हैं। देश में भी हिन्दुओं का कोई कम धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता है। मसलन, कश्मीर को ही ले लीजिए। 1979-80 में कश्मीरी पंडित दिल को दहला देने वाली धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ जमकर अनगिनत संख्या में दुष्कर्म किया गया है, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। उनके जमीन-जायदाद को अवैध रूप से कब्जा ली गई है। उनको, उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया है। करीब पांच लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से जबरन निष्कासित कर दिये गये हैं। उस समय केन्द्र में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तथा नेशनल काफ्रेंस की सरकार थी। 30 वर्ष बीत गये, आज तक एक भी निष्काषित कश्मीरी पंडित को कश्मीर में वापस नहीं बसाया जा सका है। कांग्रेस द्वारा पैदा की गई यह समस्या इतनी दुरूह है कि मोदी सरकार के साढ़े पांच वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी जस की तस बनी हुई है।

★ हिन्दुओं पर हो रहे भारी जुल्म को कुछ कम करने का कानून है 'नागरिकता संशोधन बिल' :- आजादी के समय से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिन्दुओं पर हो रहे भारी जुल्म को कुछ कम करने का कानून है 'नागरिकता संशोधन बिल'। उपरोक्त तीनों देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित हिन्दुओं के घर वापसी का बिल है, मूल वतन को लौटाने का बिल है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तोड़फोड़, आगजनी और अराजकता फैलाकर इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी के देशद्रोही चरित्र को न सिर्फ दर्शाता है, बल्कि भारत से हिन्दुओं को खदेड़ने के नियत को भी दर्शाता है। इसी कांग्रेस पार्टी का कारनामा है कि 1979-80 में पांच लाख कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से प्रताड़ित कर कश्मीर से ही खदेड़ दिया गया, उनको उनके घर से बेदखल कर दिया गया, जो 30 वर्षों से दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषित कर रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए को खत्म कर देगी। अर्थात् देश-द्रोहियों, अलगाववादियों को खुली छूट दे देगी की वे देश को तोड़ने के लिए देश भर में कोई कितना भी तोड़फोड़ करे, आगजनी करे, वह निर्दोष ही बना रहेगा। उनके विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा। देश का मुस्लिम समुदाय, देश के हिन्दु समुदाय को देश के किसी भी इलाके से खदेड़ दे, उसे कानूनी तौरपर जायज माना जायेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही पार्टी, अलगाववादी पार्टी नहीं माना जाये, तो और क्या माना जाये? कांग्रेस पार्टी के क्रिया-कलापों से लगता है कि यह पार्टी भारत को इस्लामिक देश बनाकर ही दम लेगी।

मुसलमान इस्लामिक देशों या मुस्लिम बहुल देशों में नागरिकता पा सकते हैं, लेकिन हिन्दुओं को कश्मीर की तरह अपने ही देश से खदेड़ दिया जायेगा, तो वे भारत को छोड़कर और कहां जायेंगे। विभाजन के बाद भारत में रह रहे हिन्दु, देश के विभाजन के पहले भारत के ही नागरिक थे। लेकिन, विभाजन के बाद से ही देश में उनका धार्मिक उत्पीड़न भयानक रूप से होने लगा है तो वैसे में वे शरण लेने के लिए किस देश की ओर देखेंगे? हिन्दुओं का दुनियां में भारत को छोड़कर कोई दूसरा देश नहीं है। बहुत प्राचीन काल से ही भारत हिन्दुओं का देश रहा है। भारत हिन्दुओं का मूल देश है, इसलिए देश का बंटवारा होने के बाद से ही इस्लामिक देश पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए हिन्दुओं का पाकिस्तान से पलायन कर भारत आना स्वभाविक है। भारत की आत्मा और नियती हिन्दुओं से जुड़ी हुई है, चाहे वे दुनियां के किसी भी देश में क्यों न रह रहे हो। इस नागरिकता संशोधन बिल के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार ही नहीं, दुनियां भर के किसी भी देश में धार्मिक आधार पर सताये जा रहे हिन्दु भारत के नागरिक बन सकेंगे, तभी भारत से उनका खोया हुआ रिस्ता भारत से स्थापित हो सकेगा। वर्षों बाद किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गये हिन्दु पुनः अपने परिवार से मिल सकेंगे। यह सौ फिसदी स्वभाविक भी है और न्यायोचित भी। इसलिए दूसरे देशों में धर्म के आधार पर सताये गये हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को हर हालत में नागरिकता संशोधन बिल को पूरी तरह से लागू कर उनको लाभ दिलाया ही जाना चाहिए। ऐसा किये जाने से किसी कारणवश अपने देश से बिछड़ गये हिन्दुओं

के मन में अपने मूल देश भारत के प्रति गौरव और अधिक बढ़ जायेगा। इतना ही नहीं दुनियां के सभी देश अपने-अपने देश में बसे हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे, जो देखा ही जाना चाहिए। हिन्दुओं और सिखों में खासियत है कि ये जिस देश में बसे हुए हैं, उस देश को तन-मन से अपना मानते हैं। उस देश के विकास में जी-जान से जुटे रहते हैं और उस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए यदि कारणवश यह भटक कर अपने घर से बाहर चले गये किसी व्यक्ति को वापस अपने घर लौटने से कैसे रोका जा सकता है? अपने देश से भटक कर बाहर गया हुआ कोई व्यक्ति अपने घर नहीं लौटेगा तो कहां जायेगा? इसलिए कश्मीर से मुसलमानों द्वारा जबरन खदेड़े गये कश्मीरी पंडितों को पुनः कश्मीर में बसाने के लिए मोदी सरकार को युद्ध स्तर पर अविलंब हर संभव प्रयास करनी चाहिए। इस बात को देश के हिन्दुओं को अच्छी तरह समझाना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी तथा अमित शाह और क्या कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। जमाने के बाद भारत को लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री और सरदार पटेल जैसा गृहमंत्री मिला है। अब कोई पाकिस्तान, भारत की एक इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। जैसा कि 1947 में पंडित नेहरू के समय में पाकिस्तान, भारत के कश्मीर की एक तिहाई जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नाम से जाना जाता है। अब कोई चीन, भारत के एक इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा, जो 1962 में पंडित नेहरू के समय में 72 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा

कर रखा है। ये बातें पाकिस्तान के विरूद्ध 2018 में पहली बार भारत द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में भारत द्वारा पहली बार पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक से साबित हो जाता है। वर्ष 2018 में भारत द्वारा 77 दिनों तक डोकलाम में चीनी सेना को न सिर्फ रोके रहने बल्कि वापस लौट जाने को बाध्य करने को यानि भूटान में चीनी सेना के प्रवेश को रोकने से भी यह बात प्रमाणित हो जाती है। इससे यह भी साबित होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को कितनी मजबूती से बाहरी हमलों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि आज विश्व की महाशक्ति चीन भी भारत की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने से डर गया है। इसलिए हर भारतीय नागरिक का पुनित कर्तव्य है कि पूरी ताकत से मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करे और देश को विघटन करने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में बुरी तरह पटखनी देकर उनकी विघटनकारी मंसूबों पर पानी फेर दे, फेर दिया ही जाना चाहिए।

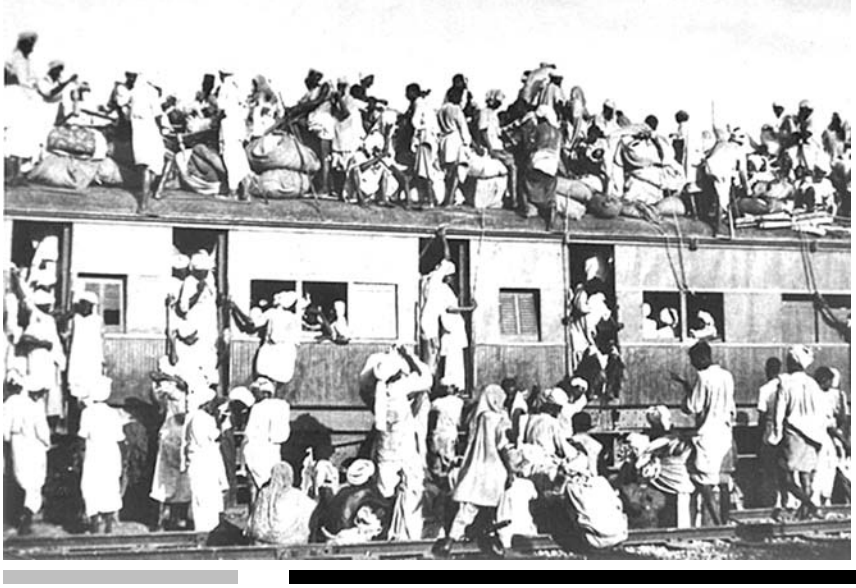

★ नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? :- 11 दिसम्बर 2019 को कांग्रेस पार्टी की वजह से मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत पड़ी। अगर धर्म के आधार पर 1947 में देश का विभाजन नहीं किया गया होता तो, संसद के दोनो सदनों से इस बिल को पारित कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जाती है और भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तें क्या है? घुसपैठ रोकने के लिए और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों की मदद करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 के पहले तक पांच बार 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संसोधन किया जा चुका है। फिर भी समस्या जस की तस बनी रही। 2019 में मोदी सरकार को संशोधन करनी पड़ी, जो हर लिहाज से न्यायोचित है।

भारतीय संविधान का प्रारंभिक शब्द 'इंडिया डैट इज भारत....' भारतीय गणतंत्र को राष्ट्र राज्य की मान्यता देते हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के मुताबिक राज्य पुरातन सभ्यता और

सांस्कृतिक पहचान का उत्तराधिकारी होता है और उसके ऊपर पुरातन पहचान को बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है। इसी उत्तरदायित्व के पालन में नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा पड़ोसी राज्य में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों यानि हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को राहत देना भारत की नैतिक एवं संवैधानिक बाध्यता है। भारत की संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का अनुमोदन भारतीय सभ्यता के एक गहरे घाव पर मरहम का काम करेगा।

★ असंवैधानिक है नागरिक संशोधन बिल का विरोध :- स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका के शिकागो में 'विश्व धर्म संसद' में अपने संबोधन में कहा था-'मुझे भारत देश का नागरिक होने पर गर्व है, जिसने सभी धर्मों और दुनियां के सभी देशों के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है'। मोदी सरकार ने भारत की इसी विरासत पर आधारित CAA या CAB कानून बनाया है। भारत को दुनियां हिन्दु देश के रूप में मानती, जानती है। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को समान्य बताते हुए सउदी प्रिंस ने कहा था-'भारत तो हिन्दु देश है'। फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर वहां के अल्पसंख्यकों का दिल को दहला देने वाला उत्पीड़न एक सच्चाई है। इन तीन देशों में अल्पसंख्यक तबके के लोगों को सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है कि वे अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान नहीं बनना चाहते हैं। CAA या CAB कानून उन तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर भारत आये ऐसे उत्पीड़ित विस्थापितों को सुरक्षा प्रदान करने का कानून है। इसलिए भारत पड़ोसी देशों से धार्मिक

उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को शरण दे रहा है तो विपक्ष को आपत्ती क्यों हो रही है। ऐसे में विपक्ष के हिंसक विरोध से साफ तौरपर यह संदेश जाता है कि प्रदर्शनकारियों को भारतीय संविधान के प्रति आस्था नहीं है। अर्थात् विपक्ष संविधान को बचा नहीं रहा है, बचाने का नाटक कर रहा है। यह विपक्ष का देशद्रोही हरकत नहीं तो और क्या है?

देश के सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषित कर दिया है कि वे अपने-अपने राज्य में CAA या CAB कानून लागू नहीं होने देंगे। ये सातों राज्य हैं-ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, कमलनाथ का मध्य प्रदेश, भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़, अमरेन्द्र सिंह का पंजाब, पी. विजयन का केरल और अरविन्द केजरीवाल का दिल्ली। ऐसा इसलिए कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, जो सरासर गलत है। बात यह है कि संविधान की सातवी अनुसूचि की प्रविष्टि 17 के अनुसार नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाना पूरी तरह से संघीय सरकार के अधिकार में आता है। विशुद्ध रूप से संघ के अधिकार की परिधि में आता है। संविधान के अनुसार देश के किसी भी राज्य के पास संघ द्वारा पारित कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सातों राज्यों के मुख्यमंत्री देशद्रोही हैं। इसलिए भारत सरकार को इन सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना चाहिए तथा चुनाव आयोग को इन सभी मुख्यमंत्रियों की पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। विपक्ष का नेता होने के कारण मोदी सरकार की आलोचना करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश की एकता, अखण्डता और

साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने के लिए राजनीति करना किसी तरह से उचित नहीं है। आखिर देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से कैसे देखा जा सकता है? यह दुखद है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेता की भूमिका मुसलमानों के बीच झूठ फैलाकर उनमें भय पैदा कर रहा है तथा उन्हें हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए न केवल प्रेरित कर रहा है बल्कि भरपूर सहयोग कर रहा है।

★ नागरिकता संशोधन बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है :- नागरिकता संशोधन बिल मुसलमान या किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। इसलिए इस बिल को लेकर मुसलमानों को जरा सा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे भारत के नागरिक हैं और भारत के ही नागरिक बने रहेंगे। यह नागरिकता छिनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का बिल है। इस बिल का किसी भी भारतीय नागरिक को कुछ भी नुकसान पहुंचाने से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो यह कहता है कि यदि आप आज नागरिक हैं तो कल से नागरिक नहीं माने जायेंगे। भारतीय नागरिकता कानून जस का तस है। भारतीय नागरिक पहले की तरह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्र हैं। नागरिकता संशोधन बिल भारतीय नागरिकों के अधिकारों को न तो निरस्त करता है और न ही कर सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इस बिल को लेकर औसत मुसलमान न तो चिंतित है और न ही डरा हुआ है बल्कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारतीय मुसलमानों में भ्रम फैलाकर डराया जा रहा है कि इस बिल के लागू हो जाने से उनकी नागरिकता खत्म हो जायेगी। अगर विपक्ष की दृष्टि में नागरिकता संशोधन बिल में भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खत्म किये जाने से संबंधित एक भी शब्द है तो इस बिल से उस शब्द को खोजकर जनता के सामने पेश करे। सच्चाई तो यह है कि भारतीय

मुसलमानों में भ्रम फैलाकर विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में देश के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को देशद्रोह के आरोप में तत्काल प्रभाव से विपक्षी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दिया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि विपक्ष देश की संप्रभुता तारतार कर देने पर आमदा है।

बांग्लादेश बनते समय जितने लोग भारत में आये, सभी को भारतीय नागरिकता मिली। बगैर हिन्दु-मुसलमान का भेदभाव किये। बावजूद इसके किसी भी तरह के उत्पीड़न के शिकार मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने के लिए मौजूदा कानून में केवल प्रावधान ही नहीं है बल्कि पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने 566 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। इसलिए नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष का यह प्रचार कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है तो सौ फिसदी झूठ है, भारत के धर्म निरपेक्ष साख को खोखला करता है। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, देश में रह रहा कोई भी मुसलमान भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करेगा तो उसपर खुले दिल से विचार किया जायेगा। इसका पुख्ता प्रमाण है गुजरात में पाकिस्तान से आयी महिला हसीना बेन। जिसे 19 दिसम्बर 2019 को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। वह मूल रूप से गुजरात की रहने वाली थी, जो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पति के मौत के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। हसीना बेन ने दो साल पहले ही भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दिया था।

यहां पर इस बात का का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पाकिस्तान के बलुचिस्तान में पाकिस्तान सरकार बलुचों पर भारी सितम ढ़ा रही है, पाकिस्तान सरकार द्वारा बलुचों का बेरहमी से उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा इसलिए की बलुच आत्म-निर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान धोखा देकर अवैध रूप से बलुचिस्तान पर कब्जा किये हुए है और वहां की प्राकृतिक संपदा का बुरी तरह से दोहन कर रहा है। इसलिए बलुचिस्तान, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। अतः बलुचिस्तान की समस्या को किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर किये जाने वाली उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

★ पूर्वोत्तर के राज्यों का भी नागरिक संशोधन बिल से कोई खतरा नहीं है :- पूर्वोत्तर

राज्यों की संस्कृति और पहचान बनी रहे, इसके लिए नागरिकता संसोधन बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके प्रावधानों को देश के कुछ हिस्से में लागू नहीं किया जायेगा। देश के ये हिस्से संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा विनियम 1873 के अंतर्गत 'इनर लाइन परमिट' वाले राज्य। छठी अनुसूचि में शामिल जनजाति क्षेत्र हैं-कार्बी अंगलोंग (असम), गारो हिल्स (मेघालय), चकमा जिला (मिजोरम) और त्रिपुरा के आदिवासी जिले। इनर लाइन परमिट भारतीय नागरिकों को अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड समेत कुछ क्षेत्रों में यात्रा को प्रतिबंधित करता है।

दरअसल, देश के सभी क्षेत्रों के लोग एक जैसे नहीं है। इसलिए सभी के ऊपर एक जैसा कानून लागू किया जाना न तो संभव है और न ही उचित है। ऐसा इसलिए कि उन्हें सुरक्षा देना और उनकी पहचान बनाये रखने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। यही वजह है कि

संविधान की पांचवी और छठी अनुसूचि में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसलिए देश के कुछ इलाके को स्वशासी बनाया गया है। यहां तक की देश के दूसरे क्षेत्र के नागरिकों को उन क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनके अपने नियम-कानून हैं। उन्हें अपनी परंपरा के मुताबिक नियम बनाने की आजादी है। संसद द्वारा बनाये गये कानून उन पर लागू नहीं होते है। दीवानी और फौजदारी विवादों में लागू होने वाले कानून उन पर लागू नहीं होते। नागरिकता संशोधन बिल में भी उनकी स्वायतता को सम्मान दिया गया है। यह जरूरी था, ताकि विशेष परंपराओं के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और बोल-चाल क्षेत्रों की विशेष पहचान को कायम रखा जा सके। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान की छठी अनुसूचि में शामिल होने के कारण मेघालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह त्रिपुरा का भी एक बड़ा हिस्सा इससे बचा रहेगा। असम के मूल निवासियों की रक्षा होगी। अरूणाचल प्रदेश में भी यह बिल लागू नहीं होगा। इसी तरह इनर लाइन परमिट से सुरक्षित नागालैंड और मिजोरम में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, पहचान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अब तो मोदी सरकार ने समिति बनायी है, जो असम समझौते के क्लॉज-6 के तहत सांस्कृतिक एवं सामजिक पहचान कर उनकी सभी चिंताओं को दूर करेगी। ●

(लेखक फायर एण्ड सेफ्टी विशेषज्ञ हैं।)
मो०:- 9334107607
वेबसाईट www.psfsm.in

शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं : डॉ. रणजीत

ज्ञान,कर्म,तपस्या,बलिदान एवं सम्पूर्ण विश्व मे लोकतंत्र की जननी के नाम से प्रख्यात वैशाली हमेशा से संघर्ष करती आ रही हैं और इस संघर्ष करने वाली धरती ने अनेको ऐसे सपूतों को जन्मा हैं जो कला के क्षेत्र में ,साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन एवं प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। हम वैशाली के देशरी जो कि एक छोटा मार्किट हैं वहाँ के एक शख्स की बात करेंगे जो विपत्ति के समय एक सपने को देखता हैं और उसे सच करने की कोशिश में जुट जाता हैं वह शख्सियत है देशरी के मिडिल क्लास की फैमिली से आने वाले श्री नारायण सिंह के पोते एवं रामटहल सिंह एवं महादेवी पटेल के पुत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा 2008 बैच के गुजरात कैडर डॉ रणजीत कुमार सिंह का। रणजीत बताते हैं कि उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई हैं। वे जब 6ठीं क्लास में थे तो जिले में पूरी तरह से बाढ़ आया हुआ था,सभी लोग डीएम को खोज रहे थे तब मैंने डीएम के बारे में दादाजी से जानकारी ली कि आखिर डीएम कैसे बना जाता हैं,उसका काम क्या हैं तभी से हमारे दिमाग मे इसका बीजारोपण शुरू हो गया। इस युवा ने अपनी सपना पूर्ण करने के बाद जोश तेवर एवं नए अंदाज में पारदर्शिता के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने की प्राथमिकता से विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके डॉ रणजीत फिलवक्त बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पदभार सम्भाल रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** ने **डॉ० रणजीत कुमार सिंह** से खास मुलाकात की। प्रस्तुत है इसके प्रमुख अंश:-

✯ आपने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया हैं?

मैं गुजरात कैडर का आईएएस हूँ वहाँ पर भी मैने लंबे समय तक कार्य किया हैं। बिहार में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के रूप में अपना योगदान देने के पश्चात फिलवक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार का पदभार सम्भाल रहा हूँ। बिहार मेरी मातृभूमि हैं और यहाँ काम करना मेरे लिए गर्व की बात हैं।

✯ जिले में कार्य करना एवं विभाग में कार्य करने में क्या अंतर महसूस कर रहे है?

जिले में जिलाधिकारी के रूप कार्य करते हुए सभी विभागों पर फोकस की जरूरत होती हैं वहाँ इम्पेलिटेंसन का कार्य होता हैं जबकि विभाग एक अलग होता हैं जहाँ पालिसी मेकिंग का कार्य होता हैं। दोनों की अपनी-अपनी एक्सपीरिएंस हैं लेकिन कोई भी युवा अफसर हमेशा फील्ड को ही पसंद करता हैं,फील्ड के बाद सचिवालय ताकि उसके अनुभव को आने वाले पदाधिकारी लाभ ले सके।

✯ बतौर प्राथमिक शिक्षा निदेशक बेहतरीन व्यवस्था के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप योजना, लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक के लिए स्कॉलरशिप इस माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा हैं। किचेन गार्डेन, वाल पेंटिंग,स्मार्ट क्लास, हाई स्कूल हर पंचायत में खोलने की योजना हैं ताकि बच्चे को दसवीं तक के लिए कहीं दूर जाना न पड़े। सेफ्टी सैटरडे के नाम से लोगो को प्रत्येक शनिवार आपदा से बचने के लिए तैयार किया जाता हैं, विभिन्न तरह की आपदा के बारे में जानकारी देकर उससे प्रभावित लोगों की कैसे मदद की जा सके, शुरुआत हो रही हैं।

✯ आपको नहीं लगता हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अतीत जितना गौरवशाली रहा हैं वर्तमान स्थिति उतनी भयावह होती जा रही हैं?

नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ हालांकि प्राइवेट स्कूल ज्यादा आये हैं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता हैं लेकिन बिहार की सरकारी शिक्षा वयस्था बेहतरीन रिजल्ट शुरू से देता आ रहा हैं एवं इसकी महत्ता आज भी बरकरार हैं।

✯ सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भी अभिभावक सरकारी शिक्षा व्यवस्था में अपने बच्चे को दाखिला नहीं लेना चाहते?

किसी भी सिस्टम के लिए सिर्फ सरकारी व्यवस्था सिर्फ दोषी नहीं माना जाना चाहिए। अभिभावक, बच्चे, विद्यालय समिति, शिक्षक सबकी रेस्पोंसबिलिटी बनती हैं कि किस तरह बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे। लोकल जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वह अपने स्तर पर सरकारी स्कूलों में बच्चे को भेजने के लिए जागरूक करे तथा स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखे। स्कूल किसी सरकार का नहीं बल्कि आप हम सबका हैं, हमारा देश का भविष्य उसी में पल रहा हैं इसलिए उसे कितना बेहतर बनाया जाए आपलोगो को भी सोचने की जरूरत हैं। डोर टू डोर मिशनरी ही पहुंचती हैं इसलिए लोगो को जागरूक करने में आपलोग अपनी कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल जो कृतिमान स्थापित करेगा उसपर गर्व महसूस करेंगे।

✯ बिहार के शिक्षकों के ऊपर शिक्षा देने के साथ-साथ अन्य कामो का भी बोझ रहता हैं,जिसकी वजह से वह मुख्य जवाबदेही निभाने में चूक रहे हैं?

शिक्षक का मुख्य काम शिक्षा देना ही हैं इसके अलावा छुट्टी के समय उनसे अलग कार्य लिया जाता हैं ताकि वह समाज के पढ़े-लिखे

जागरूक व्यक्ति होते हैं एवं उन्हें ग्रास रुट तक कि जानकारी होती हैं। शिक्षा ही उनकी प्राथमिकता हैं।

★ सम्मान काम एवं सम्मान वेतन की खाई की वजह से नए शिक्षक हमेशा धरना प्रदर्शन पर चले जाते हैं,जिसकी वजह से शिक्षा पर कितना असर पड़ता हैं?

पहले के टीचर कंपटेटिव एग्जाम के आते थे। अब नियोजित शिक्षक हैं, इनको भी हैवी सेलरी एवं प्रमोशन दिया जा रहा हैं। इन्हें शिक्षा पर फोकस करने की जरूरत हैं।

★ क्या आपको नहीं लगता कि निजी संस्थानों में फीस की लगातार बढ़ोतरी के बाद भी लोगो की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, अगर हाँ तो क्यो?

फीस पर सरकार नजर बनाए हुए हैं। आज निश्चित तौर पर लोगो मे परचेंजिग कैपेसिटी बढ़ी हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निजी संस्थाने 13 हजार के आसपास है जबकि उनके सामने हमारे 72 हजार संस्थान है एवं ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी व्यवस्था सरकारी शिक्षा पर ही निर्भर हैं। निजी संस्थाने बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। सरकारी वाला ही हर क्षेत्र में बाजी मार रहा हैं।

★ लोगो की पहली पसंद निजी संस्थान होने के बावजूद भी उन्हें ट्यूशन की जरूरत होती हैं,वैसे में सरकारी संस्थान अपनी नियमितता भी बरकरार नहीं रख पाता हैं तो छात्रों का भविष्य क्या होगा?

ट्यूशन को लेकर पेरेंट्स में एक देखा देखी की भावना जागृत हुई हैं,भले ही किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन सुबह शाम एक घण्टे ट्यूशन कराना ही बेहतर समझते हैं जो कि गलत हैं। जो बच्चा 6 घण्टे स्कूल में पढ़कर आता हैं ,उसे सेल्फ स्टडी की जरूरत हैं न कि ट्यूशन की क्योकि ट्यूशन तो केवल होमवर्क पूरा कराता है, एक घण्टे में सारे सब्जेक्ट घोलकर पिला नहीं सकता हैं। आजकल तो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हैं ,उसे उसी के स्कूल टीचर के माध्यम से ट्यूशन दिलाया जा रहा हैं ताकि बच्चे का नंबर स्कूल में अच्छा मिल सके,जिससे बच्चे का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ हैं। ट्यूशन पूरी तरह बच्चे को बर्बाद कर रहा हैं।

★ बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति क्या हैं,क्या उनकीं कमी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहा हैं?

94 हजार शिक्षकों का नियोजन प्रोसेस में हैं,अब शिक्षकों की कोई कमी नहीं रहेगी।

★ जहाँ भी गए सुर्खियों में रहे,शिक्षा विभाग में ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे आपको सदियों तक याद रखा जा सके?

शिक्षा ही एक मात्र साधन हैं जिससे सबकुछ सम्भव हैं इसलिए इसपर हमारा विशेष फोकस हैं।प्राइमरी स्कूल में शिष्य गुरु की परंपरा चलती रहे, गुरु दिन रात छात्रों के भविष्य की सोचे एवं वही रेस्पेक्ट बच्चे के अंदर भी बरकरार रहे। मैं अभिभावकों से बताना चाहूंगा कि आपके पास धन रहे या न रहे, सबकुछ बेच दीजिये लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनावे। बच्चे को ससमय स्कूल भेजे एवं टीचर भी ससमय उपस्थित रहे। जितने भी प्रकार की स्कीम चलाई जा रही हैं सभी का लाभ ले। गार्डेनिग,कम्युनिटी किचेन की भी शुरुआत कर दी गई हैं। बच्चे यूनिफार्म में रहे, स्कूलों का निरीक्षण ,उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके उनके अभिभावकों को, विद्यालय विकास समिति एवं लोकल जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए क्योंकि यही बच्चा 15 साल बाद देश का नेतृत्व करेगा।

★ लोगो को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे ताकि वह अपने बच्चे का दाखिला मोटी रकम वसूल करने वाली निजी संस्थान में न कराकर बल्कि सरकार द्वारा मुफ्त में चलाई जा रही शिक्षा का लाभ ले सके?

एकलब्य का कोई गुरु नहीं था, जंगल में भी रहकर वह सभी विद्याओं में निपुण हो गया था। टीचर ,पेरेंट्स एवं बच्चे में काफी अच्छा समन्वय होना चाहिए। मैं भी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल से ग्रहण किया हूँ, आजतक प्राइवेट स्कूल नहीं गया। निजी एवं सरकारी स्कूल में बस मात्र एक ही अंतर हैं वह इंग्लिश भाषा का। इंग्लिश में कमजोर बच्चे अपने आप को हीन भावना से देखते हैं जो कि कतई सही नहीं हैं। हमारे देश की मातृभाषा हिंदी ही हैं इसलिए भाषा को समस्या न समझे लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी पर पूरी फोकस के साथ पढ़े। सरकारी विद्यालय के ही अधिकतर बच्चे आईएएस, आईपीएस बनते आ रहे हैं जो कि सार्वभौमिक सत्य हैं।

★ ऐसी चर्चा आम हैं कि अधिकतर शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जाते एवं कुछ नियमित भी नहीं रहते वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वह ससमय उपस्थित रहे।

मैं डीएम सीतामढ़ी था तो 150 शिक्षकों को सस्पेंड किया था। जो शिक्षक समय पर नहीं आते हैं उन्हें दंडित किया जाता हैं,फिर थोड़े समय बाद उन्हें रिलीज किया जाता हैं ताकि दण्डित होने के पश्चात अपनी आदत सुधार लें अगर उसके बाद भी कुछ लोग के आदत में सुधार नहीं होता हैं तो फिर आगे की करवाई जारी कर दी जाती हैं। मैं अभिभावकों से आग्रह करूँगा की बच्चे ही आपके असली सम्पति हैं उन्हें शिक्षा के समान अवसर देने चाहिए,बाल विवाह से बचें एवं बच्चियों को पढ़ने का मौका दे। मैं कई बार देखा हूँ की 12जी टॉपर के बाद लड़की की शादी करा दी जाती हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं,मैं मानता हूं कि कम से कम 25 साल में शादी करे ताकि आपकी लड़की एडुकेटेड होकर जॉब करने लगेगी तो तमाम तरह की समस्याओं का समाधान सम्भव हैं ।

श्रद्धांजलि

इंटक बिहार के वरीय प्रदेश महामंत्री डी. राम जी का निधन दिनांक 28/12/2019 को हो गया। स्व० राम साहब विगत 40 वर्षों से सक्रिय रूप से श्रम आन्दोलन से जुड़े रहे और उनके निधन से पूरा श्रम जगत शोकाकुल है। केवल सच पत्रिका परिवार स्व० डी. राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

कानून तोड़ने वालों पर कठोरतम कार्रवाई तय : तरनजोत

आईएएस की प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि हर युवाओ की सपना आईएएस बनने का होता हैं,वह उसके तैयारी में जी तोड़ मेहनत करता हैं,हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होते हैं लेकिन उसमें पॉइंट में ही बच्चे सफल हो पाते हैं। उन्ही सफल एक युवा की आज हम बात करेंगे जो लुधियाना पंजाब के मूल निवासी 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तरनजोत सिंह की। दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में योगदान के साथ ही बड़ी चुनौतियों से जूझते हुए राजधानी की विधि व्यवस्था के साथ-साथ भ्रष्ट डीलरों पर नकेल कसते हुए लोगो के बीच विशिष्ट पहचान स्थापित करने में सफल तरनजोत सिंह के साथ पत्रिका प्रतिनिधि **श्रीधर पाण्डेय** एवं **त्रिलोकीनाथ प्रसाद** की संक्षिप्त रिपोर्ट:-

बातचीत के क्रम में तरनजोत ने बताया कि उसकी प्राथमिक शिक्षा लुधियाना में ही हुई हैं। घर परिवार के सदस्य की हार्दिक इच्छा थी कि वे भी डॉक्टर बनकर क्योकि माता पिताजी एवं बहन तीनो ही मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन तरनजोत सिंह की सपना इंजीनियर बनने का था और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी रुड़की से की उसके बाद ओएनजीसी में बतौर इंजीनियर अपनी सेवा देने लगे। सेवा के साथ साथ सिविल सर्विसेज के प्रति रुचि भी बढ़ने लगी और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी, लगातार मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ न लग रहीं थी फिर भी श्री सिंह ने हिम्मत नहीं छोड़ा और तीसरी अटेम्प में आईएएस क्लियर कर गए। तरनजोत आगे बताते हैं कि बिहार सरकार यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, कल्चर अलग अलग हैं। ट्रेनिंग के दौरान भागलपुर में श्रावणी मेला को काफी करीब से समझने का मौका मिला। बिहार कल्चरी काफी रिच हैं, बोधगया, राजगीर, पटना साहिब का नाम तो पहले से ही सुना था क्योकि उसके इतिहास काफी पढ़े थे, लेकिन यहाँ काम के दौरान काफी कुछ सीखने एवं समझने को मिले। इसी बीच बिहार के महापर्व छठ को भी करीब से देखा। यहाँ सेवा के अच्छे अवसर हैं बिना कोई डर दबाव के काम करने की जो आजादी हैं वह काबिले तारीफ हैं।

दानापुर एसडीएम के पदभार सम्भालते ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय राजधानी में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी, बात-बात पर रोड जाम की समस्या देखने को मिलने लगी। दानापुर अनुमंडल मिश्रित होने के कारण इधर अभी डवलपमेन्ट के कार्य ज्यादा चल रहे हैं, छोटे-छोटे समस्याओं को सुन तत्काल करवाई कर देने से लोगो को प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ जाता हैं। जमीनी विवाद सम्बन्धीत भी समस्या यहाँ देखने को मिलते है, शहरी इलाकों में जमीनी रेट ज्यादा होने की वजह से आपसी रंजिस देखने को मिल जाते हैं, उनलोगों के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश हैं कि कानून को तोड़कर कोई भी बच नहीं सकता, दबंगो पर करवाई निश्चित तौर पर होगी। अपनी ट्रेनिंग के याद को ताजा करते हुए आगे बताते हैं कि ट्रेनिंग में हर एक विभाग से सम्बंधित चीजो की जानकारी दिलाया जाता हैं ताकि आगे के कार्यो को उसी के अनुरूप करना होता हैं तत्पश्चात अंचल में पदस्थापित किया जाता हैं, जहाँ हर पहलू को देखने को मिलते हैं। गौतमबुद्ध को अपना आदर्श मानने वाले तरनजोत सिंह खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें गौतमबुद्ध की ही धरती पर कार्य करने का मौका मिला हैं,उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध अष्टांग मार्ग की फॉलोशोपी से बहुत कुछ सीखने एवं समझने को मिला हैं और आज की रोजमर्रा की जिंदगी में उनके एक-एक वाक्य काम आते हैं। यूपीएससी के तैयारी करने वालो छात्रों के सन्देश देते हुए तरनजोत सिंह ने बताया कि हर जॉब में मेहनत की जरूरत होती हैं, शार्टकॉर्ट की चकर में न पड़े खूब मेहनत करें, और अच्छे गाइडर एवं अच्छी बुक उनको सफलता के करीब पहुँचाएगी, मेरी शुभकामनाएं हैं।

केवल सच पत्रिका के माध्यम से लोगो को अपील करते हुए बताया कि प्रशासन उनकी हेल्प के लिए हमेशा से तैयार हैं आपसी समन्वय बनाकर रहे उनके आवेदन पर त्वरित समाधान होगा वही भ्रष्टाचार में लिप्त डीलरों को स्पष्ट सन्देश देते हुए कहा कि अगर डीलरों में अनियमितता की शिकायत मिलती हैं तो उनपर निश्चित तौर पर करवाई होगी, कुछ डीलरों पर करवाई हो चुकी हैं इसलिए सही तरीके सही दाम पर लाभुकों तक

आर्यभट्ट के अवतार थे डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

● ललन कुमार प्रसाद

आर्यभट्ट के अवतार और बिहार के आइंस्टीन तथा अपने गांव के वैज्ञानिक बाबू कहे जाने वाले दुनियां के महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1942 को आरा से 12 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल बहादूर सिंह और माता का नाम लहासो देवी है। वशिष्ठ बाबू के जन्म के समय उनके पिता सिपाही के पद पर कार्यरत्त थें। वशिष्ठ बाबू तीन भाईयों एवं दो बहनों में सबसे बड़े थे। उनके दोनो छोटे भाईयों का नाम अयोध्या नारायण सिंह उर्फ किशुन सिंह और हरिशचंद्र नारायण सिंह है तथा छोटी बहनों का नाम सीता देवी और मीरा कुंवर है। पांचवी कक्षा तक उनकी पढ़ाई बसंतपुर गांव में हुई थी। वशिष्ठ बाबू के प्रतिभा की पहचान सर्वप्रथम उनके पैतृक गांव के उसी स्कूल के एक मास्टर साहब को हुई थी, जिस स्कूल में पांचवी कक्षा तक वशिष्ठ बाबू ने पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे नेतरहाट चले गये, जहां 1957 में छठी कक्षा में दाखिला लिया और 1963 तक वही पढ़ते रहे। 1963 में हायर सेकेन्ड्री तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी साल पटना के सायंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई हेतु दाखिला लिया।

8 सितम्बर 1965 को वशिष्ठ बाबू ने कैलिफोर्निया (अमेरिका) के बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला लिया। 1966 में उन्हे अमेरिका की अंतरीक्ष एजेंसी नासा में काम करने का मौका मिला। 1967 में कोलंबिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स के निदेशक बने, तब उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। वशिष्ठ बाबू ने 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एण्ड ऑपरेर्टस विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर 1969 में पीएचडी की, जो गणित की दुनियां में तहलका मचा दिया। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू के शोध का विषय जितना जटिल व कठिन था, उतना ही रहस्यपूर्ण था। इसलिए बर्कले युनिवर्सिटी ने उन्हें 'जिनियसो का जिनियस' की उपाधि से नवाजा। पीएचडी करने के बाद 1969 में ही वे वाशिंगटन युनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बने। वशिष्ठ बाबू 1971 में भारत लौट आये और अपने साथ दस बक्सा किताबे ले आये। भारत आने पर आईआईटी कानपुर में प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किया। वहां पर उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने बॉम्बे आईआईटी का रूख किया। बाद में टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच (ट्रांबे) के साथ जुड़ गये। वे टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच तथा स्टैटिक्स इंस्टीच्यूट के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे।

अशोक राजपथ स्थित कुल्हड़िया अर्पाटमेंट के उनके फ्लैट में अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह में वशिष्ठ बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे अपने फ्लैट में ही चक्कर खाकर गिर पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल के आइसीयू में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह के इलाज के बाद ठीक होकर अपने फ्लैट वापस लौट आये। 14 नवम्बर 2019 को सुबह 8 बजे वशिष्ठ बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुरंत उनके मझले भाई अयोध्या नारायण सिंह और भतीजे मुकेश सिंह तथा राकेश सिंह इलाज कराने के लिए पीएमसीएच इमरजेंसी में ले आये, जहां डॉक्टरों ने ईसीजी सहित अन्य जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय सुबह के साढ़े आठ बज रहे थे।

☆ **वशिष्ठ बाबू सच्चे देशभक्त थे :-** वशिष्ठ बाबू को अमेरिका में न पैसे की कमी थी और न बड़े ओहदे की। ऐसा इसलिए की वे अमेरिका

की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, कोलम्बिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स और वाशिंगटन युनिवर्सिटी में उच्च पदों की शोभा बढ़ा चुके थे। कैलिफोर्निया के बर्कले युनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष डॉ० केली अपनी इकलौती बेटी की शादी वशिष्ठ बाबू से करने को तैयार थे। इसके लिए डॉ० केली ने पटना सायंस कॉलेज के तत्कालिन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ के द्वारा वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह को राजी करने का अनुरोध कराया था और प्राचार्य नगेन्द्र नाथ ने उनकी ओर से पैरवी भी की थी। अगर वशिष्ठ बाबू अमेरिका में बस जाते तो नोबेल पुरस्कार सहित न जाने दुनियां के कितने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे जाते। सारी दुनियां में उनका गुणगान होता रहता, लेकिन देश प्रेम में वशिष्ठ बाबू ने सबकुछ ठुकरा दिया। वे अपने देश की सेवा करना चाहते थे। विदेशों की ऐशो-आराम के बजाय देश के लिए जिना और देश के लिए मरना पसंद था। वे चाहते थे कि देश में वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी में अपना योगदान देना चाहते थे। ऐसा इसलिए कि, जो देश विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता है, वह देश उतना ही खुशहाल और सुखी-समृद्ध होता है। इसलिए डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह 1971 में भारत लौट आये।

✯ लाल बहादूर सिंह बेटे के मोह से ऊपर न उठ सके :- हमारे समाज में मान्यता है, यदि पुत्र शादी नहीं करेगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन वशिष्ठ बाबू तीन भाईयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए यदि उनके पिता वशिष्ठ बाबू पर शादी करने का दबाव नहीं भी बनाते तो भी उनका वंश आगे चलता ही, बढ़ता ही। लेकिन, वशिष्ठ बाबू के लिए पिता का भारी दबाव से उभर पाना मुश्किल था। ऐसा ही सबके साथ होता है। भले ही कोई भगवान महावीर और जगतगुरू शंकराचार्य की तरह अपवाद निकल जाये तो बात दूसरी है। भगवान महावीर और जगत गुरू शंकराचार्य तथा आज के स्वामी रामदेव हम सभी को बहुत प्रिय लगते हैं। सभी कहते हैं कि इनके माता-पिता ने देश और समाज के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन जब यह बात अपने पर आती है तो सभी मुकर जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में डबल स्टैण्डर्ड अपनाते हैं। दूसरे का बेटा सन्यासी बने तो बहुत अच्छा लेकिन अपना बेटा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। लाल बहादूर सिंह बेटे का मोह नहीं त्याग सके, जबकि तीन बेटे और दो बेटियों में से एक बेटे का मोह देश का नाम रौशन करने के लिए मानवता की महत्ती सेवा करने के लिए त्यागा जाना चाहिए था। अगर लाल बहादूर सिंह ऐसा कर पाते तो बेटे के साथ वह भी अमर हो जाते। बेहद प्रखर बुद्धि का होने के साथ-साथ वशिष्ठ बाबू का रंग-रूप, कद-काठी बहुत ही आकर्षक था। इसलिए प्रोफेसर जॉन एल. केरी वशिष्ठ बाबू को अपना दामाद बनाना चाहते थे। फिर उनकी इकलौती बेटी को वशिष्ठ बाबू से प्रेम हो गया था। उन्होंने वशिष्ठ बाबू को शादी का प्रस्ताव दिया था। वशिष्ठ बाबू डॉ० केली की बेटी से शादी के प्रस्ताव को मानने के लिए सहमत भी हो गये थे, लेकिन डॉ० केली की शर्त थी की वशिष्ठ बाबू अमेरिका में ही बस जाये। लेकिन वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह नहीं राजी हुए। वशिष्ठ बाबू ने भी डॉ० केली के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए की मुझे अपने देश भारत जाना है। देश की सेवा करनी है। अपने देश के लिए जीना और मरना है। इसलिए 1971 में वशिष्ठ बाबू वापस भारत लौट आये। यदि वशिष्ठ बाबू डॉ० केली की बेटी से शादी कर अमेरिका में बस जाते तो उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में ही नोबेल प्राइज मिल गया होता और जाने-माने यूरोपीय गणितज्ञ के मार्गदर्शन में वे दुनियां के सबसे बड़े गणितज्ञ बन गये होते। अगर वशिष्ठ बाबू देश प्रेम से ऊपर उठकर पूरी मानव जाति के हित की बात सोचते तो पूरे विश्व में अपने समय के महानत्तम गणितज्ञ के रूप में उनकी तूती बोलती। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सायंस कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य गणितज्ञ डॉ० के.के. झा और बिहार के महान गणितज्ञ डॉ० के.सी. सिन्हा का भी यही मत है।

✯ आज के बिहार में प्रतिभाओं की कद्र बिल्कुल नहीं है :- प्राचीन बिहार में जितनी प्रतिभाओं की कद्र की जाती थी, उतनी विश्व में कही भी नहीं की जाती थी। यही कारण है कि विश्व के पांच प्राचीन विश्वविद्यालयों में से चार बिहार में थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार से बाहर था, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। बिहार के ये चारो विश्वविद्यालय थे-नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों में पूरी दुनियां

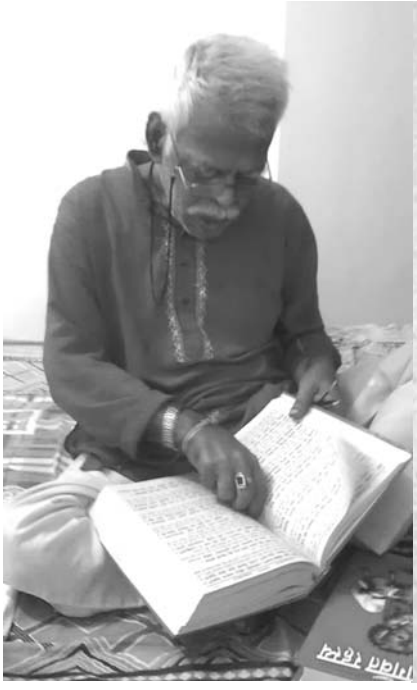

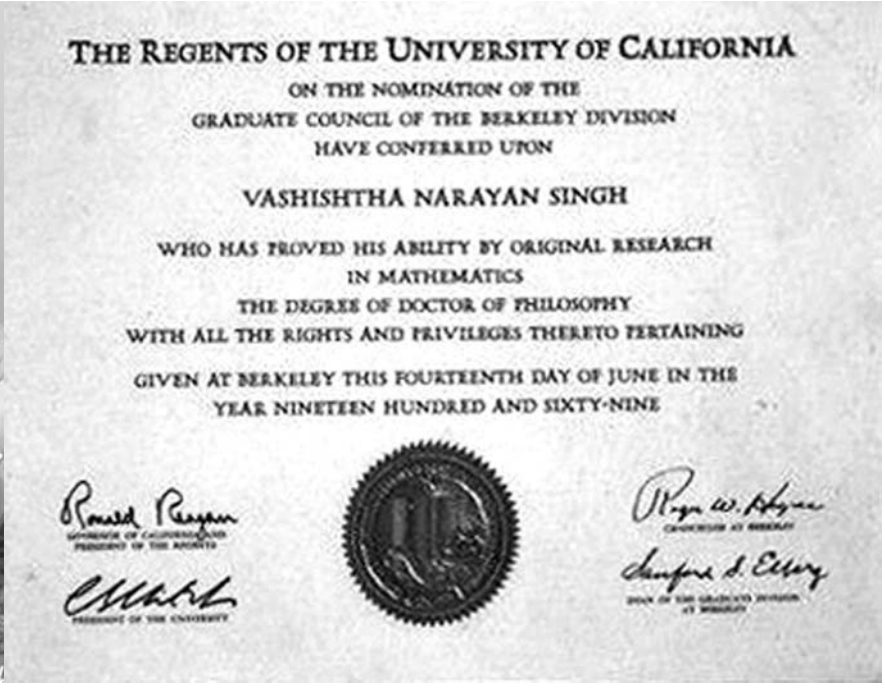

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
ON THE NOMINATION OF THE
GRADUATE COUNCIL OF THE BERKELEY DIVISION
HAVE CONFERRED UPON
VASHISHTHA NARAYAN SINGH
WHO HAS PROVED HIS ABILITY BY ORIGINAL RESEARCH
IN MATHEMATICS
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
WITH ALL THE RIGHTS AND PRIVILEGES THERETO PERTAINING
GIVEN AT BERKELEY THIS FOURTEENTH DAY OF JUNE IN THE
YEAR NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-NINE

से लोग पढ़ने-पढ़ाने आया करते थे। इसका सटिक उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय। जहां पूरी दुनियां से लोग पढ़ने-पढ़ाने के लिए आया करते थे। यहां के विद्वानों की विद्वता की तूती पूरी दुनियां के सिर चढ़ बोलती थी। आर्यभट्ट हो या आचार्य चाणक्य, महर्षी पतंजलि हो या बराहमिहिर, विश्व प्रसिद्ध वैध जीवक हो या वात्सायन, इन सबका लोहा पूरी दुनियां मानती थी। अब तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कद्र नहीं है। इस दृष्टि से बिहार पूरे भारत में शीर्ष पर है, इसलिए आज बिहार की गिनती देश के पिछड़े राज्यों में की जाती है। यही कारण है कि 60-65 साल पहले तक एशिया का ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली पटना युनिवर्सिटी को देश के नैक ग्रेडिंग में A++ के बजाये B+ मिला है। पटना युनिवर्सिटी के कैमेस्ट्री विभाग में प्रोफेसर और हेड तथा नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ० रॉबिनसन के गुरू भाई डॉ० ज्ञानचंद चटर्जी (डॉ० जे.एन. चटर्जी) के ज्ञान का उपयोग बिहार सरकार नहीं कर सकी। बिहार सरकार की उपेक्षा के चलते बिहारवासी उनके ज्ञान का पूरा लाभ नहीं उठा सके। उन्हें रिर्सच करने हेतु बिहार सरकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी, वरना वे भी नोबेल पुरस्कार विजेता होते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह बिहार के जाने-माने केमेस्ट्री के विद्वान प्रोफेसरों का मत है। आज बिहार में बिहार सरकार द्वारा विद्वानों की कितनी उपेक्षा की जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह है, जिनका निधन 14 नवम्बर 2019 को हो गया। उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष सात महीने थी। वे जीवन के अंतिम 45 वर्षों में मानसिक बिमारी सिजोफ्रेमिया से पीड़ित रहे। अर्थात् भारी कष्टपूर्ण जीवन जीये।

यह कहना गलत है कि वशिष्ठ बाबू जितना पितृ भक्त थे, उतना मातृ भक्त नहीं थे। सच तो यह है कि वे बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति थे। वे किसी की बात भले ही टाल दें, पर माँ लहासो देवी की बात नहीं टालते थे। मसलन, 2 अप्रैल 2012 की घटना को ही ले लीजिए। भोजपुर के प्रसिद्ध बखोरापुर काली मंदिर के परिसर में बनाया गया शिव मंदिर जब बनकर तैयार हो गया तो मंदिर के संरक्षक सुनील सिंह गोपाल चाहते थे कि उसका उद्घाटन भोजपुर की शान महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह करे। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ वशिष्ठ बाबू से सम्पर्क किया। दो दिनों तक अनुनय-विनय करते रहे, लेकिन वशिष्ठ बाबू राजी नहीं हुए। तब स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके माँ के पास जाकर कहे कि वशिष्ठ बाबू मंदिर का उद्घाटन कर दे। माँ के कहने पर वशिष्ठ बाबू ने फिता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। उसके साथ ही माँ काली सांस्कृतिक महोत्सव 2012 का शुभारंभ भी हुआ।

पता नहीं वशिष्ठ बाबू को खैनी खाने की लत कब और कैसे लग गयी, लेकिन रंगकर्मी संजय शाश्वत बताते हैं कि वशिष्ठ बाबू खैनी खाने के शौकीन थे। वे बसंतपुर गांव या पटना में रहने के दौरान चाय पीने के बाद खैनी की डिमांड करते थे। जब उन्हें खैनी खाने की तलब होती थी तो आसपास में उम्र में बड़े हो या छोटे किसी को भी कह देते थे कि 'भईया तनी खइनी खिलाव'। संजय बताते हैं चाय और खैनी के सेवन के बाद उनका मूड फ्रेश हो जाता था।

वशिष्ठ बाबू न कवि थे और ना ही उन्हे कविता लिखने का शौक था। फिर भी उन्होंने दो-चार कविताएं लिखी है। उनकी एक कविता दी जा रही है, जो इस प्रकार

है-

''हम क्या थे और क्या हो गये
दुनियां चलती जाती है
हम भी घुलते-मिलते हैं
दुनियां में मैंने जितनो को देखा
सबकी नजरें टेढ़ी हैं।
तुम क्या करना चाहते थे
और क्या हो गया
हे भगवान रक्षा करो।
अब रक्षा करो भगवान रक्षा करो
यह दुनियां तुम्हारी है।
इस दुनियां में हम कुछ भी नहीं है
तुम गणितज्ञ हो, तुम महान हो।
तुम प्रोफेसर हो, तुम भाग्यवान हो
अब मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता।
अगर तुम ही नहीं हो तो हम भी नहीं हैं।'

★ बेमेल शादी का वशिष्ठ बाबू के दिमागी हालत पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा :- डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह पितृ भक्त थे। नहीं चाहते हुए भी पिता के कहने पर वह शादी करने के लिए राजी हो गयें। गणित में बेहद लगाव के चलते ही उनकी बारात निकलने में देर रात हो गयी थी। दरअसल, बारात कूच करने के लिए तैयार थी, उस समय भी वे गणित के सूत्रों की पढ़ाई में मग्न थे। बारात निकलने के समय भी वे कमरे का दरवाजा बंद कर पढ़ाई में व्यस्त थे, जिसके कारण बारात देर रात में लड़की वाले के दरवाजे लगी। 8 जुलाई 1973 को छपरा जिला के सदर प्रखंड के खलपुरा गांव के निवासी एम.बी. बी.एस. डॉ० दीपनारायण सिंह की दूसरी बेटी पी. एच.डी. डॉ० वंदना सिंह से हुई। उस समय वशिष्ठ बाबू की उम्र 31 वर्ष थी। शादी के समय वशिष्ठ बाबू की ख्याति दुनियां के महान गणितज्ञ के रूप में सुमार हो चुकी थी। इसलिए शादी के दौरान उनको देखने के लिए छपरा के लगभग सभी कॉलेजों के प्रोफसर और जिला के नामी-गिरामी लोग पहुंचे थे, लेकिन वशिष्ठ बाबू का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। वशिष्ठ बाबू के छोटे भाई हरिशचंद नारायण सिंह बताते हैं कि शादी के तुरंत बाद से ही भैया का व्यवहार बदलने लगा था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक डॉ० वंदना सिंह करीब साढ़े पांच महीने तक ही वशिष्ठ बाबू के साथ रही। अर्थात् मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आती-जाती रही। बाद में वशिष्ठ बाबू के छोड़कर मायके में अपने माता-पिता के पास चली गई। जिसका वशिष्ठ बाबू की दिमागी हालात पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ा। जनवरी 1974 में वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये। वर्ष 1975 में पत्नी से उनका

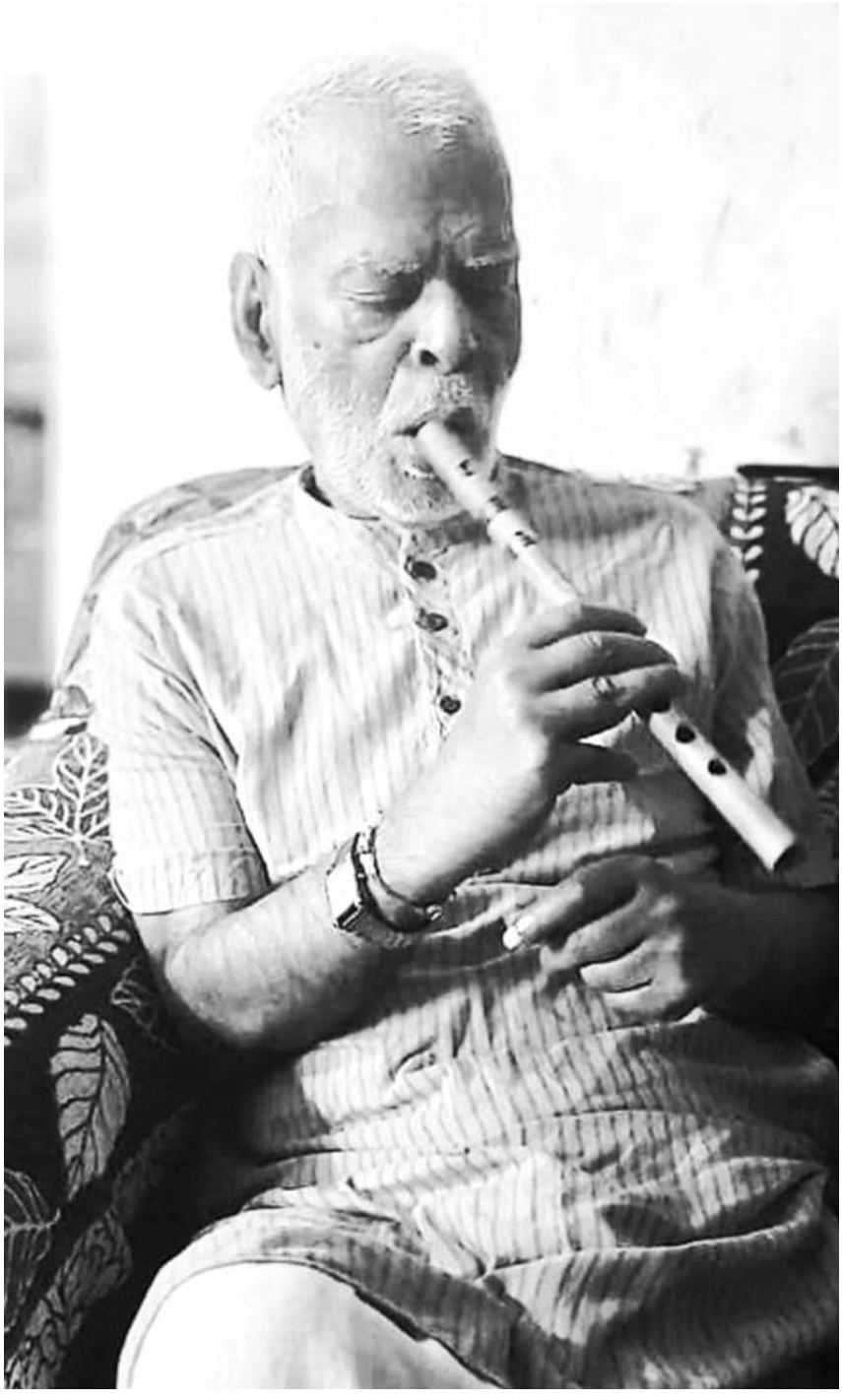

तलाक हो गया। वर्ष 1976 में उनके घरवालों ने उनका इलाज कराने के लिए उन्हें राँची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित कांके मेंटल हॉस्पीटल में भर्ती करवाया। सरकारी संस्थान होने के चलते वशिष्ठ बाबू वहां उपेक्षित रहे। उपेक्षा का कारण गरीब परिवार से जुड़ा होना भी था। इसलिए उनका उचित इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गयी। 1978 में वशिष्ठ बाबू का इलाज सरकारी खर्च पर शुरू हुआ। जून 1980 में उनके इलाज हेतु सरकार द्वारा पैसा देना बंद कर दिया गया। उसके बाद इलाज के लिए पैसा नहीं रहने के कारण 1982 में कांके के एक प्राइवेट हॉस्पीटल 'डेविड हॉस्पीटल' में हॉस्पीटल के प्रबंधकों द्वारा बंधक बना लिये गये थे।

अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते वशिष्ठ बाबू अपने सगे-संबंधियों तथा जात-बिरादरी

के लोगों में बहुत ही मशहूर हो गये थे। उनकी जाति-बिरादरी के लोग चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी प्रकार वशिष्ठ बाबू से हो जाये। एक से बढ़कर धनी तथा प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ते आने लगे। हालांकि वशिष्ठ बाबू के पिता लाल बहादूर सिंह उन्हें बहुत प्रेम करते थे। दोनो बैठकर आपस में घंटों बात किया करते थे। बावजूद इसके लाल बहादूर सिंह ने बेटे की शादी एक गरीब परिवार में करने के बजाय एक धनी तथा तथाकथित प्रतिष्ठित परिवार के बहुत ही पढ़ी-लिखी लड़की से कर दी। लाल बहादूर सिंह से यह बहुत बड़ी चूक हो गयी जो बाद में वशिष्ठ बाबू के लिए घातक सिद्ध हुई। वशिष्ठ बाबू के सास-ससुर प्रतिभा को संरक्षण देने के बजाय अपने घमंड की तुष्टी हेतु दिखावे को तरजीह देने लगे। ससुराल वाले चाहते थे, समाज के गणमान्य व्यक्ति द्वारा आमंत्रित भोज में वे उनकी बेटी के साथ जाकर सिरकत करे और मेजबान के परिवार के साथ गपशप में अच्छा-खासा समय दे। उनके यहाँ प्रतिष्ठित परिवार के लोग आये और बेटी दामाद आगंतुकों के साथ मेल-जोल, बातचीत करने में पर्याप्त समय दे। बेटी-दामाद देश के दर्शनीय तथा ऐतिहासिक स्थलों का खूब भ्रमण करे। वशिष्ठ बाबू को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ऐसे कार्यों में समय की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। वैसे कार्यों में समय लगाने के बजाय पढ़ाई में अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, जिससे की दुनियां में उनके देश का नाम रौशन हो। दरअसल, घर और खासकर उनके ससुराल वालों के समाज में बड़ा दिखाने की प्रवृति ने वशिष्ठ बाबू को बिल्कुल असहज बना दिया। इस कारण वशिष्ठ बाबू की तबीयत बिगड़ी और जनवरी 2014 में उन्हें मानसिक दौड़ा पड़ा। अर्थात् वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये। जाँच के बाद पता चला कि वशिष्ठ बाबू सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बिमारी से ग्रसित हो गये हैं। पटना सायंस कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य और गणितज्ञ डॉ० के.के. झा के अनुसार ऐसा कुछ बताते हैं कि वशिष्ठ बाबू के रिर्सच वर्क की चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान थे। इसका भी प्रतिकूल असर वशिष्ठ बाबू के दिमागी हालात पर पड़ा।

8 अगस्त 1989 को वशिष्ठ बाबू के भाई अयोध्या नारायण सिंह, जो सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत्त थे, वशिष्ठ बाबू का इलाज कराने हेतु पूना के मिलिट्री हॉस्पीटल भर्ती कराने के लिए आरा से ट्रेन से ले जा रहे थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के गढ़वारा रेलवे स्टेशन पर रात में बुक स्टॉल की दुकान देखकर वशिष्ठ बाबू ट्रेन से उतर गये। उस दौरान ट्रेन में उनके छोटे भाई अयोध्या नारायण सिंह, उनकी पत्नी और बेटी सो रही थी। ट्रेन खुल गई और वशिष्ठ बाबू वही रेलवे प्लेटफॉर्म पर छुट गये। गढ़वारा रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकलते समय कुछ रेलवे कर्मचारियों और टिकट निरीक्षकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उस समय वशिष्ठ बाबू द्वारा लगभग 30 मिनट तक अंग्रेजी में स्पीच देते देख सभी रेलवे कर्मचारी सहम गये और स्टेशन परिसर से बाहर चले गये। फिर वशिष्ठ बाबू कहां गुम हो गये, पता नहीं चला।

4 साल से लापता वशिष्ठ बाबू संयोग से 9 फरवरी 1993 को भिखारी की भेष-भूषा में छपरा के डोरीगंज बाजार में एक झोपड़ीनुमा होटल के बाहर फेंके गये जूठन में खाना तरासते मिले। उस समय उनके शरीर पर मैला फटा कपड़ा था तथा वे नंगे पांव थे। उनकी दाढ़ी-मूंछे बढ़ी हुई थी और सर का बाल भी बढ़ा हुआ बेतरतीब था। शरीर भी धूल-धूसरित था। दुनियां के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ की ऐसी अति दयनीय और दर्दनाक दशा! चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए बिहारवासियों को, केन्द्र सरकार को और खासकर बिहार सरकार को। जिसके मुखिया नीतीश बाबू पिछले 14 वर्षों से लगातार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं, जो इंटर तक पटना सायंस कॉलेज के छात्र रहे और उसके बाद पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की तथा उन्होंने बिहार के विकास के लिए पिछले सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले सबसे अधिक काम किया है।

वशिष्ठ बाबू को खोजने का श्रेय उनके गांव बसंतपुर के ही कमलेश राम और भोरिक राम उर्फ सुदामा राम को जाता है। ये दोनो भोरिक राम की बेटी की बिदाई के लिए पलंग तथा अन्य फर्नीचर खरिदने हेतु डोरीगंज बाजार आये थे। इन दोनो ने ही अपने गांव के वैज्ञानिक चाचा यानि महान गणितज्ञ डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह को पहचाना और उनके घरवालों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही घर वाले नाव से तुरंत आरा से डोरीगंज बाजार पहुंचे और देखते ही वशिष्ठ

बाबू को पहचान लिया। घरवालों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुरंत उनकी दाढ़ी बनवाई और सर का बाल कटवाया। उसके बाद उन्हें नहला-धुलाकर नया वस्त्र पहनाया और तब उनको लेकर वापस पैतृक गांव बसंतपुर लौट आये।

डॉ० वशिष्ठ नारायण की चार वर्षों की गुमनामी के बाद उनके मिलने की पहली खबर 9 फरवरी 1993 को राष्ट्रीय सहारा में छपी थी। 11 फरवरी 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने सहयोगी श्रममंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ उनसे मिलने बसंतपुर गांव आये थे। उनकी अति दयनीय हालत देखकर मुख्यमंत्री इतने भावुक हो गये कि उन्होंने कहा कि बिहार को बंधक रखना पड़े तो रखेंगे, लेकिन इस महान गणितज्ञ का इलाज विदेश तक करायेंगे। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू की विलक्षण प्रतिभा से लालू प्रसाद अच्छी तरह वाकिब थे। बात यह है कि छात्र जीवन में वह वशिष्ठ बाबू से दो-तीन साल जुनियर थे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के निर्देश पर श्रम मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह खुद वशिष्ठ बाबू को लेकर बैंगलुरू के निम्हांस हॉस्पीटल में भर्ती कराने गये थे। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोइली से सम्पर्क कर गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू के इलाज की समुचित व्यवस्था करायी और कई दिनों तक वशिष्ठ बाबू के साथ हॉस्पीटल में भी रहे। दरअसल, तत्कालीन श्रम मंत्री वशिष्ठ नारायण सिंह (आज के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष) और महान गणितज्ञ एक ही क्षेत्र से आते हैं। इस नाते प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह से खास लगाव था। वहां 1993 से 1997 तक वशिष्ठ बाबू का सरकारी खर्च पर सघन इलाज चला। जिससे उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। लेकिन लालू सरकार ने आगे के इलाज हेतु पैसा देना बंद कर दिया, जिस कारण लाचारी में पर्याप्त इलाज कराये बगैर वशिष्ठ बाबू वर्ष 1997 में वापस अपने गांव बसंतपुर लौट आना पड़ा। यही पर लालू सरकार से बड़ी चूक हो गई, वरना वशिष्ठ बाबू पूर्णत: ठीक हो जाते और गणित

म नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेते। ऐसा इसलिए कि वशिष्ठ बाबू से अपेक्षाकृत कम प्रतिभा संपन्न अमेरिका के महान गणितज्ञ जॉन नैश भी इसी बिमारी से ग्रसित हो गये थे। उनका गहन इलाज कराकर अमेरिकी सरकार उन्हें सिजोफ्रेनिया की बिमारी से उबार लिया था। बाद में जॉन नैश को गणित का नोबेल पुरस्कार मिला। जबकि जॉन नैश के पीएचडी का रिर्सच वर्क वशिष्ठ नारायण सिंह के पीएचडी के रिर्सच वर्क के समक्ष कही नहीं ठहरता। यदि लालू जी समझदार होते हुए भी नासमझ न बनते तो लालू जी भी वशिष्ठ बाबू के साथ अमर हो जाते।

लालू प्रसाद के मन में वशिष्ठ बाबू की अहमियत कितनी थी, वह इस बात से भी पता चलता है कि लापता होने के बाद पहली बार जिन दो व्यक्तियों ने डोरीगंज बाजार में उन्हें पहचाना था और उनके घरवालों को सूचित कर उनसे मिलवाया था, उन दोनो व्यक्तियों को लालू जी ने सरकारी नौकरी देकर पुरस्कृत किया था। ये दोनो व्यक्ति थे-कमलेश राम और भौरिक राम। उन्होंने कमलेश राम और भौरिक राम को आरा समहरणालय में अलग-अलग पदों पर नौकरी दी। वे दोनो आज भी कार्यरत्त हैं। लालू जी ने वशिष्ठ बाबू की आर्थिक मदद भी की, क्योंकि वशिष्ठ बाबू का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था, इसलिए उनके घर को मुफलिसी से उबारने के लिए उनके भाई हरिशचंद्र नारायण सिंह, भतीजे संतोष सिंह और अशोक सिंह को भी विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी दी। हरिशचंद्र नारायण सिंह को आरा अनुमंडल में नाजीर के पद पर, संतोष सिंह को आरा समहरणालय में कर्लक के पद पर और अशोक सिंह को पटना में पुलिस के पद पर नौकरी दी।

जैसे ही वशिष्ठ बाबू के घर के आर्थिक रूप से खराब हालत के बारे में नेतरहाट ओल्ड ब्वॉयज ऐसोसिएशन (नोबा) को जानकारी मिली, तभी से यह संगठन उनके परिवार को आर्थिक मदद करता रहा। वशिष्ठ बाबू को नोबा के सदस्यों ने सबसे अधिक सहयोग किया। वर्ष 2013 से नवम्बर 2019 तक लगातार छ: वर्षों

तक प्रतिमाह 20 हजार रूपये घर का किराया देने, बिजली का बिल भरने तथा वशिष्ठ बाबू के इलाज हेतु देता रहा। यह पैसा उनके मंझले भाई अयोध्या नारायण सिंह को दिया जाता था, जो 2009 से वशिष्ठ बाबू और अपने परिवार के साथ पटना के अशोक राजपथ के किनारे स्थित कुल्हड़िया कॉप्लेक्स के तीसरी मंजिल पर अवस्थित फ्लैट नं.-302 में रहते थे। अयोध्या नारायण सिंह का परिवार ही वशिष्ठ बाबू का देखरेख और सेवा-टहल करता था।

लेकिन, बिहार के विकास के लिए सबसे अधिक काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लगातार 14 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की सूध नहीं ली, कभी भी किसी तरह की मदद उन्हें और उनके परिवार वालों को नहीं की। आश्चर्य होता है कि नीतीश बाबू जैसा तेज, कर्मठ, पुरूषार्थी और धून के पक्के मुख्यमंत्री से यह चूक कैसे हो गई? 14 नवम्बर को उन्होंने सिर्फ कुल्हड़िया कॉम्पलेक्स पहुंचकर वशिष्ठ बाबू के पार्थिव शरीर पर अपने हांथों से माल्यार्पण करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इतना जरूर है कि नीतीश बाबू के चलते वशिष्ठ बाबू को बड़हरा प्रखंड के सिन्हा ओपी क्षेत्र स्थित सोन नदी के महुली घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 15 नवम्बर को दिवंगत डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह के भतीजे मुकेश कुमार

सिंह ने उन्हें दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर मुखाग्नि दी। दिवंगत डॉ० सिंह को घाट पर बिहार पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्हें 24 रायफलों की सलामी दी गई।

समाज में गरीब कितना उपेक्षित होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण हैं डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह। पटना सायंस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ और पटना युनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब को छोड़कर आजतक पटना सायंस कॉलेज के दूसरे किसी प्राचार्य और पटना युनिवर्सिटी के किसी दूसरे कुलपति ने एक बार भी उनकी सूध नहीं ली। पटना युनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति डॉ० रासबिहारी सिंह, उनके निधन के बाद बड़ी-बड़ी डिंगे हांक रहे हैं और अनेक घोषनाएं कर रहे हैं कि डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह की याद में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर इनमें कुछ ऐसा कर सकने की क्षमता होती तो नैक की ग्रेडिंग में पटना युनिवर्सिटी को A++ के बजाय B+ और पटना कॉलेज को A++ के बजाय C ग्रेड नहीं मिलता।

बिहार के विभिन्न पार्टियों के नेताओं का तो कहना ही क्या? बड़ी-बड़ी डिंगे हांकने में इनका कोई जवाब नहीं। मसलन, रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वशिष्ठ बाबू जैसे प्रतिभा संपन्न सदियों में बिरले ही पैदा होते हैं, इसलिए भारत सरकार इन्हें पद्मश्री, भारत रत्न आदि पुरस्कारों से सम्मानित करे तथा बिहार के प्रमुख स्थलों पर इनकी आदमकद मुर्ती स्थापित करे। लेकिन इनमें से किसी भी राजनेता ने, जब वशिष्ठ बाबू जीवित थे तो गलती से भी एक बार भी याद नहीं किया।

☆ **जन्मजात टॉपर थे वशिष्ठ बाबू :-** वशिष्ठ नारायण सिंह नेतरहाट स्कूल के 1957-63 बैच के छात्र थे। उन्होंने छठी क्लास में नेतरहाट स्कूल में कदम रखा। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर क्लास में टॉप करते गये। कामयाबी की नई इबादत लिखते गये। जब 1963 में हाइयर सेकेन्ड्री की परीक्षा में उन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया तो हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल हो गया। अपनी प्रतिभा के बल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। परीक्षा की कॉपी जांचने वाले ने तब कहा था कि इन्हें कोई पढ़ा सके, ऐसा यहां कोई शिक्षक नहीं है। हाइयर सेकेन्ड्री के बाद उन्होंने पटना के सायंस कॉलेज में दाखिला लिया और उन्हे फैराडे हॉस्टल मिला। फैराडे हॉस्टल अप्रितम मेधा वाले छात्रों को मिलता था।

एक दिन ट्यूटोरियल क्लास के दौरान वशिष्ठ बाबू ने जाने-माने गणित के शिक्षक प्रो० बिकन भगत से कहा कि गणित के इस सवाल को दूसरे नियम से भी बनाया जा सकता है। उस सवाल को वशिष्ठ बाबू ने एक से अधिक तरीकों से हल कर दिया। यह बात प्रो० बिकन भकत को अच्छी नहीं लगी। ऐसी घटना बार-बार हुई तो प्रो० बिकन भगत को लगा कि वशिष्ठ उनसे अशिष्ठता कर रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ से की। कहा कि इस लड़के का रौल नं.-23 है और यह क्लास में तंग करता है। प्राचार्य डॉ० नगेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ को अपने चेंबर में तलब किया। उन्होंने वशिष्ठ से कई सवाल पूछे। वशिष्ठ ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। एक से अधिक तरीके से सवालों को हल करके बतलाया। डॉ० नगेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ से बहुत ही कठिन सवाल किया, जिसे वशिष्ठ ने मिनटों में हल कर दिया। इससे प्राचार्य नागेन्द्र नाथ गदगद हो गये। उन्होंने वशिष्ठ को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि इतना मेधावी छात्र मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है, यह लड़का बहुत बड़ा गणितज्ञ बनेगा। यहां

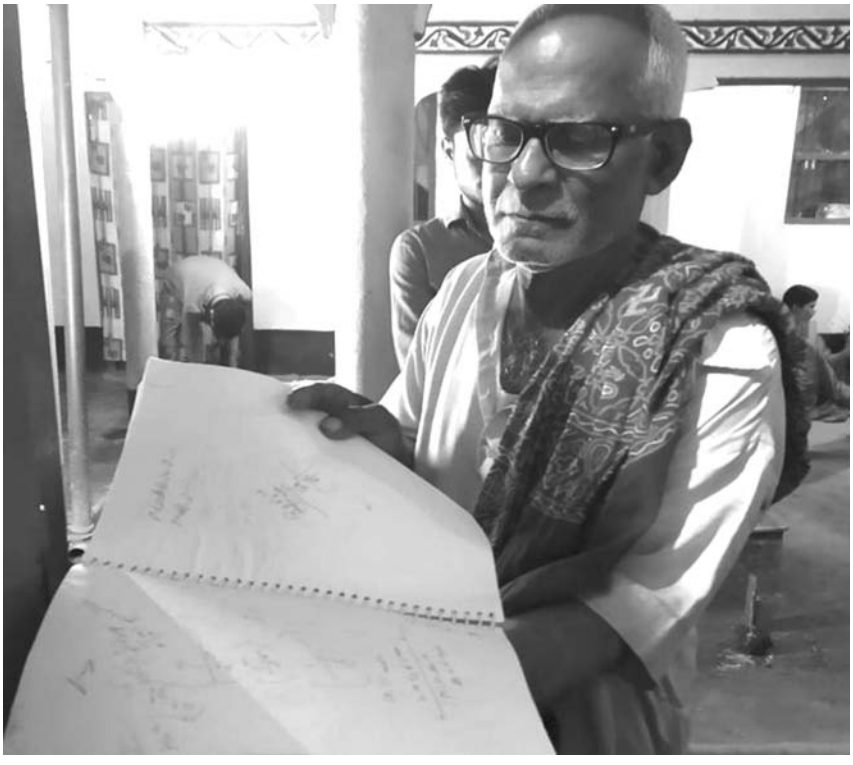

पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि डॉ० नगेन्द्र नाथ खुद पहुंचे हुए गणितज्ञ थे, बड़े वैज्ञानिक थे। वे 'नाथ-रमण इफेक्ट' थ्योरी के जनक थे। अर्थात् वे 'नाथ-रमणस इफेक्ट' के मशहूर साइंटिस्ट थे। डॉ० बिकन भगत, जिन्हें पहले लगता था कि वशिष्ठ उन्हें क्लास में हूट कर रहा है, बाद में वे वशिष्ठ के मुरीद हो गये।

सायंस कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ ने उस वक्त के पटना युनिवर्सिटी के कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब से वशिष्ठ नारायण की पूरी कहानी सुनाई और तीन साल की बीएससी ऑनर्स की डिग्री की परीक्षा में एक ही साल में शामिल किये जाने की सिफारिश की। डॉ० नागेन्द्र नाथ के मुंह से वशिष्ठ नारायण की विलक्षण प्रतिभा की बात सुनकर कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब इतने प्रभावित हो गये थे कि वे खुद अपनी गाड़ी बीआरए-8812 सायंस कॉलेज में भेजकर वशिष्ठ को युनिवर्सिटी में बुलवाया और उन्हें रिसिव करने के लिए खुद युनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद थे। वशिष्ठ बाबू को लेकर कुलपति डॉ० जॉर्ज जैकब अपने चेम्बर में ले गये। प्राचार्य डॉ० नागेन्द्र नाथ और डॉ० बिकन भगत भी वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ में गये थे। प्राचार्य, कुलपति और डॉ० बिकन भगत के बीच बातचीत के बाद तुरंत कुलपति ने वशिष्ठ नारायण को 1963-64 में बीएससी पार्ट-1 की जगह बीएससी ऑनर्स फाइनल में शामिल होने की अनुमति देने को राजी हो गये। पटना युनिवर्सिटी के सीनेट सिंडिकेट ने वशिष्ठ बाबू को बीएससी पार्ट-1 के बजाय सीधे बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में बैठने की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अर्थात् पटना विश्वविद्यालय ने वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए नियम बदले। तीन साल के बजाय एक साल में ही बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में भी वशिष्ठ बाबू न सिर्फ टॉप रहे, बल्कि नया कृतिमान यानि रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्हें कुल 600 में से 574 अंक प्राप्त हुआ।

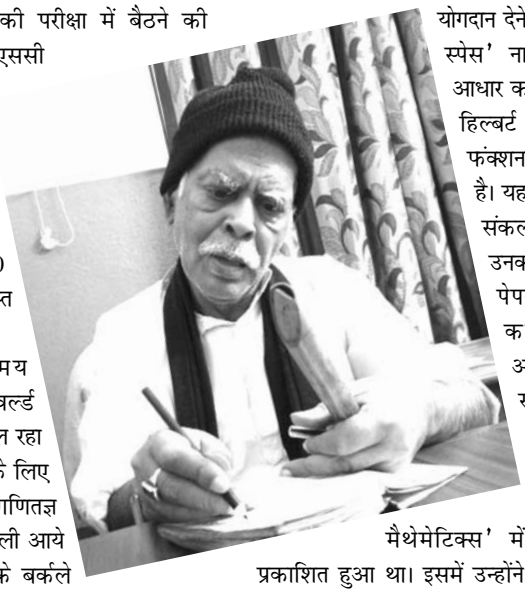

उस समय सायंस कॉलेज में वर्ल्ड मैथेमेटिक्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें भाग लेने के लिए यूरोप के जाने-माने गणितज्ञ प्रो० डॉ० जॉन एल. केली आये थे। वे कैलिफोर्निया के बर्कले युनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। डॉ० नागेन्द्र नाथ ने वशिष्ठ नारायण को डॉ० केली से मिलवाया। डॉ० नगेन्द्र नाथ ने डॉ० केली से कहा कि आप वशिष्ठ को अमेरिका ले जाइये। यह बहुत ही प्रतिभाशाली है, आपका नाम रौशन करेगा। डॉ० केली ने उन्हें गणित के कुछ सूत्र हल करने को दिये, जिसे वशिष्ठ बाबू ने मिनटो में कई प्रकार से हल कर दिये। यह देख डॉ० केली दंग रह गये। उन्होंने वशिष्ठ को तत्काल अमेरिका चलने को कहा, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे। पटना युनिवर्सिटी ने उनके लिए विशेष तौरपर परीक्षा आयोजित की। महज 22 वर्ष की उम्र में ही पी.जी. की डिग्री हासिल करने वाले वे देश के इतिहास में पहले व्यक्ति बने।

8 सितम्बर 1965 को वशिष्ठ बाबू का बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला मिला। प्रो० केली ने उन्हें दो साल बाद पीएचडी की इनरॉलमेंट परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी। लेकिन वशिष्ठ बाबू उसी साल छः महिने के बाद ही इनरॉलमेंट परीक्षा में बैठे और टॉप कर गये। डॉ० केली के मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अति कठिन व जटिल टॉपिक 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर 1969 में पीएचडी प्राप्त की। 1974 में उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ। तब गणित की दुनियां में इस शोध पत्र ने तहलका मचा दिया। वशिष्ठ बाबू की पीएचडी के विषय को आज भी अनूठा माना जाता है।

★ **वशिष्ठ बाबू की पीएचडी का विषय आज भी अनूठा और रहस्यमय माना जाता है** :- वशिष्ठ नारायण सिंह ने भौतिक विज्ञान की सबसे दुरूह शाखा क्वांटम मेकेनिक्स में योगदान देने के लिए 'हिल्बर्ट स्पेस' नाम के गणितीय आधार का इस्तेमाल किया। हिल्बर्ट स्पेस गणित में फंक्शनल मैथ की शाखा है। यह सर्वाधिक कठिन संकल्पना है। गणित में उनकी पीएचडी रिसर्च पेपर 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेर्टस विद ए साइक्लिक वेक्टर' नाम से 1974 में 'पैसिफिक जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स' में 18 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने गणितीय आधार पर विज्ञान के कुछ गुढ़ रहस्यों पर उन्होंने अपने मत दिये थे। उस समय उनकी सोच मौलिक थी। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में संकेत दिया था कि दुनियां में कुछ भी अनंत नहीं है, जिसे गणितीय

एक नजर में डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह

☞ 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में उनका जन्म हुआ था

☞ वर्ष 1957 में नेतरहाट स्कूल की छठ्ठी कक्षा में दाखिल हुए।

☞ वर्ष 1963 में हायर सेकेण्ड्री की परीक्षा में पूरे बिहार में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ।

☞ वर्ष 1963 में ही पटना के सायंस कॉलेज में बीएससी पार्ट-1 में दाखिल हुए।

☞ वर्ष 1964 में उन्होंने पटना युनिवर्सिटी की बीएससी ऑनर्स की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान नये कृतिमान के साथ स्थापित किया।

☞ 8 सितम्बर 1965 को उन्हे कैलिफोर्निया (अमेरिका) के बर्कले युनिवर्सिटी में आमंत्रण दाखिला मिला।

☞ वर्ष 1966 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में उन्हें काम करने का मौका मिला।

☞ वर्ष 1967 में कोलंबिया इंस्टीच्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स के निदेशक बने।

☞ वर्ष 1969 में 'रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एण्ड ऑपरेटर्स विद ए साइक्लिक वेक्टर' पर पीएचडी की, जो गणित की दुनियां में तहलका मचा दिया। इसलिए बर्कले युनिवर्सिटी ने उन्हें जीनियसो का जीनियस की उपाधि से अलंकृत किया।

☞ वर्ष 1969 में ही वाशिंगटन युनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर बने।

☞ वर्ष 1971 में वे भारत लौट आये।

☞ वर्ष 1972-73 में आईआईटी कानपुर में

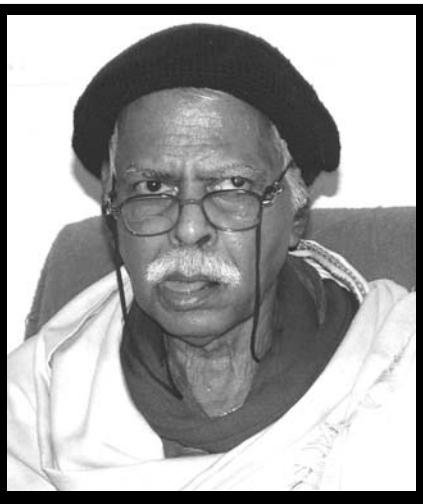

प्राध्यापक, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिर्सच (ट्रॉम्बे) तथा स्टेटिक्स इंस्टीच्यूट में अहम पदों पर आसिन रहे।

☞ 8 जुलाई 1973 में को डॉ० वंदना सिंह से शादी हुई, जो उनकी बर्बादी का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ।

☞ वर्ष 1974 में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये।

☞ वर्ष 1976 में उनके घर वालों ने उनका इलाज कराने के लिए राँची के समीप कांके स्थित कांके मेंटल हॉस्पीटल में भर्ती कराया।

☞ वर्ष 1978 में कांके मेंटल हॉस्पीटल में उनका सरकारी खर्च पर इलाज शुरू हुआ, जो 1980 में सरकारी पैसा नहीं मिलने पर बंद हो गया।

☞ वर्ष 1982 में इलाज का पैसा नहीं चुकाने के कारण एक प्राइवेट हॉस्पीटल 'डेवीड हॉस्पीटल' में बंधक बना लिए गये।

☞ इलाज हेतु आरा से मिलिट्री हॉस्पीटल ले जाने के दौरान 8 अगस्त 1989 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के गढ़वारा रेलवे स्टेशन से लापता हो गये।

☞ 9 फरवरी 1993 को छपरा के डोरीगंज बाजार में एक झोपड़ीनुमा होटल के बाहर फेंके गये भोजन तलाशते मिले।

☞ 11 फरवरी 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने के लिए उनके पैतृक गांव बसंतपुर जाकर उनके घर पर मिले।

☞ लालू प्रसाद ने 1993 से 1997 तक सरकारी खर्च पर उनका इलाज बैंगलुरू के निम्हांस हॉस्पीटल में भर्ती कराया, जिससे वशिष्ठ बाबू की मानसिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

☞ अक्टूबर 2019 के दूसरे सप्ताह में एक सप्ताह के इलाज के बाद वशिष्ठ बाबू ठीक होकर कुल्हड़िया कॉप्लेक्स स्थित अपने आवास पर लौट आये।

☞ 14 नवम्बर 2019 को पीएमसीएच में सुबह साढ़े आठ बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

संकल्पना पर समझा नहीं जा सकता है। जानकारों का मानना है कि आगामी दशक में विज्ञान की कुछ अवधारणाओं में बदलाव होने जा रहा है। इनमें वे अवधारणाएँ भी शामिल है, जिस पर उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में अपना मत दिया था। जाहीर है कि विज्ञान की अवधारणाओं में होने वाले बदलाव की नीव में विश्व के चुनिंदा गणितज्ञों में डॉ० वशिष्ठ नारायण सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में श्री डायमेंशन (लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई) से परे कुछ और आयामों की संभावना जतायी है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया है। छोटे कणों के गुण धर्म को समझने के लिए क्वांटम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में यह भी बताने का प्रयास किया है कि कणों के स्वभाव अलग-अलग क्यों होते हैं? आज से 50 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स यानि कणों की चक्रीय वृद्धि यानि कणों के वृद्धि के स्वभाव पर इतनी गहराई से सोच रखने वाले चंद वैज्ञानिकों में एक वशिष्ठ बाबू भी थे। दरअसल, क्वांटम मैकेनिक्स कणों के स्वभाव को समझने का जरीया है। वशिष्ठ बाबू का रिसर्च बहुआयामी है। उसमें ऑप्टीमाइजेशन पर भी फोकस किया गया है। उन्होंने बताया है कि असीमित को सीमित और असंख्य को बेहद कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर वशिष्ठ बाबू के सोच में गणित के उपयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है। ऐसा वशिष्ठ बाबू के रिसर्च को लेकर पटना युनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर डॉ० के.सी. सिन्हा और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉ० अमरेन्द्र नारायण का मत है।

★ **वशिष्ठ बाबू को गणित से बेहद लगाव था :-** वशिष्ठ बाबू को गणित से बेहद लगाव था। दिन हो या रात, जब मन किया कॉपी या डायरी खोलकर पेन से गणित के सूत्र लिखना शुरू कर देते थे। गणित के सूत्रों को हल करने में उलझे रहते थे। इतना ही नहीं मन किया तो अपने घर की दीवारों पर गणित का सूत्र लिख डालते। उनके ग्रामीण सत्यनारायण सिंह के अनुसार उनकी माँ प्रति दिन उनको खल्ली देती थी। जब वे गांव में घूमने निकलते थे, तो बिजली के पोल, जमीन, दीवार, कही भी गणित के सूत्र लिख देते थे। गांव के घर की दीवारों पर उनके द्वारा लिखे गणित के सूत्र आज भी विद्यमान हैं। वशिष्ठ बाबू को नोट बुक से बहुत लगाव था। वे हर साल एक नोट बुक खरीदते थे और हर दिन उस नोट बुक पर कुछ न कुछ लिखते थे। पटना के अशोक राजपथ के किनारे कुल्हड़िया कॉप्लेक्स में स्थित उनके फ्लैट में 2006 से 2019 तक के उनके द्वारा लिखित नोट बुक रखे हुए हैं। जिनमें गणित के ढ़ेर सारे सूत्रों की भरमार है। समान्यत: उनके कमरे में सिंगल बेड पर सफेद रंग की चादर बिछी होती थी, जिसपर कई जगहों पर स्याही के